राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

इंस्टाग्राम तक पहुंचा विराट और रोहित का विवाद

>>12

वर्ष 3 अंक 47

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 27 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

सहजन के पेड़ के सहारे जंग लड़ रही बड़ी आबादी

महराजगंज : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले महराजगंज जिले में सहजन के सहारे स्वास्थ्य विषयक लक्ष्य हासिल करने का प्रेरक प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र के 33 गांवों में घर-घर में सहजन के वृक्ष लहलहा रहे हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

पानी, पानीपूरी, पंचायत और पाठशाला ने कर दिया कमाल

कानपुर : उत्तर प्रदेश के जालौन का इटौरा अकबरपुर गांव ग्राम स्वावलंबन का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने है। ग्राम प्रधान की सोच और ग्रामीणों के सहयोग से विकास की राह पर रफ्तार भर रहे इस गांव का डंका देश दुनिया में बज रहा है। मिल चुके हैं अनेक पुरस्कार। (पेज-13)

अमेरिका ने रोका क्रिकेटर शमी का वीजा

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

एक्सक्लूसिव

- **बीसीसीआइ के बीच में पड़ने के बाद मिला शमी को वीजा, भारत को फ्लोरिडा में खेलने हैं दो टी-20 मुकाबले**

मुहम्मद शमी — फाइल फोटो

भारतीय क्रिकेटर मुहम्मद शमी पर चल रहे पुलिस केस उनकी मुसीबत बन गए और इस कारण अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के सीईओ राहुल जौहरी के दखल के बाद उन्हें वीजा मिल सका। वह अब अमेरिका और उसके बाद वहां से वेस्टइंडीज जा सकेंगे। शमी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे और टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में तीन टी-20, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। इसमें दो टी-20 तीन व चार अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के लॉडरहिल शहर के सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में होंगे। वहीं तीसरा टी-20 छह अगस्त और पहला वनडे आठ अगस्त को गुयाना में खेला जाना है। दूसरा वनडे 11 अगस्त और तीसरा वनडे 14 अगस्त को त्रिनिदाद एवं टोबैगो में खेला जाएगा। पहला टेस्ट 22 से 26 अगस्त तक एंटीगा तो दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से तीन सितंबर तक जमैका में आयोजित होगा।

बीसीसीआइ की तरफ से भारत के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के वीजा का आवेदन मुंबई स्थित अमेरिकिन वाणिज्यिक दूतावास में दिया गया था। मुहम्मद शमी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं हैं। वह वनडे और टेस्ट टीम के सदस्य हैं लेकिन उन्हें भी अमेरिका होते हुए ही वेस्टइंडीज जाना है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान रोहित शर्मा और कोच रवि शास्त्री के पास पहले से ही 10 साल का अमेरिका का वीजा है। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि जिन खिलाड़ियों के पास अमेरिका का वीजा नहीं था, उनके लिए हमने पी-1 वीजा कैटेगरी में आवेदन दिया था। आप अगर कोई अंतररष्ट्रीय खेल टीम के सदस्य हैं तो आपको अमेरिका के लिए शॉर्ट टर्म वीजा मिलता है। भारतीय दल की तरफ से जितने भी आवेदन दिए गए थे, उनमें शमी को छोड़कर बाकी सबको पहली बार में वीजा मिल गया। शमी के खिलाफ केस चल रहे हैं इस कारण अमेरिका ने उनका वीजा रोक दिया था। मालूम हो कि पत्नी हसीन जहां ने शमी के खिलाफ केस कर रखा है और यह मुकदमा अभी लंबित है। बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी ने इसके बाद मामले में दखल दिया और बीसीसीआइ की तरफ से अतिरिक्त कागजात अमेरिकिन वाणिज्यिक दूतावास में जमा कराए गए जिसके बाद शमी को वीजा मिल सका। हालांकि इस मसले पर जौहरी से बात नहीं हो सकी।

कारगिल के शहीदों को सलाम

कारगिल में ऑपरेशन विजय की सफलता के 20 साल पूरे होने पर शुक्रवार को द्रास स्थित वार मेमोरियल में थल सेना प्रमुख बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ और एडमिरल कर्मवीर सिंह ने शहीदों को सलामी दी। (खबर पेज-6 पर) जागरण

आजम पर लटकी निलंबन की तलवार

सख्त रुख ▶ सदन में सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो कार्रवाई निश्चित

आजम से सोमवार को स्पीकर के सामने पेश होकर माफी मांगने को कहा गया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सपा सांसद आजम खां (टीवी ग्रैब)। एएनआइ

लोकसभा में शुक्रवार को दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सदस्यों ने भाजपा सांसद रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा सांसद आजम खां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सदस्यों ने एकराय से आजम खां के बयान की निंदा करते हुए कार्रवाई का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर छोड़ दिया। स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद आजम को बचाव का एक मौका देने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक आजम को सोमवार को स्पीकर के सामने पेशकर होकर माफी मांगने की सूचना भी दे दी गई है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर निलंबन तय है। यह निलंबन इस सत्र के बचे हुए दिनों के लिए हो सकता है। हालांकि कुछ नेता सपा नेता के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के पक्ष में हैं।

लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक विधेयक पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष के आसन पर बैठीं रमा देवी ने आजम से चेयर की तरफ देखकर बोलने को कहा था। इस पर आजम ने रमा देवी की तरफ मुड़ते हुए ऐसी अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसे सुनकर सभी सदस्य स्तब्ध रह गए थे। तत्काल उस पर विरोध जताया गया और आजम से माफी मांगने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने माफी मांगने की बजाय सदन से बाहर जाना ज्यादा वाजिब समझा था। बगल में बैठे अखिलेश ने भी अपने नेता का बचाव किया था।

शुक्रवार को सदन में फिर से यह मुद्दा उठा। भाजपा की संघमित्रा मौर्या ने प्रस्ताव किया कि आजम खां सदन में आकर माफी मांगें। फिर तो भाजपा समेत कांग्रेस, राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और बीजद समेत हर दल के नेताओं ने एक-एक कर आजम को कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। बीजद के भतृहरि माहताब ने आजम के बयान को अक्षम्य बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह विषय केवल महिलाओं का नहीं है। हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। सभी दलों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए जिससे ऐसा संदेश जाए कि कोई सदस्य किसी का अपमान करके बच नहीं सकता है। ईरानी ने आजम का समर्थन करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी निंदा की।

समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान पुरुषों समेत सदन के सभी सदस्यों पर एक धब्बा है। अगर आजम खां ने यह टिप्पणी संसद के बाहर की होती तो महिला के बचाव में पुलिस आ गई होती। **–स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री**

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आजम अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आजम को सीरियल आफेंडर (बार-बार गलती करने वाला) बताया। उन्होंने कहा कि आजम सदन के बाहर भी महिलाओं का अपमान करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हैरानी है कि इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेने में 'दुविधा' और 'संकोच' क्यों है।

तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता उसे भारतीय संस्कृति का पता नहीं। अभिनेत्री से तृणमूल नेत्री बनी मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि गुरुवार को सदन में जो कुछ भी हुआ वह बहुत शर्मनाक था।

राकांपा की सुप्रिया सुले ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि आजम की अपमानजनक भाषा से उनका सिर शर्म से झुक गया। जदयू के लल्लन सिंह ने कहा कि स्पीकर को आजम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा कोई इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करे। वहीं, द्रमुक की कनीमोरी ने हैरानी जताते हुए कहा कि जब महिलाओं का संसद में अपमान हो रहा है तो सदन के बाहर उनके साथ क्या होता होगा। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आजम खां के बयान से पूरा देश शर्मसार है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि आजम खां के शब्द द्विअर्थी थे और वह इस तरह की भाषा संसद के बाहर भी बोलते रहते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान सदन में न तो आजम थे और न ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेकिन सदन के क्षोभ को देखते हुए अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि आजम खां को माफी मांगने का एक मौका दिया जाएगा। अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो अध्यक्ष जो चाहें वह कार्रवाई होगी।

...लेकिन राजनीति भी हुई पेज>>5

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

विधेयक 'जल्दबाजी' में पास कराने पर विपक्ष को ऐतराज

नई दिल्ली : राज्यसभा में भारी विरोध के बाद भी आरटीआइ विधेयक पारित होने के झटके से उबरने में जुटे विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। विपक्ष की अलग-अलग पार्टियों से जुड़े 17 सांसदों ने शुक्रवार को सरकार की 'जल्दबाजी' पर आपत्ति जताते हुए सभापति को चिट्ठी लिखी है।

आजकल ▶ पृष्ठ 14

चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान-2

बेंगलुरु : चंद्रयान-2 उपग्रह गुरुवार की रात सफलतापूर्वक चंद्रमा की तरफ और एक कदम बढ़ गया। अंतरिक्षयान पर लगे प्रणोदन प्रणाली के जरिए गुरुवार-शुक्रवार की रात एक बजकर आठ मिनट पर दूसरी बार उपग्रह की कक्षा को बदलते हुए उसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की अगली कक्षा में प्रवेश कराया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि कक्षा बदलने की यह प्रक्रिया लगभग 15 मिनट तक चली।

मानेसर जमीन घोटाले में 67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों को सस्ते में जमीन बेचने के लिए किया गया था मजबूर**
- **हुड्डा सरकार में हुए घोटाले में अब तक 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है ईडी**

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुए मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। आरोप है कि किसानों को जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर औने-पौने दाम में जमीन बेचने को मजबूर किया गया था। इस क्रम में बिल्डरों को गलत तरीके से 1500 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया था। माना जा रहा है कि गुरुवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चंडीगढ़ में ईडी ने इस मामले में भी पूछताछ की है।

ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को महामाया एक्सपोर्ट्स की 14.56 एकड़ जमीन जब्त की गई, जिसका बाजार भाव 43.54 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा अन्य आरोपी अतुल बंसल की कंपनी एबीडब्ल्यूआइएल की 23.03 करोड़ की चार एकड़ जमीन और बैंक खाते में जमा धन को जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर जमीन एबीडब्ल्यूआइएल ने खरीदी थी। इसके पहले भी ईडी इस घोटाले के आरोपियों की 42.19 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है। घोटाले में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान 27 अगस्त 2004 को मानेसर में मॉडल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई। इसके लिए 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। अधिग्रहण की जद में मानेसर के नौरंगपुर और लखनौला गांव की 688 एकड़ जमीन भी आ गई। अधिग्रहण का भय दिखाकर बिल्डरों ने किसानों की 400 एकड़ जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली। उस समय जमीन की कीमत लगभग चार करोड़ रुपये प्रति एकड़ थी। इस तरह से किसानों से 1600 करोड़ रुपये की जमीन 100 करोड़ में हथिया ली गई थी। 24 अगस्त 2007 को हरियाणा सरकार ने अचानक अधिग्रहण की अधिसूचना वापस ले ली, लेकिन तब तक जमीन पर बिल्डरों का कब्जा हो चुका था। हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। (पेज-5 भी देखें)

विमान घोटाले में दीपक तलवार गिरफ्तार, सात दिन के रिमांड पर

नई दिल्ली : विमान घोटाले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी, जिसके बाद अदालत में ही सीबीआइ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर जांच एजेंसी ने उसकी 14 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन सात दिन की ही मिली। (पेज-3)

औद्योगिक प्रदूषण में दिल्ली नंबर दो पर

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- **पांच सालों के दौरान 20 प्वाइंट बढ़ा औद्योगिक प्रदूषण**
- **महाराष्ट्र का तारापुर पहले नंबर पर, गुरुग्राम नौवें, पानीपत 11वें नंबर पर**

राष्ट्रीय राजधानी में औद्योगिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि दिल्ली का सीईपीआइ (कांप्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स) बीते पांच सालों में 20 प्वाइंट तक बढ़ गया है, जिससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रैंकिंग में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में यह देश में दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र का तारापुर पहले नंबर पर तो हरियाणा का गुरुग्राम नौवें और पानीपत ग्यारहवें स्थान पर है। दिल्ली को यह रैंकिंग नजफगढ़ ड्रेन बेसिन के आधार पर दी गई है। इनमें आनंद पर्वत, नारायणा, ओखला और वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

सीपीसीबी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 2013 और 2018 के दौरान 100 शहरों के सीईपीआइ स्कोर में काफी बदलाव आया है। नजफगढ़ बेसिन का प्रदूषण स्कोर 2013 में 73.43 प्वाइंट पर था, जो 2018 में बढ़कर 93.69 हो गया है। मालूम हो कि सीईपीआइ स्कोर में हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण का आकलन किया जाता है। 2018 में इन सब औद्योगिक क्षेत्र में हवा में प्रदूषण 72, पानी में 89 और मिट्टी में 59.25 प्वाइंट रहा है।

एनसीआर के इन जिलों में स्थिति चिंताजनक : रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम 2018 में नौवें पायदान पर रहा है। यहां का प्रदूषण स्कोर 85.15 रहा है। 2013 में यह शहर इस सूची में शामिल नहीं था। भिवाड़ी का प्रदूषण स्कोर इस दौरान 9 प्वाइंट बढ़ा है। 2013 में यह स्कोर 70.63 था, जो 2018 में बढ़कर 79.63 हो गया है। गाजियाबाद में 2013 में 68.71 था, जो अब बढ़कर 72.30 हो गया है। पानीपत का स्कोर 83.54 है और यह 11वें पायदान पर है।

फरीदाबाद व नोएडा में हुआ सुधार: दूसरी तरफ इन पांच सालों में फरीदाबाद में काफी सुधार देखने को मिला है। फरीदाबाद का प्रदूषण स्कोर 11.38 प्वाइंट सुधरा है। 2013 में यहां का प्रदूषण स्कोर 73.55 था, जो 2018 में 62.17 रह गया है। इसी तरह नोएडा के प्रदूषण स्कोर में भी 9.93 प्वाइंट का सुधार हुआ है। 2013 में यहां का स्कोर 78.69 था जो अब कम होकर 68.76 रह गया है।

यह हैं सीईपीआइ के मानक : सीपीसीबी के अनुसार जहां सीईपीआइ स्कोर 70 प्वाइंट या इससे अधिक है, उन्हें क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया, जहां 60 से 70 फीसद तक है, उन्हें गंभीर प्रदूषित क्षेत्र और जहां स्कोर 60 से नीचे है उन्हें अन्य प्रदूषित क्षेत्रों में रखा गया है। इसी रिपोर्ट के आलोक में एनजीटी ने हाल ही में आदेश दिए हैं कि क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया और गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को बसाने और पुरानी इकाइयों के विस्तार को मंजूरी न दी जाए। साथ ही इन क्षेत्रों में जो औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द बंद किया जाए।

अब सीबीआइ ने तृणमूल सांसद डेरेक ओ 'ब्रायन को किया तलब

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले की जांच में जुटी सीबीआइ ने अब तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्राइन को तलब किया है। उन्हें अगस्त के प्रथम सप्ताह में पूछताछ के लिए सीजीओ कांप्लेक्स में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार दुर्गापूजा से पहले ही सीबीआइ सारधा कांड की चार्जशीट सौंपने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से सत्ताधारी नेताओं और पुलिस अफसरों से पूछताछ में तेजी लानी शुरू कर दी है। सीबीआइ ने इससे पहले भी पूछताछ के लिए डेरेक को तलब किया था, लेकिन संसद चलने की वजह से उन्होंने हाजिर होने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद एक बार फिर शुक्रवार को सीबीआइ ने तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को नोटिस भेजकर तलब किया है। तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी व तमोनाश घोष को भी नोटिस भेजा गया है। इन सभी से सारधा के साथ आर्थिक लेनदेन हुआ था कि नहीं आदि सवालों के जवाब लिए जाएंगे।

येदियुरप्पा चौथी बार बने कर्नाटक के सीएम

- **बहुमत साबित करने के लिए मिला 31 जुलाई तक समय**

बेंगलुरु, एजेंसियां : कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा (76) ने शुक्रवार को राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। वह चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल ने उन्हें 31 जुलाई तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 माह पुरानी जदएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार विधानसभा में विश्वास मत हार गई थी।

जदएस-कांग्रेस के बागी विधायकों के भविष्य पर अनिश्चितता के चलते गुरुवार शाम तक भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करने से बच रही थी, लेकिन गुरुवार रात स्पीकर रमेश कुमार ने दो बागी कांग्रेस विधायकों और एक निर्दलीय को अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह भाजपा ने अचानक सरकार बनाने का फैसला किया। येदियुरप्पा के मुताबिक, उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से शुक्रवार को ही शपथ दिलाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने येदियुरप्पा को अकेले ही शपथ दिलाई, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बहुमत साबित करने के बाद शपथ दिलाई जाएगी। जदएस और कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, यहां तक कि कुमारस्वामी भी समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में अन्य गणमान्य लोगों के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा, भाजपा महासचिव वी. मुरलीधर राव आदि शामिल थे।

बता दें कि येदियुरप्पा ने पहली बार 2007 में राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, लेकिन जदएस के समर्थन वापस लेने से सिर्फ सात दिन ही पद पर रहे थे। इसके बाद वह मई 2008 से जुलाई 2011 तक मुख्यमंत्री रहे, तब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद भी उन्होंने सीएम पद संभाला था, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण तीन दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था।

कर्नाटक में हफ्तों चले सियासी 'नाटक' के बाद बीएस येदियुरप्पा ने सीएम की कुर्सी पा ही ली। बेंगलुरु में शुक्रवार को राज्यपाल वेजुभाई वाला (दाएं) ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। प्रेट्र

बीएस येदियुरप्पा को बधाई। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा राज्य में स्थिर, किसान हितैषी और विकासोन्मुखी सरकार देगी। **– अमित शाह**, भाजपा अध्यक्ष

कुमारस्वामी के आदेशों पर लगाई रोक पेज>>3

चिट्ठी वार

उन्मादी भीड़ की हिंसा पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाली 49 हस्तियों को दी नसीहत, उनके पत्र की भावना को बताया चुनिंदा आक्रोश और झूठी धारणा, कहा, उनका स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा है और वे राजनीति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं

61 हस्तियों का पलटवार-देश को बदनाम न करें बुद्धिजीवी

मुंबई, प्रेट्र : उन्मादी भीड़ की हिंसा के खिलाफ तीन दिन पहले कुछ बुद्धिजीवियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के जवाब में शुक्रवार को 61 जानी-मानी हस्तियों ने भी पत्र लिखा और दुष्प्रचार करने वालों पर जमकर हमला बोला। बता दें कि 23 जुलाई को 49 बुद्धिजीवियों ने मोदी सरकार में हो रही उन्मादी हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था।

61 जानी-मानी हस्तियों ने भी एक खुले पत्र में उन्मादी हिंसा पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाली हस्तियों को देश का 'स्वयंभू गार्जियन' करार देते उनको जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि उन लोगों का स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा है और वे राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उन लोगों का राजनीति झुकाव स्पष्ट है। उनका उद्देश्य दुनिया में भारत की छवि खराब करना है। उन्होंने झूठे आरोप लगाए और देश व लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की है। उनका इस तरह पत्र लिखकर विरोध जताना अंतराराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि, प्रधानमंत्री के कामकाज के प्रभावशाली तरीके, राष्ट्रीयता और मानवता के खिलाफ है, जो भारतीयता के मूल्यों में निहित है।

विभिन्न क्षेत्रों की इन हस्तियों ने लिखा खुला पत्र

सोनल मानसिंह

मालिनी अवस्थी

प्रसून जोशी (सभी फाइल फोटो)

इस पत्र को लिखने वाली 61 प्रमुख हस्तियों में क्लासिकल डांसर और सांसद सोनल मानसिंह, वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट, विश्वभारती शांतिनिकेतन के देवाशीष भट्टाचार्य, अवध विश्वविद्यालय के उपकुलपति मनोज दीक्षित, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अनिर्बन गांगुली, शिक्षाविद राधारमन चक्रवर्ती, फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, विवेक अग्निहोत्री, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट, गीतकार प्रसून जोशी, पत्रकार स्वपनदास गुप्ता, अभिनेता विश्वजीत चटर्जी, अभिनेत्री पल्लवी जोशी, गायिका मालिनी अवस्थी तथा फिल्म निर्माता सौकत मुखर्जी शामिल हैं।

पत्र में कहा गया है कि जब आदिवासी और गरीबों को नक्सली निशाना बनाते हैं, कश्मीर में अलगाववादी स्कूल बंद करवाते हैं, अलगाववादी विश्वविद्यालयों में देश के टुकड़े-टुकड़े के नारे लगाते हैं तो तब ये बुद्धिजीवी चुप क्यों रहते हैं। कैराना में हिंदुओं के पलायन पर वे कुछ नहीं बोलते।

उन्होंने पीएम को लिखे पत्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, उनका एजेंडा साफ है। वे भारत को तोड़ने वालों के हाथों में खेल रहे हैं। संविधान ने हमें असहमति जताने का हक दिया है, देश के टुकड़े करने वालों का साथ देने का नहीं। बुद्धिजीवियों का यह समूह महिलाओं को समानता का हक दिलाने और तीन तलाक को खत्म करने के मुद्दे पर आगे क्यों नहीं आता। 61 हस्तियों ने कहा, ऐसा लगता है कि उनके लिए देश की एकता व अखंडता का कोई मतलब नहीं है। वैचारिक रूप से वे अलगाववादियों के समर्थक हैं। उनके अंदर विरोध की भावना है जबकि मोदी सरकार 'सबका साथ सबका विकास' के नारे के साथ चल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उन्मादी भीड़ की हिंसा की घटनाओं की कई बार आलोचना कर चुके हैं।

पहले 49 हस्तियों ने क्या लिखा था : इससे पहले देश के अलग-अलग क्षेत्रों के 49 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखकर यह अपील की थी कि मुस्लिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन्मादी भीड़ की हिंसा तत्काल प्रभाव से रुकनी चाहिए। इस पत्र को लिखनेवालों में फिल्म निर्माता अडूर गोपाल कृष्णन, अपर्णा सेन, गायिका शुभा मुद्गल, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, अभिनेता सौमित्र चटर्जी, अभिनेत्री रेवती, सामाजिक कार्यकर्ता विनायक सेन, समाजशास्त्री आशीष नंदी, अभिनेत्री कोंकणा सेन, फिल्मकार श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप और मणिरत्नम शामिल थे।

मॉब लिंचिंग पर केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **याचिका में मॉब लिंचिंग रोकने के कोर्ट के आदेश का पालन कराने और राज्यों से स्थिति रिपोर्ट लेने की अपील**

सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ के पीट-पीट कर मार डालने (मॉब लिंचिंग) की बढ़ती घटनाओं को रोकने और कोर्ट के गत वर्ष के मॉब लिंचिंग रोकने के आदेश को कड़ाई से लागू करने की अपील पर केंद्र सरकार, मानवाधिकार आयोग और 11 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई व दीपक गुप्ता की पीठ ने ये नोटिस गैर सरकारी संगठन एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। कोर्ट ने जिन राज्यों को नोटिस जारी किया है उनके नाम उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश और दिल्ली हैं। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने पिछले वर्ष तहसीन पूनावाला के मामले में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए विस्तृत आदेश दिए थे। इसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

याचिका में मांग की गई है कि राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वह मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दें। साथ ही यह भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू करने के लिए क्या किया गया। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट संसद से कहे कि वह मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए। पिछले वर्ष 17 जुलाई को कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए राज्यों को तत्काल सख्त कदम उठाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए क्रमवार दिशा-निर्देश जारी किए थे।

29 अगस्त को होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव के पदों के लिए कौन-कौन मैदान में उतरेगा, इसकी अंतिम सूची 23 अगस्त को जारी की जाएगी। 21 और 22 अगस्त को नामांकन भरे जाएंगे।

व्यवस्था ▸ लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए उठाया कदम

22 नई व्यावसायिक अदालतें बनाने को मिली मंजूरी

केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की अदालतों में लंबित मामलों को समाप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 18 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थायी करने और 22 नई व्यावसायिक अदालतें बनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कानून विभाग की ओर से कैबिनेट में पेश किए गए इस प्रस्ताव के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं के तहत व्यावसायिक जज के रूप में 22 जजों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा इन अदालतों में अधीनस्थ स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी। जज एवं स्टाफ की कुल संख्या 212 होगी। इन अदालतों के निर्माण एवं स्टाफ के वेतन आदि पर लगभग 13 करोड़ 55 लाख 90 हजार का सालाना खर्च आएगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने 18 अस्थायी फास्ट ट्रैक अदालतों को स्थायी करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अनुसार, दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं के तहत 18 अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए स्वीकृत 90 प्रतिशत अनुबंधित पदों को स्थायी पोस्ट में बदलने के निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके साथ यहां 86 अधीनस्थ स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इन सभी पर लगभग आठ करोड़ 88 लाख 45 हजार की धनराशि सालाना खर्च की जाएगी।

कई वर्षों से लंबित था मामला : 11वें वित्त आयोग ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न राज्यों में 1,734 अदालतों की स्थापना के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत 502 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालांकि वित्त आयोग ने दिल्ली में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के किसी भी प्रस्ताव को इसमें शामिल नहीं किया था। दिल्ली सरकार ने इस मामले को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के सामने उठाया। इसके बाद मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2003-04 में दिल्ली सरकार को गैर-नियोजित अनुदान के रूप में पांच वर्षों की अवधि के लिए 20 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए धनराशि जारी की। 11वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2005 में समाप्त हो गया।

इसके बाद 12वें वित्त आयोग ने दिल्ली में फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की। 2005 में अस्थायी आधार पर बनाए गए 20 जजों और 95 सहायक कर्मचारियों के पद की नियुक्ति का मामला साल-दर-साल आगे बढ़ता रहा। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था। जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि अस्थायी अदालतों को स्थायी किया जाए।

जलभराव से निपटने को कमांडो की तरह करें काम : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मानसून के दौरान राजधानी में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्स दिए। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि लीक से हटकर सोचिए और जलभराव से निपटने के लिए कमांडो की तरह काम करिए। पीठ ने कहा कि आगामी 20 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग समेत अन्य एजेंसियों को शहर में जलभराव रोकने के लिए पूरी ताकत लगाना सुनिश्चित करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि मानसून के दौरान जल जमाव व वाहनों के रेंगने की समस्या आम है। इससे फुटपाथ पर चलने वाले लोगों और खासतौर पर बच्चों को परेशानी होती है। कभी-कभी वे खुले ड्रेन में गिर जाते हैं, जिसके उनकी मौत तक हो जाती है। पीठ ने कहा कि इन सभी पहलुओं को देखते हुए पहले से ही पंप की व्यवस्था कर लें और जलभराव की सूचना मिलने पर पानी को निकाला जाए। पीठ ने कहा कि आइटीओ समेत उन चिह्नित इलाकों पर विशेष तैयारी पहले से कर ली जाए, जहां बारिश से समस्या अधिक है।

दिल्ली सरकार की तरफ से अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ को बताया कि मानसून को देखते हुए पहले ही नालों की गंदगी साफ कर दी गई है।

आम्रपाली के 10 हजार खरीदारों को तुरंत मिलेगा मालिकाना हक

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर

कुंदन तिवारी, नोएडा

आम्रपाली समूह पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसने के बाद इस समूह में निवेश करने वाले 42 हजार निवेशकों में से दस हजार फ्लैट खरीदारों को सबसे पहले मालिकाना हक मिलने जा रहा है। नोएडा में आम्रपाली समूह की नौ परियोजनाएं पूरी तो हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाने की वजह से बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। ऐसे में हजारों फ्लैट खरीदार बिना रजिस्ट्री के ही अपने घरों में रह रहे हैं। अब इनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि, अभी 32 हजार निवेशकों को करीब तीन माह इंतजार करना होगा। क्योंकि, कोर्ट के आदेश पर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पर तीन माह बाद ही काम शुरू कर सकती है।

आम्रपाली पर प्राधिकरण का करीब 2200 करोड़ रुपये का बकाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा होने के कारण अब प्राधिकरण भी किसी तरह की कागजी अड़चन नहीं लगा सकेगा। रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होने से सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होना तय है। ग्रेटर नोएडा में 400-500 ऐसे लोग है, जिन्हें विला का पजेशन मिल चुका है, लेकिन मालिकाना हक अभी मिलना बाकी है। सोमवार से प्राधिकरण कार्यालय पर कोर्ट का आदेश पत्र लेकर पहुंचने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय पर भी हलचल तेज होगी। वहीं एआइजी स्टांप शिव कुमार त्रिपाठी का कहना है कि अब निबंधन कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोशिश रहेगी कि बिना व्यवधान के सबकी रजिस्ट्री हो जाए।

शाहबेरी में अवैध बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डरों की तलाश शुरू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : शाहबेरी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद पुलिस-प्रशासन अवैध बिल्डरों व प्रापर्टी डीलरों को चिह्नित करने की तैयारी शुरू कर दी है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 250 से अधिक बिल्डर व प्रापर्टी डीलरों को चिह्नित किया है। इसमें तीस मुख्य आरोपित हैं। एक मुख्य आरोपित 25 हजार के इनामी शहाबुद्दीन को पुलिस ने एक दिन पूर्व ही गिरफ्तार किया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। सभी मुख्य आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की कार्रवाई होगी। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष 17 जुलाई को शाहबेरी में दो अवैध इमारत जमींदोज हो गई थी। जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने शाहबेरी में अवैध बिल्डिंग बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।

एसपी देहात रणविजय सिंह ने बताया कि शाहबेरी में किसी भी प्रकार के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस समय-समय पर क्षेत्र में गशत कर रही है। शाहबेरी में अवैध बिल्डिंग बनाने वालों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया शहर में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण से मुलाकात की गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को सही कराने, विभिन्न स्थानों पर जांच के लिए बैरियर व अन्य चीजों की मांग की गई है। जल्द ही शहर में उन स्थानों का चयन किया जाएगा जो शहर के मुख्य प्वाइंट हैं। जिसके बाद प्राधिकरण की मदद से वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

सफदरजंग अस्पताल में आज से शुरू होंगी चार सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सफदरजंग अस्पताल में शनिवार को बुजुर्ग मरीजों के लिए जेरियाट्रिक क्लीनिक सहित चार सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें अत्याधुनिक कैथ लैब, लिथोट्रिप्सी मशीन व नई एमआरआइ मशीन शामिल हैं। इन चार सुविधाओं के शुरू होने से अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज व जांच की सुविधाएं मिल पाएंगी। खासतौर पर किडनी में स्टोन से पीड़ित मरीजों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेजर का इस्तेमाल कर स्टोन निकाला जा सकेगा। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक रविवार को बुजुर्गों के लिए जेरियाट्रिक क्लीनिक चलेगा। सुबह साढ़े नौ से दोपहर 12:30 बजे तक ओपीडी होगी। इस दौरान मेडिसिन, ईएनटी, जनरल सर्जरी, नेत्र व ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए मौजूद रहेंगे। बुजुर्गावस्था में हड्डियों की चोट व आंखों से संबंधित परेशानियां ज्यादा होती हैं। इसलिए इस क्लीनिक के शुरू होने से बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टरों के परामर्श के बाद इमरजेंसी ब्लॉक में बुजुर्ग अपनी जांच करा सकेंगे। साथ ही उन्हें अस्पताल से दवाएं भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सफदरजंग अस्पताल में पहले से दो कैथ लैब कार्यरत हैं। सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में एक नए कैथ लैब की शुरुआत की जाएगी। इस तरह अस्पताल में तीन कैथ लैब की सुविधा हो जाएगी। बताया जा रहा है कि यह हाईब्रिड कैथ लैब है, जो बेहद अत्याधुनिक है। इससे हार्ट अटैक व दिल की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को फायदा होगा। इस लैब में मरीजों की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होगी। हाईब्रिड कैथ लैब का फायदा यह होता है कि यदि मरीज की जांच के दौरान ही हालत बिगड़ जाए या जल्द बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़े तो वहीं लैब में ही तुरंत सर्जरी की जा सकती है। इस तरह की सुविधा कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध है।

किडनी में स्टोन की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर अस्पताल में लिथोट्रिप्सी मशीन लगाई गई है। इसका फायदा यह होगा कि स्टोन निकालने के लिए मरीजों को चीरा लगाकर सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दिल्ली की स्वच्छता पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : शहर में सफाई व्यवस्था व कचरा मुक्त नालों की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नगर निगमों से पूछा कि आखिर अब तक दिल्ली क्यों स्वच्छ नहीं हुई है। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने तीनों नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे शपथ पत्र दाखिल करें जिसमें यह बताएं कि शहर को साफ रखने के लिए क्या कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताएं कि नगर निगम के हर जोन में कितने सफाईकर्मी, सुपरवाइजर और वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनकी क्या भूमिका है।

पीठ ने यह निर्देश स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल बीबी शरण द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया। इससे पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य नागरिक निकायों को भी अपने नियंत्रण क्षेत्रों के संबंध में आदेश जारी किया था। पीठ ने इस दौरान नगर निगमों से यह भी पूछा कि उनके सफाई कर्मचारी और सुपरवाइज अपने कर्तव्यों को क्यों नहीं निभा रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी क्या निगरानी कर रहे हैं कि कचरा साफ किया जा रहा है या नहीं। पीठ ने पूछा कि क्या जोन के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्राधिकार के तहत सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं।

नवी मुंबई से 130 किलो हेरोइन बरामद, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अफगानिस्तान-ईरान से की जा रही हेरोइन की तस्करी की कड़ियां जोड़ते हुई दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को दिल्ली से दो और हेराइन तस्करों को दबोच लिया। इनमें से एक अहमद शाह आलोकोजई अफगानिस्तान का है, जबकि दूसरे की पहचान दिल्ली के तिफल नाउ खेज के रूप में हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने उनकी निशानदेही पर ईरान से समुद्र के रास्ते लाई गई 130 किलो हेरोइन की बड़ी खेप भी नवी मुंबई से बरामद कर ली।

गत एक हफ्ते में स्पेशल सेल हेरोइन की तस्करी के तीन मामलों में कुल पांच अफगानी सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही उनसे अब तक 330 किलो हेरोइन बरामद की जा चुकी है। यह हेरोइन अफगान से अलग-अलग रास्ते से भारत में लाई गई थी। गिरफ्तार तिफल नाउ दिल्ली में अफगानी गिरोह का मुखिया है। उसने अफगानी आका हाजी के निर्देश पर जाकिर नगर इलाके में हेरोइन की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई थी। उसी ने ये खेप अफगान से ईरान और बाद में समुद्र के रास्ते मुंबई बंदरगाह पर मंगाई थी।

स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि हेरोइन की बड़ी खेप नवी मुंबई में है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने नवी मुंबई स्थित कस्टम वेयर हाउस में रखे 260 हेरोइन सोखे हुए जूट के बोरे बरामद कर लिए। यह हेरोइन ईरान के बंदरगाह अब्बास से पानी के जहाज द्वारा मुंबई लाई गई थी। एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उन बोरों में तुलसी के बीज भरे थे। विशेष तौर पर बनाए गए बोरों को कई परतों में बांटा गया था। हेरोइन सोखे बोरों के ऊपर और नीचे सफेद रंग की पॉलिथीन की परतें चढ़ाई हुई थीं, ताकि हेरोइन सुरक्षित रहे। प्रत्येक बोरे में करीब 500 ग्राम हेरोइन थी।

गत शुक्रवार को भी दिल्ली से हेरोइन की तस्करी में दो अफगानी नागरिक सहित पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 150 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। गिरफ्तार तस्करों से बाद वाघा-अटारी बॉर्डर से आने वाले ड्राइ फ्रूट सहित अन्य सामानों के बीच में छिपा कर हेरोइन लाने वाले गिरोह की जानकारी मिली थी। जिसके बाद सोमवार की रात पुलिस ने हरियाणा के कुंडली में छापा मारकर वहां से किशमिश के 102 डिब्बों में 204 पॉलीपैक के बीच छिपाकर रखी 50 किलो हेरोइन के पैकेट बरामद किए थे। साथ ही अफगानी तस्कर मुहम्मद अकबर और नेडा मुहम्मद को गिरफ्तार किया था।

तस्करों से बरामद हेरोइन। एक हफ्ते में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 330 किलो हेरोइन बरामद कर चुकी है। फोटो : सौजन्य पाठक

श्रीलंका तक होती थी सप्लाई : स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आरोपितों ने जाकिर नगर स्थित एक मकान में हेरोइन की प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी थी। तस्कर अफगानिस्तान से हेरोइन सोखे हुए मसाले के बोरे में हेरोइन भारत में मंगाते थे। बाद में उसे परिष्कृत कर उसकी तस्करी दिल्ली-एनसीआर व पंजाब के अलावा श्रीलंका में की जाती थी।

ड्रग्स तस्करी में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है तिफल नाउ खेज : तिफल नाउ खेज 10 वर्ष की उम्र में ही मैकेनिक काम काम करने लगा था। बाद में उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया था। इससे पहले वर्ष 2013 में उसे पंजाब पुलिस द्वारा ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार किया जा चुका है। अमृतसर जेल से छूटने के बाद शेख नाम के अफगानी तस्कर के संपर्क में आकर वह हेरोइन की तस्करी में लिप्त हो गया था। बाद में उसका संपर्क हाजी से हुआ।

ड्राई फ्रूट का थोक कारोबारी है अहमद शाह : पुलिस की गिरफ्त में आया दूसरा तस्कर अहमद शाह आलोकोजई गत कई वर्ष से दिल्ली में रह रहा है और उसकी पहचान एक बड़े ड्राई फ्रूट के थोक कारोबारी के तौर पर है। अफगानी ड्रग्स तस्कर हाजी के निर्देश पर वह कंपनी बनाकर अपने भारतीय संपर्कों के माध्यम से अफगानिस्तान से दिल्ली में ड्राई फ्रूट मंगाता था। इन्हीं ड्राई फ्रूट के बोरों में हेरोइन छिपी होती थी।

राहुल पहुंचे शीला दीक्षित के घर, दी श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे निजामुद्दीन स्थित उनके आवास पर पहुंचे राहुल ने पहले उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और फिर उनके कमरे में बैठ गए। पहले 20 मिनट तक राहुल गांधी और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लेकिन दोनों की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। इसके बाद संदीप की चुप्पी टूटी तो उन्होंने कहा, जिस कुर्सी पर अम्मा (शीला दीक्षित) की फोटो रखी है, इसी पर वह हमेशा बैठती थीं, और फिर संदीप की आंखें नम हो गईं।

इसके बाद राहुल गांधी ने वहां करीब तीन घंटे का समय बिताया। इस दौरान उनके साथ संदीप दीक्षित के अलावा उनकी पत्नी मोना, बहन लतिका और रमा धवन भी मौजूद थीं। इस दौरान इन सभी ने शीला से जुड़े संस्मरण याद किए। इस बीच राहुल गांधी ने शीला दीक्षित का घर देखने के साथ यह संदेश भी दिया कि गांधी परिवार के लिए दीक्षित परिवार की क्या अहमियत है। हालांकि, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित की नजदीकियों की चर्चा हमेशा होती रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस मुलाकात में कुछ लोगों के लिए राजनीतिक संदेश भी छिपा है कि पार्टी में जिस तरीके का व्यवहार शीला दीक्षित के साथ आखिरी दिनों में किया गया, वह उनके लिए चिंता का विषय है।

निजामुद्दीन स्थित शीला दीक्षित के निवास पर श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी। फोटो सौजन्य-कांग्रेस

मैं प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं : संदीप दीक्षित

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संदीप दीक्षित ने चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट कहा कि वह प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि, इस मामले में न मेरा कोई हस्तक्षेप है और न मैं इस लड़ाई में हूं। अध्यक्ष जो भी बने, ऐसा व्यक्ति बने जो सभी को साथ लेकर चले और भविष्य की दिल्ली के बारे में भी सोचे।

पीसी चाको और अजय माकन को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, मेरी इन दोनों के ही साथ कोई खास निकटता नहीं है। मेरा मानना है कि आखिरी दिनों में शीला जी के साथ जो पत्राचार हुआ, उससे वह बहुत निराश थीं। उनका कहना था कि पत्र वगैरह लिखने के बजाय शिकायत को आपस में बात करके दूर करना चाहिए था। निधन से पूर्व शीला द्वारा सोनिया गांधी को लिखे गए विवादित खत के बारे में दीक्षित ने अनभिज्ञता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी से बात कर उन्हें सांत्वना मिली है और बहुत सी नई बातें भी पता चलीं। जल्द ही वह शीला जी के बारे में भी कुछ लिखेंगे।

सीएनजी व पेट्रोल वाहनों को नौ साल की एनओसी देने की सिफारिश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने सीएनजी व पेट्रोल वाहनों को पांच के बजाय नौ साल के लिए एनओसी देने की सिफारिश की है। ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सीएनजी स्वच्छ ईंधन है और इसी वजह से डीजल की तुलना में इसे अधिक समय तक चलाने की छूट दी जा सकती है। परिवहन विभाग ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के वाहनों को पांच साल की एनओसी देता है। इसके बाद नवीनीकरण नहीं किया जाता। यह नियम डीजल, सीएनजी और पेट्रोल तीनों तरह के वाहनों पर लागू होता है। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद से ही ऐसा हो रहा है। टैक्सी चालकों की मानें तो इसके कारण ही सीएनजी टैक्सियां घाटे का सौदा बन रही हैं। पांच साल बाद उन्हें सीएनजी टैक्सियों को काफी कम दामों में बेचना पड़ता है।

ईपीसीए के अनुसार पिछले कुछ सालों से टैक्सी ऑपरेटर इस मुद्दे को उठा रहे थे। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में उक्त रिपोर्ट दी गई है। और कहा गया है कि स्वच्छ ईंधन होने की वजह से सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ियों को नौ साल के लिए परमिट दिया जाए। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट की याचिका पर 10 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली डीजल टैक्सी के पांच साल पुराने परमिट के नवीनीकरण पर रोक लगाई थी।

जीडीए के मकानों की कीमत 30 फीसद तक होगी कम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- जीडीए अधिकारी प्रशासनिक शुल्क और पर्यवेक्षण शुल्क खत्म करने पर कर रहे मंथन
- ऊपरी तलों पर बनी कोने की दुकानों पर कॉर्नर चार्ज न लगाने का प्रस्ताव हो रहा तैयार

जीडीए से मकान, दुकान और प्लॉट खरीदना करीब 30 फीसद तक सस्ता होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में सुस्ती के चलते जीडीए अधिकारी इस दिशा में मंथन कर रहे हैं। इसके लिए संपत्ति पर लगने वाले प्रशासनिक और पर्यवेक्षण शुल्क को खत्म किया जा सकता है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में भूतल से ऊपर बनी कोने की दुकानों से कॉर्नर चार्ज खत्म करने की तैयारी है। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।

जीडीए फ्लैट और दुकान की कीमत भूमि की दर, निर्माण की लागत और विकास शुल्क जोड़ कर तय करता है। भूखंड की कीमत भूमि की दर और विकास शुल्क जोड़ कर तय की जाती है। इन्हें बेचते वक्त 15 फीसद प्रशासनिक शुल्क और 15 फीसद पर्यवेक्षण शुल्क लगाया जाता है। कोने की दुकानों पर 10 फीसद कॉर्नर चार्ज लिया जाता है। ऐसे में संपत्ति 30 से 40 फीसद महंगी हो जाती है। पिछले छह सालों से रियल एस्टेट सेक्टर सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। जीडीए रेट फ्रीज करके नीलामी और योजना निकालने के बावजूद संपत्तियां बेच कर खजाना भरने के लिए धनराशि नहीं जुटा पा रहा। इस संकट को देखते हुए जीडीए अधिकारियों को संपत्ति की कीमतें घटाने पर मंथन करना पड़ रहा है। विचार विमर्श किया जा रहा है कि प्रशासनिक और पर्यवेक्षण शुल्क को खत्म कर दिया जाए। यह भी सोचा जा रहा है कि ऐसा करना संभव न हुआ तो दोनों शुल्कों को घटाकर एक-दो फीसद कर दिया जाए। भूतल की दुकानों पर कॉर्नर चार्ज लिया जाएगा। लेकिन, उससे ऊपर के तलों पर कोने की दुकानों की कीमत से कॉर्नर चार्ज खत्म करने पर मंथन किया जा रहा है। इंदिरापुरम में 30 और आरडीसी में 30 ऐसी दुकानें हैं, जो ऊतरी तल पर कोने पर बनी हैं। उनके दाम कम हो जाएंगे। आवासीय योजनाओं पर थोपी गई अतिरिक्त लागत की समीक्षा की जाएगी। संशोधन की संभावना हुई तो उसे भी घटाया जाएगा।

> संपत्ति से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण शुल्क हटाने पर विचार किया जा रहा है। भूतल से ऊपर कोने की दुकानों पर कॉर्नर चार्ज नहीं लगाने पर मंथन किया जा रहा है। इससे औसतन संपत्ति के दामों में 30 फीसद की कमी आने की उम्मीद है। इंदिरापुरम, वैशाली और कौशांबी योजना में संपत्तियों की कीमत फिर से फ्रीज करने के बारे में सोचा जा रहा है। जिला प्रशासन से गुजारिश की जाएगी कि वह भी नोएडा की तर्ज पर सर्किल रेट घटाएं। रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल के लिए इस तरह के उपाय करने होंगे।
>
> **-कंचन वर्मा, वीसी, जीडीए**

6500 संपत्तियां होंगी सस्ती : इंदिरापुरम, वैशाली, मधुबन-बापूधाम, कौशांबी, कोयल एंक्लेव, इंद्रप्रस्थ योजना, गोविंदपुरम, स्वर्णजयंतीपुरम, चंद्रशिला अपार्टमेंट, शास्त्रीनगर समेत कई स्थानों पर जीडीए की करीब 6500 संपत्तियां बिक्री के लिए पड़ी हैं। इनको खरीदारों की तलाश है। इस वक्त काफी प्रयास के बाद लोग संपत्ति खरीदने को तैयार नहीं है। इन्हीं को बेचने के बाद जीडीए धनराशि जुटाकर विकास योजनाओं को पर काम कर सकता है।

इंदिरापुरम, वैशाली और कौशांबी योजना में संपत्तियों के रेट फ्रीज किए जाएंगे। जीडीए में इसका प्रस्ताव बनना शुरू हो गया है। वर्ष 2012 में भी ऐसा किया गया था। जिसे वर्ष 2017 में हटा लिया गया था। हालांकि, इन तीनों योजनाओं को छोड़ कर अन्य सभी योजनाओं के रेट पहले से फ्रीज चल रहे हैं।

जीडीए की एक कॉमर्शियल योजना में 24 दुकानों की कीमत आधी हो जाएगी। यहां 11 साल पहले दोगुने सर्किल रेट पर दुकानों की कीमत तय कर दी गई थी। गलती से ऐसा हुआ था। उसका खामियाजा जीडीए को भुगताना पड़ा। बाजार मूल्य से अधिक कीमत होने के कारण एक भी दुकान नहीं बिकी। सूत्रों की मानें तो चिकंबरपुरम यूपी बॉर्डर पर बनी दुकानों की कीमत की गणना गलत की गई थी।

जीडीए जिला जल्द ही प्रशासन से नोएडा की तर्ज पर सर्किल रेट घटाने की गुहार लगाएगा। अधिकारियों ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर की बुरी हालत को सुधारने के लिए इससे बेहतर उपाय नहीं। इस सेक्टर की हालत सुधरने पर अवस्थापना निधि के खजाने का वजन बढ़ेगा।

लापहरवाही

सात साल में खत्म हो गया यमुना एक्सप्रेस-वे का सूचना तंत्र

यमुना प्राधिकरण की चार सदस्यीय टीम की जांच में जेपी इंफ्राटेक कंपनी की लापरवाही आई सामने

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

यमुना एक्सप्रेस-वे पर हर माह करोड़ों रुपये टोल वसूलने वाली जेपी इंफ्राटेक कंपनी इसके रखरखाव को लेकर बेहद लापरवाह है। यमुना प्राधिकरण की चार सदस्यीय टीम की जांच में इसका पर्दाफाश हुआ है। जेपी इंफ्राटेक ने एक्सप्रेस-वे पर जन सुविधाओं एवं सुरक्षा उपकरणों के जो दावे किए थे। उसमें से कई मौके पर मौजूद नहीं थे। कंट्रोल रूम को सूचना देने का तंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक को नोटिस जारी कर खामियों को एक माह में दूर करने का आदेश दिया है।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे का 2012 में उद्घाटन हुआ था। उस वक्त एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा एवं संचालन के लिए लगे आधुनिक उपकरण को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। लेकिन हादसों के बढ़ते ग्राफ से इन दावों पर सवालिया निशान लग चुका है। हादसों की वजह का पता लगाने के लिए प्राधिकरण ने बाहरी एजेंसियों के साथ अपने अधिकारियों से कई बार जांच भी कराई। एक्सप्रेस-वे पर मौजूद सुविधाओं व उपकरणों की भी जांच की गई। लेकिन इन जांच में सामने आई खामियों पर पर्दा ही पड़ा रहा। आगरा में पिछले दिनों हुए रोडवेज बस हादसे के बाद से शासन से लेकर यमुना प्राधिकरण पर एक्सप्रेस-वे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का दबाव है। यमुना प्राधिकरण ने डीजीएम परियोजना एके अरोड़ा के नेतृत्व में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति को यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौजूद सुविधाओं एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों की जांच सौंपी गई थी। सीईओ को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौजूदा संसाधनों में बड़ी खामियां मिली हैं।

नहीं काम कर रहे हैं इमरजेंसी कॉल बाक्स यमुना एक्सप्रेस-वे पर किसी भी तरह की घटना की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचाने का सूचना तंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। एक्सप्रेस-वे पर हर दो किमी पर दोनों ओर 164 इमरजेंसी कॉल बॉक्स (ईसीबी) लगाए गए थे। आज इसमें से एक भी बॉक्स कार्य नहीं कर रहा है। हादसा ग्रस्त वाहन का पता लगाने के लिए लगे 25 वीआइडीएस में से मात्र 16 ही दुरुस्त हैं।

नाइट्रोजन भरने की व्यवस्था भी चौपट यमुना यमुना एक्सप्रेस-वे पर टायर फटने की घटनाओं को रोकने के लिए नाइट्रोजन भरने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए एक्सप्रेस-वे तीन जगहों पर नाइट्रोजन भरने के लिए सेंटर बनाए गए। लेकिन इसमें से एक भी सेंटर क्रियाशील नहीं है। यही नहीं घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एक्सप्रेस-वे पर तैनात की गई एंबुलेंस भी तय संख्या से एक कम मिली।

हर माह 28 करोड़ मिलता है टोल : यमुना एक्सप्रेस-वे पर निर्माण पर 12000 करोड़ लागत आई थी। इसके एवज में जेपी इंफ्राटेक को नोएडा से लेकर आगरा तक पांच जगहों पर पांच-पांच सौ हेक्टेयर के एलएफडी आवंटित किए गए थे। साथ ही 36 साल तक एक्सप्रेस-वे पर टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है। कंपनी को हर माह एक्सप्रेस-वे से टोल के रूप में करीब 28 करोड़ रुपये की कमाई होती है।

> यमुना एक्सप्रेस-वे पर संसाधनों की कमी मिली है। इसे दूर करने के लिए जेपी इंफ्राटेक को नोटिस जारी किया गया है। एक माह में सभी मानक पूरे करने होंगे।
>
> **-डा. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण**

एक्सप्रेस वे पर संसाधनों की स्थिति

संसाधन	मानक	क्रियाशील स्थिति में
सीसीटीवी	19	13
वीआइडीएस	25	16
स्पीड कैमरा	30	15
वैरिएबल मैसेज साइन	8	7
मौसम की जानकारी के लिए लगे बोर्ड	3	3
ईसीबी	164	0
स्पीड गन	3	3
पैट्रोलिंग वाहन	11	11
क्यूआरटी	01	01
नाइट्रोजन फिलिंग स्टेशन	03	0
क्रेन	6	5
एंबूलेंस	6	5 मौके पर मिलीं

वर्चुअल अदालत में 24 घंटे हो सकेगा ट्रैफिक चालान का भुगतान

जासं, नई दिल्ली : अब बिना अदालत गए 24 घंटे ट्रैफिक चालान का भुगतान हो सकेगा। घर बैठे ट्रैफिक चालान के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा तीस हजारी अदालत में शुक्रवार को शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति एवं ई-कमेटी के चेयरमैन मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने इस अदालत की शुरुआत की। इस दौरान हाई कोर्ट के कई न्यायमूर्ति और तीस हजारी अदालत के न्यायाधीश भी मौजूद रहे।

अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो चालान करेगी, उसका डाटा वर्चुअल कोर्ट में जमा किया जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले के मोबाइल पर एक एसएमएस से इसकी जानकारी दी जाएगी और उसमें लिंक होगा। लिंक पर जाकर चालान देखा जा सकेगा। अगर नियम तोड़ने वाले को जुर्माने की रकम मंजूर होगी तो उसी लिंक से भुगतान हो सकेगा। अगर जुर्माना रकम मंजूर नहीं होगी तो वर्चुअल अदालत में पेश होकर भुगतान करना होगा।

9 अलग-अलग न्यायाधिकरण हैं देश में अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटारे के लिए। इनमें से चार न्यायाधिकरण को तो फैसला सुनाने में 10 से 28 वर्ष लगे। विवाद निपटारे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक-2019 लोकसभा में पेश किया है।

विधेयक 'जल्दबाजी' में पारित कराने पर विपक्ष दलों ने जताया ऐतराज

विरोध ▶ अलग-अलग पार्टियों के 17 सांसदों ने सभापति वैंकैया नायडू को लिखा पत्र

संसदीय परिपाटी को तोड़ने का लगाया आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में भारी विरोध के बाद भी आरटीआइ विधेयक पारित होने के झटके से उबरने में जुटे विपक्ष ने सरकार को फिर निशाने पर लिया है। विभिन्न दलों से जुड़े 17 सांसदों ने शुक्रवार को सरकार की 'जल्दबाजी' पर आपत्ति जताते हुए सभापति को चिट्ठी लिखी है। इसमें विधेयकों को बगैर किसी पुनर्मूल्यांकन के पारित कराने के सरकार के रवैये पर नाखुशी जताई गई है। साथ ही इसे संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया गया है।

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सामूहिक रूप से लिखे गए पत्र में विपक्षी दलों ने इस मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही कहा है कि अब तक जो संसदीय परंपरा रही है, उसमें अहम विधेयकों को प्रवर समिति या दूसरी किसी संसदीय समिति की पड़ताल के बाद पारित किया जाता रहा है। पत्र का समर्थन करने वालों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, द्रमुक, भाकपा, माकपा, राकांपा, टीडीपी, आप, पीडीपी, जदएस आदि दलों के सदस्य शामिल हैं।

विपक्षी दलों ने सभापति को लिखे पत्र में कहा है कि विधेयकों को पारित करने से पहले पुनर्मूल्यांकन की जो परंपरा रही है, उसके तहत 14वीं लोकसभा में 60 फीसद विधेयक संसदीय समिति के पास भेजने के बाद पारित किए गए थे। 15वीं लोकसभा में 71 फीसद विधेयक और 16वीं लोकसभा में 26 फीसद विधेयकों को समिति के पास भेजा गया था। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही अब तक 14 विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन किसी को भी संसदीय समिति के पास अध्ययन के लिए नहीं भेजा गया। विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ यह मोर्चा उस समय खोला है, जब गुरुवार को राज्यसभा में उनके भारी विरोध के बाद भी सरकार सूचना का अधिकार (आरटीआइ) संशोधन विधेयक को पारित कराने में कामयाब रही। विपक्षी दलों ने इसे सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने का कदम बताया और सभापति से संरक्षण की मांग की। ज्ञात हो संसद में विपक्ष बिखरा-बिखरा दिख रहा है।

वोटिंग के दौरान दूसरे की सीटों के पास न जाएं सदस्य

वेंकैया नायडू फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा में गुरुवार को आरटीआइ संशोधन विधेयक पारित होने के दौरान सदन में संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ हुए वाकये पर सभापति वेंकैया नायडू ने नाखुशी जताई है। उन्होंने यह व्यवस्था भी दी कि आगे से सदन में जब भी वोटिंग प्रक्रिया चल रही होगी, उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई भी सदस्य एक-दूसरे की सीटों पर नहीं जाएगा। जिसे कोई बात करनी हो, वह सदन के बाहर निकलकर या वोटिंग से पहले बात कर सकता है।

नायडू ने शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सदस्यों को आगाह किया कि सदन की गरिमा बनाए रखना उनका दायित्व है। उन्हें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। उन्होंने गुरुवार को आरटीआइ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सदन में हुए शोर-शराबे पर नाखुशी जताई। नायडू ने कहा, उन्हें यह जानकारी दी गई है कि गुरुवार को जब यह सब हो रहा था, उस समय सदन की दीर्घा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। नायडू जब यह बोल रहे थे, उस समय कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मांग की ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी निंदा की जानी चाहिए।

इस बीच संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने सभापति से गुरुवार के घटनाक्रम की फुटेज की जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कुमारी सैलजा ने उनके सुझाव पर सहमति जताई। हालांकि, सभापति ने इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सदन में शून्यकाल के दौरान निजी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस बढ़ोतरी का मुद्दा भी गूंजा।

नए कानून में सबसे पहले कसेगा हाफिज सईद व मसूद अजहर पर शिकंजा

हाफिज सईद

मसूद अजहर (फाइल फोटो)

15 वर्षों में 42 संगठन घोषित किए जा चुके हैं गैरकानूनी

बीते 15 वर्षों में 42 संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया गया। इनमें सिर्फ दीनदान अंजुमन ही ऐसा है, जिसने सरकार के फैसले के खिलाफ अपील की है। हालांकि, जब सरकार एक बार फिर अपने फैसले की पुष्टि कर देगी तो यह संगठन अदालत में चुनौती नहीं दे सकेगा।

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के आतंकवाद विरोधी कानून में प्रस्तावित संशोधनों के प्रभाव में आने के बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर आतंकवादी घोषित किए जाने वाले पहले मोस्ट वांटेड होंगे। प्रस्तावित नए संशोधन अंतरराष्ट्रीय मानकों और संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन के अनुसार होंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक-2019' को लोकसभा ने बुधवार को पारित कर दिया है। अब इसे चर्चा के लिए राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। अगर इसे संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो आतंकवादी घोषित किए जाने वाले की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी।

अधिकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकेगा। वह केंद्रीय गृह सचिव के समक्ष अपील कर सकेगा, जो 45 दिनों के भीतर फैसला करेंगे। एक कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समीक्षा समिति बनेगी, जिसमें कम से कम दो सेवानिवृत्त केंद्रीय सचिव शामिल होंगे। आतंकी घोषित किए जाने के खिलाफ इन सदस्यों तक सीधे पहुंचा जा सकेगा। सरकार उनकी संपत्ति को जब्त करने जैसे कदम उठा सकेगी। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसका ब्योरा तभी आ सकेगा जब यह बिल संसद से पारित हो जाएगा। जिसे भी आतंकी घोषित करना है, उससे संबंधित आंकड़े दूसरे देशों की सरकारों से साझा किए जा सकेंगे। ज्ञात हो, हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमले का मास्टर माइंड है और मसूद अजहर वर्ष 2001 में संसद हमला व हालिया पुलवामा हमले का मुख्य साजिशकर्ता है।

विमान घोटाले में दीपक तलवार गिरफ्तार, सात दिन के रिमांड पर

दीपक तलवार फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विमान घोटाले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी, जिसके बाद अदालत में ही सीबीआइ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर जांच एजेंसी ने उसकी 14 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन सात दिन की ही मिली। दीपक को 30 जनवरी को दुबई में गिरफ्तार किया गया था। पहले उसे मनी लांड्रिंग मामले में पकड़ा गया था। विमान घोटाले में नाम आया तो अब उसमें गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइंस का पक्ष लेते हुए बिचौलिये का काम किया, जिसकी वजह से एयर इंडिया को भारी नुकसान हुआ। इस सौदे में तलवार की कंपनी को 23 अप्रैल 2008 से छह फरवरी 2009 के बीच विदेशी एयर लाइंस कंपनियों से 6.05 करोड़ डालर दिए थे।

मटका पद्धति से मोदी ने किया पौधारोपण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद परिसर में मटका थिंबक सिंचाई पद्धति से पौधारोपण कर हरित अभियान की शुरुआत की। इस पद्धति से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है और पौधे सूखकर कभी खराब नहीं होते। गुजरात में सीएम रहते मोदी ने इस पद्धति को बढ़ावा देने की पहल की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पौधारोपण किया। एनएनआइ

चक्रव्यूह टूटने के बाद 'मध्यमार्ग' की राह पर विपक्ष

संजय मिश्र, नई दिल्ली

▶ राज्यसभा में आरटीआइ पर सरकार के बाजी पलटने के बाद शेष छह बिलों पर मध्यमार्ग की रणनीति

▶ विपक्षी खेमा आगे बीजद, टीआरएस व वाइएसआर कांग्रेस के भरोसे रणनीति से करेगा परहेज

सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पर बीजद, टीआरएस और वाइएसआर कांग्रेस के आखिर में रुख बदलने से लगे बड़े झटके के बाद विपक्षी दलों ने राज्यसभा में सरकार की घेरेबंदी के लिए आगे इन तीनों पार्टियों पर अब भरोसा नहीं करने का फैसला किया है। इसीलिए संसद के मौजूदा सत्र के दौरान रस्साकशी की संभावना वाले बाकी बचे आधा दर्जन विधेयकों पर विपक्षी दलों ने नये सिरे से रणनीति बनाने का फैसला किया है।

राज्यसभा में विपक्ष की मजबूत किलेबंदी को धराशायी करने में सरकार को मिली कामयाबी के बाद इन आधा दर्जन विधेयकों पर विपक्षी पार्टियां नई रणनीति के तहत 'मध्यमार्ग' के विकल्प पर भी गौर कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में मध्यमार्ग की इस रणनीति के तहत विपक्षी पार्टियां कुछ विधेयकों पर सरकार को गुंजाइश देने के विकल्प पर राजी हो सकती हैं। बशर्ते कुछ विधेयकों पर सरकार भी विपक्ष की बात मानने को राजी हो जाए। विपक्षी खेमे के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि आरटीआइ पर राज्यसभा में हुई जबरदस्त जोर आजमाइश के बाद सियासी हालात बदल गए हैं। ऐसे में विपक्ष की सूची में बाकी बचे सभी छह विधेयकों को प्रवर समिति को भेजने की रणनीति सिरे चढ़ाना मुश्किल है। सरकार ने भी विपक्षी पार्टियों से खींचतान वाले विधेयकों की सूची मांग ली है। साथ ही यह भी कहा है कि सभी विधेयकों को प्रवर समिति भेजने पर वह सहमत नहीं है। मगर दो-तीन विधेयकों को प्रवर या स्थाई समितियों को भेजने पर सरकार राजी हो सकती है।

विपक्षी सूत्रों ने कहा कि हर विधेयक पर सदन में आरटीआइ संशोधन बिल पारित कराने जैसा सियासी मंजर सरकार के लिए भी सुखद नहीं होगा। इसके मद्देनजर ही सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बीच का रास्ता निकालना ज्यादा मुफीद होगा। सरकार से मिले संकेतों के मद्देनजर ही विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को बाकी बचे विधेयकों पर मध्यमार्ग की रणनीति को लेकर चर्चा की। संसद के अगले दो हफ्ते इन विधेयकों पर ही चर्चा कर इन्हें पारित किया जाना है। इसीलिए विपक्षी दलों की सोमवार को होने वाली बैठक में आधा दर्जन में से ऐसे दो-तीन विधेयकों की सूची सत्तापक्ष को सौंपा जाएगी। इन्हें विपक्ष प्रवर समिति को भेजना चाहता है।

आरटीआइ संशोधन बिल पारित होने के बाद विपक्ष की सूची में तत्काल तीन तलाक बिल, वेतन संहिता विधेयक, कार्यगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल, डीएनए संशोधन बिल और गैरकानूनी गतिविधि निषेध बिल है। बीजद, टीआरएस और वाइएसआर कांग्रेस के आरटीआइ संशोधन बिल पर भरोसा दिए जाने के मद्देनजर विपक्ष इन सभी विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने की लामबंदी कर रहा था। मगर इन तीनों पार्टियों के रुख बदलने के बाद विपक्ष की लामबंदी की मुहिम कमजोर पड़ गई है और इसी वजह से विपक्षी दलों को मध्यमार्गी रणनीति के रास्ते पर गौर करना पड़ रहा है।

महिला सुरक्षा ताक पर, निर्भया खंड से नहीं खर्च किया धन

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद को बताया कि महिला सुरक्षा के लिए एक हजार करोड़ रुपये के निर्भया फंड से जुड़े कार्य या तो प्रगति पर हैं या फिर उनका कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि इस कार्य के लिए आवंटित धन और खर्च किए गए धन में काफी अंतर है। इस फंड का बड़ा हिस्सा करीब 2,840 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। ताकि दिल्ली समेत सात राज्यों की राजधानियां दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। यह प्रस्ताव मार्च, 2018 में मंजूर किया गया था। लेकिन अब तक इस पर केवल 733.92 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। निर्भया फंड के तहत ही इस साल फरवरी में ट्रैक करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 463.88 करोड़ रुपये मंजूर भी किए हैं। लेकिन अब तक इस काम के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में एक युवती के साथ हुई दरिंदगी के बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं की हिफाजत के लिए कानून बनाया था। साथ ही निर्भया फंड की व्यवस्था की थी। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से उत्पीड़ित महिलाओं के हित में धनराशि को खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

मोदी सरकार-2 के 50 दिन का कामकाज असाधारण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मोदी सरकार-2 की 50 दिन की उपलब्धियों को भाजपा ने मील का पत्थर बताते हुए कहा कि पहले 50 दिनों में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने दिशा तय कर दी है। इन फैसलों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की साफ झलक मिलती है तथा इनमें सभी वर्गों और क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वैसे तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देने की परंपरा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने 50 दिन के कामकाज का लेखाजोखा पेश कर अलग कार्यशैली की मिसाल पेश की है। इस थोड़े समय में ही सरकार की प्राथमिकताएं दिखने लगी हैं। गांव, गरीब, किसान से लेकर उद्यमियों व श्रम सुधारों तक सभी दिशा में जबरदस्त काम किए गए। पीएम किसान योजना का दायरा बढ़ाकर उसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया। किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई। सरकार ने पेयजल, जल संरक्षण, सिंचाई, नदियों की सफाई व जल संबंधी अन्य कार्यों को उच्च प्राथमिकता देते हुए इन सभी विभागों के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया। इन योजनाओं से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य आसान हो जाएगा। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ कई जन उपयोगी फैसले किए गए हैं। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने और 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला

भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते जेपी नड्डा (मध्य में)। ध्रुव कुमार

सीतारमण ने बुनियादी सुधार की दिशा में कदम उठाया है, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बल मिलेगा। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने पर जोर है। हर घर में रसोई गैस और बिजली कनेक्शन देना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। एंजल टैक्स की समाप्ति और टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। शहरी विकास के साथ ग्राम सड़क योजना को प्राथमिकता दी गई है।

नड्डा ने कहा कि इन 50 दिनों में ही सरकार ने श्रम सुधारों पर जोर देने के साथ धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा के खिलाफ कड़े कानून बनाने की दिशा में ठोक कदम उठाया है। बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने विदेश नीति के मोर्चे पर भी कई अहम पड़ाव पार कर लिए। प्रधानमंत्री के शपथग्रहण समारोह में बिम्सटेक नेताओं ने भाग लिया। शंघाई सहयोग सम्मेलन और जी-20 सम्मेलन में मोदी ने हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। मोदी ने श्रीलंका व मालदीव की यात्राएं भी कीं।

स्थायित्व की जवाबदेही पर येदियुरप्पा को मिली अनुमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ बहुमत साबित होने तक दूर-दूर ही रहेगा केंद्रीय नेतृत्व

▶ नई सरकार में बागियों को मौका देने के मुद्दे पर नड्डा ने साधी चुप्पी

गुरुवार को देर रात तक गहन मंथन के बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक में सरकार गठन के लिए पार्टी नेता बीएस येदियुरप्पा को सहमति दे तो दी, लेकिन वह तब तक पूरे प्रकरण से दूर रहेगा जब तक सरकार बहुमत साबित नहीं कर देती। लिहाजा सरकार गठन और उसके बाद स्थायित्व की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही येदियुरप्पा पर ही डाल दी गई है। येदियुरप्पा की इच्छा को देखते हुए ही उन्हें यह अवसर दिया गया है वरना केंद्रीय नेतृत्व अभी कुछ दिन इंतजार करना चाहता था। हालांकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को विश्वास है कि राज्य में स्थायित्व आएगा, लेकिन वह इस सवाल से बचते रहे कि नई सरकार में कांग्रेस-जदएस के बागी विधायकों को मौका मिलेगा या नहीं। नड्डा ने इसकी जवाबदेही भी प्रदेश नेतृत्व पर ही डाल दी।

76 की आयु पार कर चुके येदियुरप्पा की जल्दबाजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शुक्रवार सुबह से वह खुद ही ट्वीट और बयानों के जरिये यह जानकारी देते रहे कि उन्हें नेतृत्व की अनुमति मिल गई है और शाम छह बजे वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

सरकार गठन की एक संवैधानिक मजबूरी यह है कि 31 जुलाई तक सदन से वित्त विधेयक पारित कराना है। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता और संसद के जरिये वित्त विधेयक पारित कराना पड़ता ताकि वहां वेतन दिया जा सके। बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार था, लेकिन येदियुरप्पा जल्द फैसला चाहते थे।

इधर, नड्डा कर्नाटक के सवालों पर ज्यादा बोलने से बचे। उन्होंने साफ किया कि कर्नाटक में सरकार गिरने में भाजपा की कोई भूमिका नहीं थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पदों पर रहने के लिए भाजपा ने 75 वर्ष आयु का एक फॉर्मूला जरूर तैयार किया है, लेकिन येदियुरप्पा पहले ही भाजपा विधायक दल के नेता थे। वर्तमान स्पीकर के बने रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला वहीं के लोगों को लेना है। मध्य प्रदेश में दो भाजपा विधायकों के कांग्रेस का साथ देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी नजर रख रही है।

'हाथ' से फिसलता आधार

कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य चला गया। अब सिर्फ चार राज्यों (पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान) एवं एक केंद्रशासित (पुडुचेरी) में ही उसकी सरकारें बची हैं।

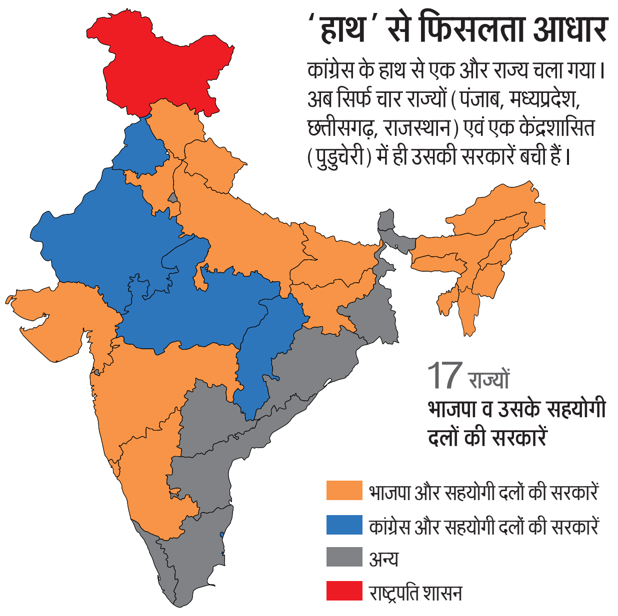

कुमारस्वामी के आदेशों पर लगाई रोक

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

मुख्यमंत्री का पद संभालते ही येदियुरप्पा ने आदेश जारी कर उनके पूर्ववर्ती कुमारस्वामी द्वारा जुलाई में जारी सभी आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

29 को विश्वास प्रस्ताव : येदियुरप्पा ने कहा, वह 29 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। उनकी सरकार बदले की राजनीति नहीं करेगी। विपक्ष को साथ लेकर चलेगी।

येद्दयुरप्पा से हुए येदियुरप्पा : राज्यपाल वजुभाई वाला को सौंपे पत्र में येदियुरप्पा ने अपने नाम की स्पेलिंग में एक 'डी' की जगह 'आइ' कर दिया (येद्दयुरप्पा से येदियुरप्पा)। बताते हैं कि ऐसा उन्होंने अंक शास्त्र से प्रभावित होकर किया है। 2007 में पहली बार सीएम बनने के बाद जब उन्हें हफ्तेभर बाद इस्तीफा देना पड़ा था तो उन्होंने नाम की स्पेलिंग में बदलाव करके उसे येद्दयुरप्पा कर लिया था।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

अनिवार्य मतदान पर संसद में दिखी अलग-अलग राय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मतदान पर निजी बिल

▶ लोकसभा में अनिवार्य मतदान पर पेश निजी विधेयक पर हुई चर्चा

▶ राज्यसभा में चुनाव खर्च सीमा के खात्मे को कानूनी संशोधन का बिल

चुनाव सुधारों से संबंधित दो निजी विधेयकों पर संसद में चर्चा हुई। लोकसभा में मतदान को अनिवार्य किए जाने से संबंधित विधेयक पर सदस्यों का अलग-अलग रुख देखने को मिला, जबकि राज्यसभा में चुनाव खर्च पर सीमाबंदी को लेकर सदस्यों ने अपने विचार रखे। लोकसभा में हुई चर्चा में मतदान को अनिवार्य किए जाने के विचार का भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी और राजेंद्र अग्रवाल तथा बीजद के बी. महताब ने विरोध किया, जबकि भाजपा के ही निहाल चंद तथा जगदंबिका पाल ने इसका समर्थन किया।

चुनाव सुधारों पर मार्च, 2015 में पेश रिपोर्ट में विधि आयोग ने अनिवार्य मतदान के विचार का ये कहते हुए विरोध किया था कि इसे लागू करना अव्यावहारिक होगा। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 66.11 फीसद लोगों ने मतदान किया जो 2014 के चुनावों में हुए मतदान से 1.16 फीसद अधिक था। रूडी ने कहा कि मतदान को अनिवार्य किए जाने से विकास होने की दलील तर्कसंगत नहीं है। शत-प्रतिशत वोटिंग खतरनाक हो सकती है। भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है। महताब ने भी कहा कि इसे लागू करना कठिन है। परंतु निहाल चंद ने अनिवार्य मतदान का ये कहते हुए समर्थन किया कि इससे चुनाव खर्च में कमी आएगी। चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं।

राज्यसभा में चुनाव खर्च का बिल : राज्यसभा में चुनाव खर्च पर व्यक्तिगत सीमा समाप्त करने के लिए 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन संबंधी निजी विधेयक पेश करते हुए कांग्रेस सदस्य एमवी राजीव गौड़ा ने कहा कि इस कानून में आदर्शवादी उपबंध से समस्या हो रही है जो वास्तव में अनुत्पादक है। मेरा सुझाव है कि चुनाव खर्च में पाबंदी खत्म करने के साथ-साथ हमें राजनीतिक दलों की फंडिंग के स्वच्छ तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना का सुझाव दिया। इसके दो हिस्से होने चाहिए। पहला भाग राजनीतिक दलों के लिए हो और उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर इसका आवंटन किया जाना चाहिए। जबकि दूसरे हिस्से का उपयोग नई पार्टियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में गौड़ा ने सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में विभिन्न दलों की ओर से कुल 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए आगे आने का अनुरोध किया। भाजपा के विजय पी. सहस्रबुद्धे ने इसका विरोध करते हुए कहा, चुनाव खर्च पर सीमा हटाने का मतलब धन बल के सहारे चुनाव जीतने वालों के आगे समर्पण करना होगा। ये एक तरह की 'भौतिक लोकप्रियता' होगी जिसमें गरीब के लिए चुनाव लड़ना असंभव हो जाएगा। जहां राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि चुनाव महंगे और आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं भाजपा के शिवप्रताप शुक्ला का कहना था कि पहले पूरे देश में चुनाव 10 लाख में निपट जाता था। अब ये खर्च कई गुना बढ़ गया है।

एनआरआइ वोटिंग अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में तीन माह के लिए याचिका स्थगित

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार देने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की अपील पर कोर्ट ने याचिका को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया है। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि चुनावों के दौरान प्रवासी भारतीयों को डाक या ई-मतपत्रों के जरिए मतदान करने की अनुमति दी जाए। उल्लेखनीय है कि सर्विस वोटरों की तरह ही एनआरआइ को प्रॉक्सी मतदान का अधिकार देने का बिल पिछले साल नौ अगस्त को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो चुका है। इसे अभी राज्यसभा में पारित किया जाना शेष है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता की दलील पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलने संबंधी बिल इसी संसदीय सत्र में पारित होने की संभावना है।

सांसदों के वाईफाई कनेक्शन से बीएसएनएल का घाटा बढ़ा

नई दिल्ली, आइएएनएस : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सांसदों को दिए जाने वाले हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन के कारण सरकारी दूरसंचार कंपनियों- बीएसएनएल व एमटीएनएल का घाटा बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, मई 2019 तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) व भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सांसदों को 757 कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।

IAS GS World PCS
सामान्य अध्ययन
नि:शुल्क कार्यशाला
29 जुलाई
Time :- 11:45 A.M.
011-27658013, 7042772062/63

5 –5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओडिशा स्थित भरतपुर कोयला खदान हादसे के मृतकों के परिजनों को। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह घोषणा की है। हादसे में चार कर्मचारियों की मौत हो गई थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 27 जुलाई 2019

कांग्रेस को आंख दिखाने वाली भाजपा खुद सहमी

बदले हालात ▶ मध्य प्रदेश में दो विधायकों के पाला बदलने से भाजपा अपने विधायकों की हिफाजत को लेकर फिक्रमंद

विधायकों के भोपाल और मंत्रालय तक के कामकाज पर रखी जा रही नजर

नईदुनिया, भोपाल

डॉ. दीपक विजयवर्गीय फाइल फोटो

पिछले छह माह की असफलता को लेकर विपक्षी दल के नाते हम कांग्रेस को आंख दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। लेकिन, मप्र की विधानसभा में जिस तरह का खेल कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, वह अनपेक्षित तो है ही शर्मनाक भी है। पूरा घटनाक्रम हमारे लिए व्यापक आकलन और समीक्षा का विषय है। - डॉ. दीपक विजयवर्गीय, मुख्य प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने भाजपा के दो विधायक शरद कोल और नारायण त्रिपाठी को क्या तोड़ा, अल्पमत के नाम पर कमलनाथ सरकार को आंख दिखाने वाली बेफिक्र भाजपा अब खुद सहम गई है। अब अपने विधायकों की हिफाजत को लेकर फिक्रमंद हो गई है। सतर्कता का आलम यह है कि पार्टी विधायक भोपाल और मंत्रालय में क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी तक जुटाई जा रही है। हालांकि, खुद को भयमुक्त दिखाने के लिए पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि खेल की शुरुआत कांग्रेस ने की है, खत्म हम करेंगे, लेकिन कब और कैसे, इसकी कोई ठोस योजना किसी के पास नहीं है।

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो विधायकों के टूटने के दो दिन बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस द्वारा खेल शुरू करने वाली जो बात कही, लगभग वही बात घटना वाले दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा भोपाल में कह चुके हैं। चौहान ने गोरखपुर में यह भी कहा कि हम सरकार गिराने में दिलचस्पी रखते तो इस सरकार का गठन ही नहीं होने देते। उनके मुताबिक, भाजपा ने कभी नहीं चाहा कि वह जोड़-तोड़ कर सरकार बनाए, लेकिन अब जब कांग्रेस इसकी शुरुआत कर चुकी है, तब भाजपा भी पीछे नहीं हटने वाली।

देखो और इंतजार की नीति : कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने वाले विधायकों के प्रति पार्टी का नरम रुख बताता है कि वह सुलह के दरवाजे बंद नहीं करना चाहती। दलबदल विधेयक के चलते ये दोनों विधायक कांग्रेस में तो शामिल हो नहीं सकते इसलिए दिल्ली के निर्देश पर इनकी मान मनौव्वल की कोशिशें जारी हैं। भाजपा यह भी जान रही है कि इन विधायकों को कांग्रेस का उच्च स्तरीय नेतृत्व तो खुशी-खुशी स्वीकार करेगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर जमकर विरोध होना तय है। इसलिए देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई जा रही है।

संतुलित बयानबाजी : दिल्ली से मिले निर्देशों के बाद अब पार्टी के तमाम बड़े नेता संतुलित बयानबाजी कर रहे हैं। कल तक सत्ता पक्ष के विधायकों के संपर्क का दावा करने वाले भाजपा नेता अब इस चिंता में हैं कि उसका कोई विधायक मुख्यमंत्री या कांग्रेस के किसी नेता से संपर्क स्थापित न कर ले। कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मंत्री व विधायक संजय पाठक को गुरुवार को इसी शक में पार्टी मुख्यालय में तलब कर लिया गया था कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। आलाकमान ने स्थानीय नेतृत्व को यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेताओं की शिकायतों को तवज्जो दें। इसलिए पिछले दो दिनों से संगठन महामंत्री सुहास भगत विधायकों की शिकायतें सुन रहे हैं।

मप्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि कांग्रेस सोचती है कि वह अपने चुहेदानी में बब्बर शेर को घेर लेगी तो यह उसका मिथ्या भ्रम है। भाजपा के सभी 108 विधायक बब्बर शेर हैं। कांग्रेस को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे।

विधायक मनीषा ने दी सफाई कहा– मैं भाजपा में ही हूं

नईदुनिया, शहडोल

मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन बुधवार को भाजपा के दो विधायकों शरद कोल और नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस का साथ क्या दिया, भाजपा विधायकों के पाला बदलने की अफवाहें उड़ने लगी। अब सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि जैतपुर विधायक मनीषा सिंह पेंद्राम कांग्रेस में जा सकती हैं। विधायक को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वे हमेशा भाजपा के साथ ही खड़ी रहेंगी।

भाजपा विधायक मनीषा सिंह ने 'नईदुनिया' से चर्चा में कहा कि कांग्रेस का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है और न ही इस बारे में किसी से कोई बात हुई है। मैं शिवराज सिंह चौहान का भरोसा किसी हाल में नहीं तोड़ सकती। मैं आज जिस मुकाम पर हूं, यह उन्हीं की देन है। विश्वासघात करना हम आदिवासियों के खून में नहीं है। विधायक ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद मुझसे कहा कि मनीषा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अफवाहों को लेकर परेशान मत होना। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद हुई मुलाकात में मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि मैं भाजपा की समर्पित कार्यकर्ता हूं और रहूंगी।

पिता क्या, पति की भी नहीं सुनूंगी : मनीषा ने दो टूक कहा कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के लिए मेरे पिता क्या, पति भी कहेंगे तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। मेरे परिजन यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। इस कारण मुझसे कभी कोई इस बारे में बात नहीं कर सकता। मालूम हो, मनीषा सिंह के पिता ध्यान सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में बांधवगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। चर्चा है कि कांग्रेस ध्यान सिंह के सहारे मनीषा को साधने की कोशिश में जुटी हुई है।

भाजपा विधायक ने स्पष्ट कहा कि भले ही मुझे लेकर लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन यह सब गलत है। हम आदिवासी आम जीवन जीते हैं और अभावों में जीते आए हैं। हमारे पास जितना है, उतने में संतोष है। कोई हमें खरीद नहीं सकता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे परिवार का सिर समाज में झुक जाए।

मध्य प्रदेश में झटके के बाद छग में बचाव की मुद्रा में भाजपा

नईदुनिया, रायपुर

- पार्टी के बड़े नेताओं ने विधायकों से संपर्क कर चर्चा की
- नेता बोले–अपने विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस फैला रही भ्रम

भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में करके जीत दर्ज की तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दो विधायक तोड़कर उनको झटका दिया। अब छत्तीसगढ़ में भाजपा बचाव की मुद्रा में है। भाजपा के आला नेताओं ने सभी विधायकों से संपर्क करके चर्चा की है।भाजपा के आला नेताओं ने कहा कि प्रदेश में जो 14 विधायक हैं, वो भाजपा की विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में उनके कांग्रेस के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वहीं, भाजपाई कांग्रेसी दावे को ट्रोल कर रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।

भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि कांग्रेस अपने विधायकों के असंतोष को दबाने के लिए भाजपा विधायकों को लेकर बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस की ओर से यह अफवाह भी उड़ाई जा रही है कि भाजपा विधायकों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के आवास पर बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि डॉ. रमन के आवास पर कोई बैठक नहीं हुई है। भाजपा नेता पंकज झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि छत्तीसगढ़ के करीब दो दर्जन विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नाराज हैं। कुछ मंत्री भी भूपेश बघेल के नेतृत्व से नाराज हैं। ऐसे में अपने विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस झूठे दावे कर रही है। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जकांछ) के कुछ विधायक संगठन के संपर्क में हैं।

बैठक के बहाने विधायकों की लेंगे टोह : भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता अभियान की बैठक शनिवार को सुबह 11 बजे आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, मोर्चा प्रकोष्ठ प्रभारी रामप्रताप सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी संतोष पांडेय सहित सांसद, विधायक, पूर्व मंडल अध्यक्ष, निगम अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य में अब तक की सदस्यता को लेकर की गई प्रगति पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधायकों पर विशेष फोकस रहेगा।

दूसरी ओर, कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक राजीव भवन में शनिवार को होगी। इसमें कांग्रेस सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में कांग्रेसजनों की भूमिका पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और दोपहर 1 बजे प्रदेश पदाधिकारियों, जिला एवं ब्लाक कांग्रेस कमेटी तथा मोर्चा संगठन–प्रकोष्ठ एवं विभाग के अध्यक्षों की बैठक रखी गई है। दोनों बैठकों में सीएम भूपेश बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

पंचायत चुनाव के लिए उत्तराखंड सरकार ने मांगी कोर्ट से मोहलत

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- हाई कोर्ट ने प्रशासकों के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाई
- सरकार व राज्य चुनाव आयोग को बुधवार तक जवाब देने को कहा

हाई कोर्ट ने राज्य में तय समय सीमा में पंचायत चुनाव नहीं कराने के मामले में सरकार व राज्य चुनाव आयोग को बुधवार तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। इस दौरान सरकार ने अदालत से पंचायत चुनाव के लिए चार माह की मोहलत मांगते हुए कहा कि अभी पंचायती राज एक्ट में संशोधन होना है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अभी पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि जब सरकार तय समय सीमा में चुनाव नहीं करा रही है तो संवैधानिक संस्था होने के बाद भी आयोग द्वारा याचिका दाखिल क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने ग्राम पंचायतों में तैनात प्रशासकों के वित्तीय अधिकारों पर भी रोक लगा दी है। प्रशासक केवल दैनिक कार्य ही करेंगे, नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में ऊधमसिंह नगर जिले के गुलरभोज के पूर्व प्रधान नईम अहमद की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद छह जुलाई को प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। अब तक सरकार द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की है। संवैधानिक प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने तक पंचायतों में नई बॉडी अस्तित्व में आ जानी चाहिए। याचिका में कहा गया कि 2010 में मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें कहा था कि आगामी पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होंगे और पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता के अनुसार संविधान के अनुच्छेद-243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव हो जाने चाहिए, मगर सरकार तय समय पर चुनाव नहीं करा पा रही है।

जदयू ने कहा–तीन तलाक पर विरोध के बावजूद भाजपा से संबंध बने रहेंगे

राज्य ब्यूरो, पटना

- कहा, कुप्रथा खत्म करने को बनने वाले कानून में सबकी राय ली जाए

केसी त्यागी फाइल फोटो

जदयू ने गुरुवार को लोकसभा में तीन तलाक बिल का विरोध किया। घोषणा की गई कि जदयू राज्यसभा में भी इस बिल का विरोध करेगा। भाजपा के लिए महत्वपूर्ण तीन तलाक बिल का विरोध करने के चलते भाजपा-जदयू के रिश्ते में खटास की आशंका जाहिर की जा रही है। पार्टी के बड़े नेता इस आशंका को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि विवादास्पद मुद्दों पर विरोध के बावजूद दोनों दलों की दोस्ती कायम रहेगी। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। मालूम हो कि दोनों दलों की अल्पसंख्यक संबंधी नीति अलग-अलग है। लेकिन, सरकारी नीतियों को लागू करने के मामले में दोनों के बीच कभी मतभेद नहीं हुआ।

यह पहला मौका नहीं है, जब जदयू और भाजपा के बीच का मतभेद संसद के भीतर और बाहर उजागर हुआ है। जदयू ने साफ कहा है कि वह एक स्वतंत्र राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करेगा। दोनों की दोस्ती सुशासन के इकलौते एजेंडे पर टिकी है। इससे इतर राजनीतिक मुद्दों पर दोनों के बीच संयोग से ही किसी मुद्दे पर एकता कायम हो पाती है। दोनों दलों के बीच सुशासन पर बनी समझदारी का मॉडल बिहार है। साझा सरकार चल रही है। लेकिन, जदयू के घोषणा-पत्र के किसी हिस्से को लागू करने पर भाजपा ने कभी एतराज नहीं किया।

जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि तीन तलाक ही नहीं, भाजपा की कश्मीर संबंधी नीति का भी हम समर्थन नहीं करते हैं। जदयू शुरू से कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 को हटाने की भाजपा की नीति का विरोध करता रहेगा। कहा कि हम किसी प्रथा की बुराइयों को जारी रखने के समर्थक नहीं हैं। हमारी स्पष्ट राय है कि ऐसी प्रथाओं में सुधार की जरूरत है। लेकिन, इसके लिए सभी भागीदारों की सहमति जरूरी है। सभी भागीदारों की राय से कानून बने तो इसे लागू करने में आसानी होगी।

त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार सुशासन के एजेंडे पर जो भी काम कर रही है, जदयू पूरी ताकत से उसके साथ है। भाजपा के साथ भविष्य के रिश्ते के सवाल पर त्यागी ने कहा कि भाजपा के साथ सिर्फ बिहार में हमारा चुनावी गठबंधन हैं। दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जदयू वहां दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हमारी अच्छी तैयारी, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भी है।

मैहर के कांग्रेस नेताओं ने नारायण का किया विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना

- कांग्रेस नेताओं ने कहा– इस्तीफा देकर आएं नारायण, पार्टी बदलकर करते हैं नौटंकी

मप्र की कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट देने वाले भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी का कांग्रेस में ही विरोध शुरू हो गया है। नारायण त्रिपाठी के विधानसभा क्षेत्र मैहर (जिला सतना) के कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर उन्हें कांग्रेस में लेने की संभावना पर विरोध जताया। नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की।

प्रेस वार्ता में मैहर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी, पुष्पराज सिंह, रामनिवास उरमलिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेश घई, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आरके सिंह समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने एकजुट होकर नारायण त्रिपाठी को पार्टी में लेने की संभावना पर नाराजगी जताई।

इस्तीफा देकर पार्टी के लिए करें काम : श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले चुनाव में नारायण त्रिपाठी का विरोध और कांग्रेस पार्टी के लिए तन, मन, धन से काम किया था। यदि त्रिपाठी को पार्टी में आना ही है तो निस्वार्थ भाव से इस्तीफा देकर आएं और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह पार्टी की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें। चतुर्वेदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें तो बस सत्ता सुख चाहिए इसीलिए वे बार-बार पार्टी बदलकर इस्तीफा देने की बजाय नौटंकी करते हैं।

भोपाल जाकर हाईकमान से दर्ज कराएंगे विरोध : उन्होंने बताया कि मैहर कांग्रेस के सभी बड़े नेता भोपाल जाकर हाईकमान से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। पुष्पराज सिंह ने भी त्रिपाठी को नौटंकीबाज करार दिया। वहीं रामनिवास उरमलिया ने कहा कि वे जब सपा में थे तब भी यही कहते थे कि मैं हमेशा सपा में रहूंगा। फिर कांग्रेस में भी इसी तरह बयानबाजी की। भाजपा में शामिल होने पर कहा कि यह मेरी आखिरी पार्टी है। मैं मरते दम तक इसी पार्टी में रहूंगा। इस बार फिर कांग्रेस में शामिल होने नौटंकी कर रहे हैं।

किसानों के नाम पर करोड़ों का खेल, बिना बताए कृषक सुरक्षा पत्रिका के सदस्य बनाए

वैभव श्रीधर, भोपाल

- बालाघाट में हुआ बड़ा घोटाला, एक करोड़ 69 लाख रुपये कर्ज की रकम में से काटकर पत्रिका को कर दिया भुगतान

मध्य प्रदेश में अभी तक किसानों के साथ नकली खाद, बीज और फर्जी कर्ज के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले सामने आते थे, लेकिन अब किसानों को बिना बताए कृषक सुरक्षा नामक पत्रिका का सदस्य बनाकर करोड़ों रुपये का गोलमाल किया गया है। इसके लिए बैंक से लेकर समिति स्तर पर मिलीभगत का तानाबाना बुना गया। एक किसान से ढाई हजार रुपये का सदस्यता शुल्क वसूला गया। मजे की बात यह है कि किसान को इसके बारे में पता ही नहीं है और उसके कर्ज खाते से राशि काटकर सीधे पत्रिका के प्रकाशक को दे दी गई।

अकेले बालाघाट में 12,263 किसानों के नाम एक करोड़ 69 लाख 93 हजार 802 रुपये का भुगतान हुआ। इसे लेकर न तो राज्य सरकार की ओर से कोई नीतिगत निर्णय लिया गया था और न ही अपेक्स बैंक ने जिला बैंक को सिफारिश की। सदस्यता के साथ पांच लीटर के पैक में एक सुरक्षा गोल्ड लाइम मुफ्त दिया जाना था, जो किसी भी किसान को नहीं दिया गया। सरकार ने कलेक्टर से मामले की जांच कराई और फर्जीवाड़ा प्रमाणित पाया गया।

अभी बालाघाट में मामला सामने आया है। अपेक्स बैंक को कहा गया है कि सभी जिला बैंकों के माध्यम से जांच कराएं, ताकि यह पता चल सके कि कहीं और तो किसानों के साथ ऐसी घटना तो नहीं हुई। यह भी दिखवाया जा रहा है कि समितियों ने बिना अनुमति भंडारण कैसे कराया। नियमानुसार समिति में रिलीज ऑर्डर के बगैर किसी भी सामग्री का भंडारण और वितरण नहीं किया जा सकता है।
डॉ. एमके अग्रवाल, आयुक्त, सहकारिता

इसके आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बालाघाट के तत्कालीन सीईओ पीएस धनवाल को निलंबित कर दिया गया और पूरे प्रदेश में जांच कराई जा रही है।

ध्यानाकर्षण से हुआ भंडाफोड़ : सूत्रों का कहना है कि कृषक सुरक्षा पत्रिका के प्रकाशक ने 14 सितंबर 2018 को बालाघाट सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर समितियों के जरिये किसानों को इसका सदस्य बनाने का ऑफर दिया। इसमें बताया कि तीन साल की सदस्यता का शुल्क दो हजार 550 रुपये रखा गया है। समितियों को कुल सदस्यता का तीन फीसदी हिस्सा बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को एक फीसद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पत्र में लिखा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कृषि के प्रति जागरूकता को देखते हुए जरूरी हो गया है कि किसानों को पत्रिका की जानकारी पहुंचे। इसमें कृषि वैज्ञानिकों के लेख 2013 से प्रकाशित किए जा रहे हैं। घोषित तौर पर ऑफर आकर्षक था, इसलिए बैंक ने इसे हाथों-हाथ लिया और किसानों को सदस्य बनाने के लिए समितियों को निर्देशित किया। नियमानुसार पहले किसानों को इसकी जानकारी दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। खानापूर्ति के लिए कुछ किसानों से ब्लैंक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। समिति के स्तर पर किसानों को सदस्य बनाकर उनके फसल ऋण के विरुद्ध राशि का भुगतान शाखाओं के माध्यम से सीधे पत्रिका को कर दिया। बालाघाट जिले से विधायक रामकिशोर कावरे ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाया तब फर्जीवाड़ा उजागर हुआ।

बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने कांग्रेस के तीन नेताओं को पीटा

नईदुनिया, बैतूल : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के सीतलझिरी गांव के पास गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब 12 बजे ग्रामीणों ने कांग्रेस के तीन नेताओं को बच्चा चोर समझकर पीट दिया। उनकी कार के कांच भी फोड़ दिए। नेताओं ने भागकर जैसे-तैसे जान बचाई और पुलिस को खबर दी।

कांग्रेस के जिला महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, जनपद सदस्य धरमू सिंह लांजीवार एवं आदिवासी कोरकू समाज के तहसील अध्यक्ष ललित बारस्कर केसिया गांव से घर लौट रहे थे। सड़क पर झाड़ियां पड़ी देखकर उन्होंने कार रोकी और बाद में कार को पलटाकर दूसरे गांव की ओर जाने लगे। तभी झाड़ियों में छिपे ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। ये लोग भागे और पाढर गांव के गोलू राठौर एवं शाहपुर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने तक आरोपित भाग चुके थे। धर्मेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट पर सीतलझिरी गांव के दिलीप वरकड़े, नाथू वरकड़े, मुकेश्वर वरकड़े, मनीष वरकड़े, दिनेश विश्वकर्मा के विरुद्ध रास्ता रोककर मारपीट करने, वाहन में तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। आरोपित फरार हैं।

बिहार में जेपी विवि के कुलपति ने सीएम कोष को बताया अशुद्ध, विधान परिषद में हंगामा

राज्य ब्यूरो, पटना

- बिहार विधान परिषद में विवादित बयान पर सदस्यों ने जताई नाराजगी
- कुलपति को सदन में बुलाने की हुई मांग, सदस्यों ने कहा कि यह अवमानना है
- कुलपति ने कहा था मुख्यमंत्री कोष से जेपी की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। यह अशुद्ध पैसा है। शुद्ध पैसे से लगेगी प्रतिमा

बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय (छपरा) के कुलपति हरिकेश सिंह के एक बयान को लेकर शुक्रवार को विधान परिषद में सदस्यों ने जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि सदन कुलपति के बयान पर संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करे। शुक्रवार को प्रश्नकाल समाप्त होते ही तनवीर अख्तर और गुलाम रसूल बलियावी ने जेपी विवि का मामला उठाते हुए कहा कि वहां के कुलपति मनमानी कर रहे हैं। दोनों सदस्य रजिस्ट्रार बहाली में मनमानी की बात कह रहे थे। इन दोनों सदस्यों की बात के बीच में ही वीरेंद्र नारायण यादव ने जेपी विवि के कुलपति के हवाले छपी खबर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने बयान दिया है कि विवि में जेपी की प्रतिमा मुख्यमंत्री कोष से नहीं लगाई जाएगी। यह अशुद्ध पैसा है। जेपी की प्रतिमा शुद्ध पैसों से लगेगी। वीरेंद्र नारायण के इतना कहते ही सदन हंगामे में डूब गया। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों का कहना था कि कुलपति पर अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए।

सभापति हारूण रशीद ने कहा कि मामला गंभीर है। शिक्षा मंत्री मामले को दिखवा लें, लेकिन सदस्य शांत नहीं हुए। नवल किशोर यादव, देवेश चंद्र ठाकुर, डॉ. मदन मोहन झा, सुबोध कुमार और रामवचन राय ने कहा कि विशेषाधिकार का मामला उठाकर उन्हें सदन में बुलाया जाना चाहिए। राजभवन को उनकी बर्खास्तगी के लिए भी लिखा जाना चाहिए। सभापति ने कहा मामला गंभीर है, शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सदन में हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा वे रिपोर्ट मंगवा कर देख लेते हैं फिर उनके मामले पर विचार किया जाएगा।

उप्र में 65 हजार करोड़ के निवेश की नींव रखेंगे अमित शाह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दुनिया को 'बदलते यूपी' का संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2 आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे गृहमंत्री अमित शाह रविवार को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश की नींव रखेंगे। इसके गवाह देश के तमाम उद्यमी और औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि बनेंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आयोजित औद्योगिक परियोजनाओं के भूमिपूजन समारोह को लेकर सरकार खासी उत्साहित है। पिछले वर्ष 29 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। सरकार का दावा है कि उनमें से 35 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है और शेष में से दो को छोड़कर सभी का काम चल रहा है। इसी क्रम में रविवार को इसी परिसर में भूमिपूजन का दूसरा समारोह किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इसमें 65 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहीं 292 औद्योगिक परियोजनाओं का भूमिपूजन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के अलावा विभिन्न उद्योगों से संबंधित छह सत्र होंगे, जिनकी अध्यक्षता विभागीय मंत्री करेंगे।

लापरवाही

फूडग्रेन के बिगड़े हुए अकाउंट के मामले को सुलझाने के लिए नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र की अगुआई वाली कमेटी को सौंपनी थी रिपोर्ट

छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट, छह माह में भी नहीं मिली

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- 31 हजार करोड़ रुपये के फूड अकाउंट का मामला, सब कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट
- राहत की उम्मीद, वित्त आयोग द्वारा बनाई कमेटी की बैठक एक अगस्त को

फूडग्रेन के बिगड़े हुए अकाउंट के मामले को सुलझाने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 11 फरवरी को नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र की अगुआई में बनाई कमेटी से छह हफ्तों में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन छह महीने बाद भी यह रिपोर्ट वित्त आयोग को नहीं मिली है। पता चला है कि इस कमेटी ने आगे एक सब कमेटी का गठन कर दिया था जिसकी रिपोर्ट रमेश चंद्र को सौंप दी गई है। एक अगस्त को इस सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी।

पंजाब की ओर से मुख्य सचिव करण अवतार सिंह मीटिंग में शामिल होंगे। सब कमेटी ने पंजाब की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सहमति व्यक्त की है। माना जा रहा है कि 15वां वित्त आयोग 31 हजार करोड़ के फूड अकाउंट में पंजाब को राहत दे सकता है।

पूर्व अकाली भाजपा सरकार ने कर्ज में बदला : पंजाब की पांच विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न खरीदने के लिए केंद्र सरकार से कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) ली जाती है। केंद्र की एजेंसी एफसीआइ के साथ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, बारदाना, ब्याज, वैट और लेबर जैसे खर्चों को लेकर विवाद कई सालों से चला आ रहा है। बैंकों ने पिछला अकाउंट क्लीयर किए बिना जब नई कैश क्रेडिट लिमिट देने से इन्कार कर दिया तो केंद्र सरकार के दबाव में पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने एजेंसियों के इस कर्ज को स्पेशल टर्म लोन में बदलवा लिया। ऐसा करने से सरकार पर 30,584 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ गया जिसकी हर महीने 270 करोड़ रुपये की किश्त बन गई है।

कैप्टन ने 2017 में उठाया मामला

कैप्टन अमरिंदर सिंह
फाइल फोटो

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में सत्ता में आते ही यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के पास उठाया। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से झा कमेटी का भी गठन किया गया जिसने कई तरह के सुझाव दिए जिसमें पंजाब को ब्याज में राहत देने की बात भी थी। मौजूदा सब कमेटी ने भी उसी तर्ज पर पंजाब को राहत देने की मांग की है।

पंजाब को राहत मिलना आसान नहीं

अब बड़ा सवाल यह है कि अगर वित्त आयोग रमेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को मान लेता है तो पंजाब को यह राहत किस रूप में दी जाएगी। विभाग के एक सीनियर अधिकारी का मानना है कि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मामला एक बार फिर से वित्त मंत्रालय के पास जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद ही वित्तीय आयोग अपनी रिपोर्ट में राहत की कोई घोषणा कर सकता है। आयोग को अपनी रिपोर्ट अक्टूबर में प्रधानमंत्री को सौंपनी है।

विधायक इरफान बोले जय श्री राम, मंत्री सीपी सिंह अल्लाह–हू–अकबर

राज्य ब्यूरो, रांची : जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से नगर विकास एवं आवास मंत्री सीपी सिंह द्वारा तथाकथित तौर पर जय श्रीराम का नारा लगवाने को लेकर उत्पन्न विवाद शुक्रवार को मानसून सत्र की समाप्ति के साथ ही थम गया। सत्रावसान के बाद विधानसभा परिसर में दोनों साथ-साथ नजर आए। दोनों ही नेताओं ने एक स्वर में कहा, हम धर्म की नहीं, विकास की राजनीति करते हैं। हमारी जोड़ी राम- रहीम की है, चाचा-भतीजे की है। गंगा-जमुनी संस्कृति में हम विश्वास करते हैं। धर्म कोई हो, सम्मान करते हैं। इस दौरान इरफान ने जहां जय श्रीराम का नारा बुलंद किया, वहीं सीपी सिंह ने अल्लाह-हू-अकबर कह इस मामले पर विराम लगा दिया।

बताते चलें कि बुधवार को दोनों ही नेताओं के बीच मजाक में जो संवाद हुआ वह राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बन गई। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। इस स्थिति को संभालते हुए दोनों ही नेता शुक्रवार को फिर मीडिया से मुखातिब हुए। दोनों ही नेताओं ने कहा कि इस मामले को बेवजह तूल दिया गया।

चुनाव बहिष्कार हुआ तो त्राल में भी होगा भाजपा का विधायक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- उमर ने लोगों को चुनाव बहिष्कार के खतरों से किया आगाह

उमर अब्दुल्ला फाइल फोटो

जम्मू कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को लोगों को चुनाव बहिष्कार के खतरों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर बहिष्कार हुआ तो विधानसभा चुनाव में भी वही होगा जो संसदीय चुनाव में हुआ। उमर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हुआ तो अनंतनाग के त्राल (जहां से बुरहान वानी और जाकिर मूसा निकले हैं) में भी भाजपा का विधायक होगा। वे लोग यहां कुछ निर्वाचन क्षेत्रों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उमर ने राम माधव का नाम लिए बिना अपने ट्विटर पर लिखा है कि नेकां और पीडीपी ने चुनाव से दूरी रखी इसलिए आपने जम्मू कश्मीर में कुछेक शहरों और कस्बों पर कब्जा कर लिया है। आपको क्या लगता है कि हम विधानसभा चुनाव में आपको आसान सा वॉकओवर देंगे।

गौरतलब है कि संसदीय चुनाव में राज्य की छह में से तीन सीट पर भाजपा और तीन पर नेकां विजयी रही। नेकां-पीडीपी ने जम्मू संभाग में अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे थे। इससे पूर्व पंचायत और शहरी निकाय चुनावों का नेकां और पीडीपी ने पूरे राज्य में बहिष्कार किया था। संसदीय चुनाव के दौरान घाटी में त्राल निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं।

53 सड़कें बंद हैं हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की वजह से। मौसम विभाग ने पहली अगस्त तक पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में 55 मिलीमीटर बारिश हुई।

जौहर यूनिवर्सिटी की सात हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त

जागरण संवाददाता, रामपुर

सांसद आजम खां को उपजिलाधिकारी सदर की कोर्ट से एक और झटका लगा है। एसडीएम सदर ने गुरुवार को जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का आदेश दिया था। शुक्रवार को जौहर यूनिवर्सिटी की सात हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने शासन को गलत रिपोर्ट भेजी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

उपजिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर आदेश दिया कि यह गलत रिपोर्ट के आधार पर लीज पर ली गई है। इसलिए पट्टे को निरस्त किया जाता है। यह जमीन सपा शासनकाल में 24 जून 2013 को 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर अहमद खां के नाम से लीज पर दी गई थी। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेत की जमीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इसलिए, इसे पट्टे पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस समय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसे नवीन परती भूमि बताते हुए शासन को गलत रिपोर्ट भेजी। छह जून 2019 को निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने यह मामला पकड़ा और उपजिलाधिकारी सदर के न्यायालय में वाद दायर कराया।

माफी मांगें आजम : मायावती

राब्यू, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा में की गई टिप्पणी के लिए सपा सांसद आजम खां की निंदा करते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें केवल संसद में ही नहीं, बल्कि सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया कि आजम ने लोकसभा में पीठासीन महिला के खिलाफ जिस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, वह महिलाओं की गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला और अति निंदनीय है।

जयाप्रदा पर टिप्पणी करने में आजम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

मुरसलीन, रामपुर

- सपा सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच में आई तेजी

सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं रामपुर के सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच में तेजी आ गई है। लोकसभा क्षेत्र रामपुर से भाजपा प्रत्याशी रहीं अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ एसीजेएम-1 के न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

उनके खिलाफ पिछले चार माह में 44 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें 27 मुकदमे ऐसे हैं, जो जमीन कब्जाने से संबंधित हैं। उन्होंने शाहबाद में हुई जनसभा में जयाप्रदा के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान दिया था। प्रशासन की ओर से मुकदमा कराया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन पर पाबंदी भी लगाई थी। शाहबाद थाने में दर्ज कराए मुकदमे में पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया है।

जयाप्रदा बोलीं-आजम की सदस्यता रद हो : जयाप्रदा का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे आजम का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा है। उनका अपमान करके उन्होंने दिखा दिया है कि महिलाओं के लिए उनकी मानसिकता कितनी दूषित है। ऐसे व्यक्ति को सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी सदस्यता रद की जानी चाहिए। पूर्व विधायक बीना भारद्वाज भी कहती हैं कि महिलाओं के प्रति आजम का नजरिया कभी अच्छा नहीं रहा।

आजम खां के विवादित बोल

कलट्टर फलट्टर से मत डरियो। देखा है, मायावती जी बड़े-बड़े अफसरों से जूते साफ कराती हैं। इसका बार उन्हीं से गठबंधन है। इनसे उनकी ही जूते साफ कराऊंगा। **2019 के लोकसभा चुनाव में**

मुलायम सिंह यादव धोती के नीचे खाकी पैंट पहनते हैं। **सपा से निष्कासन के बाद**

चाय बनाने वाले ने दो वर्ष में 80 करोड़ रुपये के कपड़े बदले। जो बेटा अपनी मां को पैसे के लिए लाइन में लगाता है वैसे बेटे को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। **- मोदी पर टिप्पणी**

यह किसी राजनीतिक पार्टी का कार्य लगता है। सत्ता की लोभी पार्टियां किसी हद तक जा सकती हैं। **बुलंदशहर दुष्कर्म कांड पर (इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और स्पष्टीकरण मांगा था)**

गोभक्त किसी भी होटल के मैन्यू में बीफ का दाम न लिखने दें। अगर ऐसा होता है तो सभी फाइव स्टार होटलों को बाबरी मस्जिद की तरह तोड़ दिया जाए। **दादरी कांड के बाद**

कारगिल में विजय दिलाने वाले सेना के जवान हिंदू नहीं मुस्लिम थे। **2014 में गाजियाबाद की रैली में**

संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे लोग मुजरिम हैं। एक दिन के सजायाफ्ता कल्याण सिंह को गवर्नर बना दिया। मोदी जी ने हिंदू-मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी की है। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर एक ऐसा शख्स बैठा है, जो 302 का मुजरिम है। **टांडा की जनसभा में**

इन पर भी मचा बवाल

- बदायूं में भारत माता को डायन कहा। जिसके लिए उन पर केस भी हुआ।
- जुलाई 2017 में सेना के जवानों के अंग काटने को लेकर विवादित बयान दिया। इसे लेकर भी उनपर मुकदमा हुआ, जो अदालत में विचाराधीन है।
- 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र बयान दिया।
- 2014 के चुनाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर कहा, 302 का अपराधी गुंडा नंबर वन उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने आया है। चुनाव आयोग ने लिया था संज्ञान

...लेकिन राजनीति भी हुई सदन में

प्रथम पृष्ठ से आगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सपा सांसद आजम खां की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर लोकसभा में सियासत भी देखने को मिली। सभी सदस्यों ने एक सुर में आजम खां के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन कांग्रेस के अधिर रंजन चौधरी और एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरे मामले उठाकर भाजपा को निशाने पर लेने की कोशिश भी की।

कांग्रेस नेता चौधरी ने खान की भर्त्सना की हालांकि कुछ मुद्दों पर वह भटकते दिखे और सोनिया गांधी को भाजपा नेताओं की ओर से 'इटालियन कठपुतली' कहे जाने का मामला भी उठाया। लेकिन मौके की नजाकत को भांपते तत्काल स्थिति साफ की कि कांग्रेस आजम खां के बयान से क्षुब्ध है और कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका समर्थन करेगी।

वहीं, ओवैसी ने कहा कि वह सदन की भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के आरोपित भाजपा नेता एमजे अकबर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। सपा नेता अखिलेश यादव सदन में तो नहीं आए। लेकिन उन्होंने बाहर कहा कि अगर भाजपा नेता उनके खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों को वापस लेते हैं तो वह भी अपनी टिप्पणियों को वापस ले लेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय ने दोबारा की हुड्डा से लंबी पूछताछ

मुसीबत ▸ मानेसर मामले में सीबीआइ कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

तबीयत बिगड़ने की अफवाह से परेशान रहे समर्थक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में पूछताछ के लिए ईडी के कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा। जागरण

मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाजपा सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। पहले दिन से यह लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इन्होंने प्रदेश के विकास का कोई काम नहीं किया। राज्य के लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए। कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह भ्रष्टाचार व घोटालों की भरमार है। यह सरकार सिर्फ हवा में तीर चलाती है। इन्हें जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के झूठे मामलों में से मैं डरने वाला नहीं हूं। **- भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा।**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दोबारा लंबी पूछताछ की।

गुरुग्राम के करीब 1500 करोड़ रुपये के मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाले में हुड्डा से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। हुड्डा के विरुद्ध विभिन्न मामलों में एक अलग-अलग जांच चल रही है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुड्डा से करीब 10 घंटे की लगातार पूछताछ की गई। उनको शुक्रवार को फिर ईडी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित अपने कार्यालय में बुलाया। लंच के बाद हुड्डा दोपहर तीन बजे प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंच गए थे। रात आठ बजे तक हुड्डा ईडी कार्यालय से नहीं लौटे थे। हुड्डा को इससे पहले मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में ही पंचकूला स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश होना था। हुड्डा अपने वकीलों के साथ वहां गए, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तारीख 6 अगस्त निर्धारित कर दी गई। सीबीआइ कोर्ट से लौटने के बाद हुड्डा चंडीगढ़ सेक्टर तीन स्थित अपने सरकारी निवास पर चले गए। वहां सैकड़ों समर्थक पहले से जमा थे। कुलदीप शर्मा और गीता भुक्कल समेत कई विधायक उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान अफवाह फैल गई कि हुड्डा की तबीयत खराब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर (बीपी) और शुगर लेवल बढ़ गया है। कुछ डाक्टरों को फ्लैट पर बुलाया गया। हुड्डा के पूर्व ओएसडी एमएस चोपड़ा ने इसे कोरी अफवाह बताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बीपी व शुगर टेस्ट सामान्य व नियमित प्रक्रिया है।

ईडी और सीबीआइ कर चुकी हुड्डा के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी : मानेसर जमीन घोटाले को लेकर हुड्डा सहित 34 अधिकारियों, बिल्डरों व लोगों के खिलाफ सीबीआइ ने 17 सितंबर 2015 को केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया। दोनों एजेंसियां हुड्डा के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर चुकी हैं। पंचकूला स्थित विशेष सीबीआइ कोर्ट में विचारण चल रहा है। इस मामले में सीबीआइ चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है।

शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे सूचना आई कि मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत 18.5 एकड़ जमीन और कुल 66.57 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। यह संपत्ति महामाया एक्सपोर्ट व अन्य की है, जो गुरुग्राम में है और इसका संबंध मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाले से है। 66.57 करोड़ रुपये इस कंपनी के बैंक खातों में है, जिसे अटैच किया गया है।

लोन चुकाने के बाद जमीन के मूल कागजात नहीं लौटाए, सीएमडी पर केस

नईदुनिया, भोपाल : लोन चुकाने के बावजूद जमीन के कागजात नहीं लौटाने के मामले में होम लोन फाइनेंस कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के सीएमडी कपिल वाधवान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मप्र के भोपाल में एमपी नगर पुलिस द्वारा दर्ज केस में वाधवान पर आरोप है कि एक बिल्डर ने प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था, जिसे चुकाने के बाद कंपनी लोन लेने के लिए गिरवी रखी जमीन के मूल दस्तावेज नहीं लौटा रही है।

मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर विनोद अहिरवार ने बताया कि बिल्डर राजेश पारदासानी (46) ने डीएचएफएल कंपनी से प्रोजेक्ट पर 2013 में लोन लिया था। इसके लिए उन्होंने अवधपुरी प्रोजेक्ट की जमीन गिरवी रखी थी। उन्हें करीब 25 करोड़ का लोन स्वीकृत किया था। ऋण डिस्बर्समेंट (लोन की बाकी) के रूप में उन्हें साढ़े बारह करोड़ की राशि मिली। जितना कार्य प्रोजेक्ट रूप में किया जाना था, वह किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया है। इसी दौरान बिल्डर को और रकम की जरूरत पड़ी तो बिल्डर ने कंपनी से निवेदन किया कि उन्हें डिस्बर्समेंट के साढ़े चार करोड़ पए दिए जाएं। इसके कंपनी ने इनकार कर दिया और कहा कि जब तक निर्धारित प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, वह और रकम नहीं दे सकती है। कंपनी के मुताबिक, दूसरी संपत्ति (कोलेटरल) पर रकम दी जा सकती है। इस पर बिल्डर ने अपनी चंदनपुरा कालियासोत की दस एकड़ जमीन के मूल दस्तावेज जमा कर दिए। कंपनी ने 18 जून 2013 को इस दस्तावेज पर साढ़े चार करोड़ का लोन दिया। पारदसानी ने बताया कि उन्होंने डीएचएफएल का 15 मार्च 2018 को पूरा लोन चुका दिया था। इसकी एनओसी भी कंपनी ने दे दी। बावजूद इसके कंपनी उनकी जमीन के मूल दस्तावेज (कोलेटरल कागजात) नहीं लौटा रही थी।

78 घंटे तक खंगाला बिश्नोई का आवास, भव्य को दिल्ली ले गई आयकर की टीम

जागरण संवाददाता, हिसार

- दिल्ली में आमने-सामने बैठकर हो सकती है पति-पत्नी और पुत्र से पूछताछ
- विधायक जसमा देवी का ब्लड प्रेशर बढ़ा, अस्पताल में कराया भर्ती

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के यहां सेक्टर 15 स्थित आवास पर 78 घंटे तक की जांच के बाद आयकर विभाग टीम दिल्ली रवाना हो गई। टीम कुलदीप के पुत्र भव्य बिश्नोई को अपने साथ दिल्ली में रजोकरी स्थित उनके फार्म हाउस ले गई। वहां कुलदीप, पत्नी रेणुका और बेटे भव्य को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जा सकती है।

आयकर अधिकारियों ने मंगलवार सुबह साढ़े सात बजे से शुक्रवार दोपहर एक बजे तक पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के इस आवास का कोना-कोना छान मारा। अधिकारियों को कुलदीप के समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पुलिस के 50 सुरक्षाकर्मियों के सुरक्षा घेरे के बीच टीम को निकाला गया। भव्य को गाड़ी का शीशा तक नहीं खोलने की हिदायत दी गई। भव्य के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था, मगर वह अपनी मुस्कान से इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वह समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए निकल गए।

जसमा देवी को अस्पताल में कराया भर्ती : टीम के जाते ही समर्थक गेट खोलकर सीधे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की पत्नी एवं पूर्व विधायक जसमा देवी के पास पहुंचे। जसमा देवी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थीं। उनके चेहरे पर तनाव था। वह बार-बार कहती नजर आईं कि उनसे बातचीत न की जाए। उनको तुरंत प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया जहां उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है।

...तो बिगड़ सकते थे हालात : जसमा देवी की तबीयत बिगड़ने का समाचार पढ़ते ही शुक्रवार को उनके समर्थक कुलदीप के आवास के सामने पार्क में एकत्र होने लगे थे। दोपहर 12 बजे कार्यकर्ताओं ने टीम को कुलदीप के आवास के प्रांगण में एकत्रित होता देख नारेबाजी शुरू कर दी। दोपहर एक बजे जैसे ही टीम बाहर निकली, पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाते हुए समर्थकों को पार्क से बाहर नहीं निकलने दिया।

चार दिन बाद घर से निकले जसमा व भव्य

आयकर की टीम ने मंगलवार को बिश्नोई के प्रतिष्ठानों पर एक साथ सर्वे शुरू किया था। भव्य बिश्नोई आदमपुर में थे, जबकि जसमा देवी दो महीनों से सेक्टर 15 स्थित आवास पर रह रही थीं। मंगलवार को हिसार स्थित आवास पर कार्रवाई के बाद शुक्रवार तक भव्य और जसमा देवी यहीं थे, उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया। टीम ने आवास के पीछे बने कुक और माली के क्वार्टर तक खंगाले। मुजफ्फरपुर (बिहार) के गांव केवपपुर निवासी शत्रुघ्न ने बताया कि वह पहले दिल्ली फार्म हाउस में थे। उनके क्वार्टर की भी अच्छे से तलाशी ली थी। टीम ने पूछा था कि वह कब से यहां रह रहा है और उसे कितना वेतन दिया जा रहा है।

ई-टेंडरिंग घोटाले में मप्र के पूर्व मंत्री के सचिव सहित दो गिरफ्तार

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई-टेंडरिंग घोटाले की छानबीन में जुटे आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा के निज सचिव वीरेंद्र पांडे और ओएसडी रहे निर्मल अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले एक-सवा महीने से जांच एजेंसी इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी।

गौरतलब है कि दोनों को पिछले माह ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तारी उस समय भी की जा सकती थी, लेकिन जांच एजेंसी ने अपना केस और पुख्ता बनाने के लिए जान बूझकर दोनों को निगरानी में रखा। बताया जाता है कि ईओडब्ल्यू को छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। इनमें यह भी बताया जाता है कि पांडे और अवस्थी हैदराबाद की मेसर्स मैक्स मेंटेना लिमिटेड कंपनी के सतत संपर्क में रहे। इन दोनों की घोटाले में शामिल अन्य कंपनियों से कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। दोनों का संबंध सोरठिया वेलजी प्रा. लिमिटेड कंपनी के टेंडर से जोड़कर देखा जा रहा है। अब यह भी माना जा रहा है कि जांच एजेंसी पूर्व मंत्री से भी पूछताछ कर सकती है। शक की सुई एक वरिष्ठ आइएएस पर भी उठ रही है। उस समय वे विभागीय प्रमुख थे।

कारोबारी गुरपिंदर की मौत मामले में जेल में ही बनाया इंक्वायरी ऑफिस

जागरण संवाददाता, अमृतसर

आइसीपी पर नमक की खेप में 584 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में नामजद कारोबारी गुरपिंदर सिंह की जेल में मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए एडीसी हिमांशु अग्रवाल ने जांच तेज कर दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है। इसलिए एडीसी प्रतिदिन 12 घंटे से ज्यादा समय जांच में लगा रहे हैं। वहीं नहीं पिछले चार दिन से अपने सरकारी आफिस भी नहीं गए। पता चला है कि उन्होंने फतहपुर जेल के एक कमरे को ही उन्होंने अपना इंक्वायरी रूम (जांच आफिस) बना लिया है। केस से जुड़े गुरपिंदर के परिवार सहित 150 से ज्यादा लोगों को वहीं बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। बयान कलमबद्ध करने के अलावा वीडियो स्टेटमेंट भी ली जा रही है।

जांच के चौथे दिन शुक्रवार को एडीसी सुबह दस बजे फतहपुर जेल पहुंच गए थे। वीरवार रात उन्होंने जेल प्रबंधन से 2 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक की वीडियो फुटेज मांगी थी, जो उन्हें सौंपी गई। शुक्रवार को दोपहर तक कई लोगों के बयान कलमबद्ध कर लिए गए।

अफसरों की लापरवाही के चलते शुगर की इंसुलिन मिस कर गया था गुरपिंदर

एडीसी ने शुक्रवार को पूरा दिन कई लोगों से पूछताछ की। इनमें गुरपिंदर को खाना देने वाले मुलाजिम, खाना बनाने वाले लोग भी शामिल थे। उनसे गुरपिंदर के आचरण और शुगर की ली जाने वाली दवाओं के बारे में जानकारी एकत्र की गई। आरोप है कि कुछ अफसरों की लापरवाही के चलते गुरपिंदर शुगर के इंसुलिन मिस कर चुका था। इसके बाद एडीसी घरिंडा थाना, राजासांसी थाना और कस्टम विभाग के अफसरों के बयान कलमबद्ध हो सकते हैं।

फतहपुर जेल में एडीसी हिमांशु अग्रवाल के इंक्वायरी आफिस में जेल के किसी भी अधिकारी को जाने की अनुमति नहीं है। सुबह जांच कार्यालय में पहुंचने के बाद एडीसी किसी का फोन रिसीव नहीं करते। समन भेजकर बुलाए गए लोगों के बयान कलमबद्ध करवाए जाते हैं। सारी कार्रवाई में एडीसी के दो मुलाजिम उनके साथ रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा भर्ती का ब्योरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- उत्तर प्रदेश में 72825 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला
- उम्मीदवारों की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित
- न्यायमूर्ति यूयू ललित और एमआर शाह की पीठ ने की मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 72825 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार से भर्तियों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुश्री रेणुका कुमार को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश की अवहेलना का आरोप लगाने वाली उम्मीदवारों की अवमानना याचिका पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2011 में निकाली गई 72825 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति यूयू ललित और एमआर शाह की पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद गत 22 जुलाई को यह आदेश दिए। बहुत से उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया था। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि आदेश का पालन किया गया। प्रतिपक्षी दावों को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल कर विस्तृत ब्योरा देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह जिलावार ब्योरा देकर बताए कि अक्टूबर 2016 तक किन श्रेणियों में कुल कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा क्या अक्टूबर 2016 के बाद कोई नई नियुक्तियां प्रभावित हुईं। सरकार को यह भी बताना है कि कोर्ट के 27 जुलाई 2015 के आदेश और उसके बाद संशोधित किये गए आदेश में भर्ती के लिए तय मापदंड पूरे करने वाले लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भर्ती हुई। अगर हुई है तो उनका नाम, उम्र और कट ऑफ को देखते हुए उन उम्मीदवारों की ओर से अर्जित अंकों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हलफनामे की सॉफ्ट कापी अवमानना याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों को भी दी जाएगी। इसके पहले कोर्ट ने मामले पर विस्तृत बहस सुनकर अवमानना याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि प्रदेश सरकार की ओर से एक अक्टूबर 2016 को कोर्ट में दाखिल किये गए हलफनामे में दिए गए नियुक्ति के आंकड़े कोर्ट के दो नवंबर 2015 और सात दिसंबर 2015 के आदेश में दर्ज किये गए आंकड़ों से भिन्न हैं। उन्होंने कहा कि दो नवंबर 2015 के आदेश में दर्ज आंकड़े देखे जाएं तो उस दिन तक 58135 उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी थी या वे ट्रेनिंग कर रहे थे। बाकी बचे 14640 जिसमें से 12091 को हर दृष्टि से नियुक्ति के लिए योग्य माना गया। सरकार की मानें तो 12091 में से सिर्फ 391 की नियुक्ति हुई तो फिर राज्य सरकार उस हलफनामे में दिए गए आंकड़ों में यह कैसे कह सकती है कि 64257 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है।

जबकि इसके जवाब में प्रदेश सरकार की दलील थी एक अक्टूबर 2016 के हलफनामे में दिये गए आंकड़े पर याचिकाकर्ताओं ने कभी विवाद नहीं उठाया। यहां तक कि मामले में कोर्ट ने 2017 में फाइनल फैसला भी दे दिया उसके एक साल बाद ये याचिकाएं दाखिल कर आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार से भर्ती का ब्योरा मांगते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।

इंतजार

मुनि की रेती के कैलाश गेट व वेद निकेतन के बीच निर्माणाधीन है जानकी सेतु, 30 जनवरी 2020 तक पूर्ण होना है जानकी सेतु का निर्माण, रामझूला का दबाव घटाएगा यह पुल

ऋषिकेश में गंगा पर जानकी सेतु समय से तैयार करना बड़ी चुनौती

दुर्गा नौटियाल, ऋषिकेश

ऋषिकेश में मुनिकीरेती व वेद निकेतन के बीच निर्माणाधीन जानकी सेतु (झूला पुल) को दिसंबर तक पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है। इससे रामझूला पुल पर जन दबाव को भी कम किया जा सकेगा। जागरण

तीर्थनगरी ऋषिकेश में मुनि की रेती व स्वर्गाश्रम के बीच गंगा नदी पर बन रहे जानकी सेतु (झूला पुल) के निर्माण में लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल के बंद होने के बाद राम झूला पुल पर बढ़े अतिरिक्त दबाव ने जानकी सेतु को विकल्प के तौर पर तैयार करने के लिए विभाग को मजबूर कर दिया है। लोनिवि अब जनवरी 2020 तक हर हाल में जानकी सेतु को तैयार करने में जुट गया है।

टिहरी व पौड़ी जिलों को तीर्थनगरी से जोड़ने वाले दो महत्वपूर्ण पुलों लक्ष्मण झूला व राम झूला में से लक्ष्मण झूला को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए, अब राम झूला पुल पर ही पूरा दारोमदार टिका हुआ है। इन दोनों पुलों के विकल्प के तौर पर वर्ष 2006 में मुनि की रेती के कैलाश गेट व स्वर्ग आश्रम के वेद निकेतन घाट के बीच जानकी सेतु के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। दिसंबर 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने करीब 30 करोड़ की लागत से बनने वाले इस झूला पुल के लिए चार लाख रुपये की टोकन मनी जारी की। इसके बाद यहां झूला पुल के बजाय मोटर पुल की संभावनाएं तलाशी गई और इस कवायद में छह साल का समय निकल गया। वर्ष 2012 में शासन से यहां थ्री-लेन ब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिली। 25 मार्च 2013 को धन आवंटित भी कर दिया गया। पुल निर्माण की जिम्मेदारी जायका कंपनी को सौंपी गई।

वर्ष 2016 के हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले इस पुल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। मगर, कंपनी का काम इतना धीमा रहा कि तय समय पर पुल नहीं बन पाया। नतीजा कंपनी से जानकी सेतु के निर्माण का कार्य छीन लिया गया। वर्ष 2016 में 346 मीटर लंबे इस थ्री-लेन ब्रिज को पूरा करने का कार्य हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। मगर, बजट के अभाव में इस कंपनी ने भी कुछ समय बाद काम बंद कर दिया। बीते वर्ष जब इस पुल की लागत का आकलन किया गया तो रिवाइज्ड एस्टिमेट 50.79 करोड़ पहुंच चुका था। इसमें से 11 दिसंबर 2018 को वित्त समिति ने 49 करोड़ की मंजूरी देते हुए निर्माण का काम शुरू करवाया।

फिलहाल जानकी सेतु के निर्माण का कार्य 83 फीसद पूरा हो चुका है। लोनिवि ने कार्यदायी संस्था को 30 जनवरी 2020 तक काम पूरा करने की डेडलाइन दी है। अब जबकि, लक्ष्मण झूला आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है और राम झूला आबादी का भारी दबाव झेल रहा है, तब तय समय पर जानकी सेतु का निर्माण एक बड़ी चुनौती है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जनवरी 2020 के आखिर तक हर हाल में जानकी सेतु का निर्माण पूरा हो जाएगा। यदि तय समय पर निर्माण पूरा होता है तो जानकी सेतु राम झूला पुल का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। साथ ही लोनिवि को भी राम झूला पुल की मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

बंगाल के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए देने का निर्देश

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- ट्रिब्यूनल ने महंगाई भत्ता मामले पर सुनाया फैसला

स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सैट) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मियों को भी डीए (महंगाई भत्ता) का भुगतान करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को डीए मामले की सुनवाई में सैट ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि शहीद दिवस के अवसर पर मंच से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 123 फीसद महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार इससे अतिरिक्त बोझ वहन नहीं कर पाएगी।

सैट के न्यायमूर्ति आरके दास और न्यायाधीश सुरेश बाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के रहने व खान-पान के स्तर को बेहतर करने के लिए डीए दिया जाता है ताकि बढ़ती हुई महंगाई का असर उनपर न पड़े। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका निर्धारण करती है, इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर डीए मिलना चाहिए। यह उनका अधिकार है। राज्य सरकार छह महीने के भीतर इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी करे। इसके साथ ही एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान करने का उन्होंने निर्देश दिया। सैट ने कहा कि राज्य सरकार ने 2001 से 2011 तक नियमित रूप से डीए का भुगतान किया, लेकिन इसके बाद यह अनियमित होता चला गया। डीए का भुगतान कैसे किया जाए, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बकाया का भुगतान करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। सैट ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार चाहे तो डीए का भुगतान नकद में भी कर सकती है। इसे पीएफ खाते में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके साथ ही सैट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द छठा वेतन आयोग लागू करने को लेकर जरूरी कदम उठाने को कहा।

18 हजार फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई कारगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का इस्तेमाल किया था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 27 जुलाई 2019

कारगिल के शहीदों का आजीवन ऋणी रहेगा देश : कोविंद

नमन ▸ द्रास नहीं जा पाए राष्ट्रपति, श्रीनगर में ही दी शहीदों को श्रद्धांजलि

खराब मौसम के चलते कारगिल की जगह श्रीनगर में उतरा विमान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में मौसम खराब होने से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शुक्रवार को द्रास दौरा अंतिम समय में रद हो गया। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर के बादामी बाग स्थित चिनार कोर मुख्यालय में कारगिल युद्ध स्मारक स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ राज्यपाल सत्यपाल मलिक और अन्य अधिकारियों ने भी पुष्पचक्र अर्पित किए। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर पर लिखा कि अतुलनीय वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की भावना का परिचय देते कारगिल युद्ध में भाग लेने और देश की एकता और अखंडता को यकीनी बनाए रखने वाले सशस्त्र बलों के प्रति यह राष्ट्र हमेशा आभारी रहेगा।

कारगिल युद्ध की जीत पर हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर मुख्य समारोह स्थल द्रास में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को द्रास वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने द्रास में एक सैनिक दरबार को भी संबोधित करने के अलावा तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक भी करनी थी।

ऑपरेशन विजय की सफलता के 20 साल पूरे होने पर शुक्रवार को श्रीनगर में कारगिल के शहीदों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हालांकि उन्हें द्रास में मुख्य समारोह में शिरकत करनी थी, लेकिन मौसम में खराबी की वजह से उनका कार्यक्रम रद करना पड़ा। जागरण

कारगिल में नहीं उतर पाया राष्ट्रपति का विमान : शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति दिल्ली में वायुसेना के विशेष विमान में सवार होकर कारगिल के लिए रवाना हुए। उन्हें कारगिल से हेलीकॉप्टर से द्रास पहुंचना था, लेकिन कारगिल में मौसम खराब होने के चलते विमान को श्रीनगर ले जाया गया। सुबह करीब नौ बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रीनगर टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से वह हेलीकॉप्टर में राजभवन के पास स्थित नेहरू हेलीपैड पर पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रपति राजभवन में करीब 10 मिनट तक राज्यपाल के साथ रहे। वह राज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बादामी बाग स्थित चिनार कोर मुख्यालय पहुंचे।

राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका पर लिखा : कारगिल विजय दिवस की 20वीं सालगिरह पर मैं एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम अपने वीर जवानों की बहादुरी के कारनामों, उनकी शौर्य गाथाओं को याद कर रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। हम अपने इस महान राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं।

अक्साई चिन और गुलाम कश्मीर को वापस लेना है : रावत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि अक्साई चिन और गुलाम कश्मीर हमारा है, हमारे राष्ट्र का हिस्सा है और इसे वापस प्राप्त करना है। इसे कैसे प्राप्त करना है, यह एक राजनीतिक फैसला है, जिसे देश के राजनीतिक नेतृत्व को तय करना है। हमें जो आदेश होगा, हम वही करेंगे।

द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में जनरल रावत ने कहा कि कश्मीर अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं रह गया है। पाकिस्तान इस मामले को हवा देने और कश्मीर में हमेशा अशांति फैलाए रखने के लिए घुसपैठियों को इस तरफ भेजने का हर संभव प्रयास करता है। जनरल रावत ने कहा कि घुसपैठ का प्रयास जब भी होता है, घुसपैठियों को एलओसी से ही मारकर भगा दिया जाता है।

यह पूछे जाने पर कि गुलाम कश्मीर को कैसे हासिल किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था तो उन्हें वापस खदेड़ दिया गया, लेकिन कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा, जिसे आज हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नाम से जानते हैं। अक्साई चिन और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है। गुलाम कश्मीर को वापस हासिल करने के लिए हमें सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा। इसे कैसे वापस लिया जाना है, यह सरकार को तय करना है। लेकिन मैं यहां देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि आप बेफिक्र रहें। सशस्त्र सेनाओं को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, वह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे पूरा किया जाएगा। हमारे जवान हमेशा सरहदों की हिफाजत करते रहेंगे।

पाकिस्तान द्वारा 1999 की तरह कारगिल घुसपैठ की साजिश की संभावना पर उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो उसे तबाही झेलनी पड़ेगी।

- राजनीतिक नेतृत्व को लेना है फैसला, जो आदेश होगा, हम करेंगे
- कश्मीर अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं, पाकिस्तान दे रहा हवा

जम्मू-कश्मीर के कब्जे वाले हिस्से को खाली करें पाक और चीन : इंद्रेश

जागरण संवाददाता, जम्मू

- जम्मू-कश्मीर के बाशिंदे ललकार रहे वापस किया जाए हमारा हिस्सा
- आतंकवाद से मुक्ति के लिए 122 देशों ने भारत को दिया समर्थन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के हिस्सों को तुरंत खाली कराने की वकालत की है। कारगिल विजय दिवस पर शुक्रवार को टीचर्स भवन में फोरम फरी अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की ओर से कराए गए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का 78 हजार वर्ग किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि 48 हजार वर्ग किलोमीटर चीन ने दबाया हुआ है। ऐसे में हमें क्या रात में नींद आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर इन देशों को ललकार रहा है। कश्मीर इनका नहीं हमारा है। हमारा हिस्सा वापस किया जाए। इंद्रेश ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को छुड़ाने के लिए जागरूक बनने और आंदोलन छेड़ने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि आज गुलाम कश्मीर क्षेत्र की विधानसभा सीटें जम्मू-कश्मीर विधानसभा में खाली पड़ी हैं, लेकिन अब देश गुलाम कश्मीर को वापस लेगा। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान देश दुनिया में अलग-थलग पड़ चुका है। इस्लामिक देशों की कांफ्रेंस में भारत अतिथि बना, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया। मगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई। इंद्रेश ने कहा कि भारत पर आज दुनिया को भरोसा है। विश्व भारत के साथ चलने को तैयार है। आतंकवाद से मुक्ति के लिए 122 देशों ने समर्थन देकर बता दिया कि वे आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ हैं। इस मौके पर पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह और जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे देश ने शहीदों को किया सलाम

नई दिल्ली, जेएनएन

- मोदी ने कारगिल युद्ध के दौरान जवानों से मुलाकात की पुरानी तस्वीर साझा की

कारगिल युद्ध में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर मिली जीत के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने वीर सपूतों की शहादत और बहादुरी को सलाम किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'कारगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का मैं हृदय से वंदन करता हूं। यह दिवस हमें अपने सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। उन पराक्रमी योद्धाओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जय हिंद!' पीएम ने पुरानी तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, '1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मुझे कारगिल जाकर हमारे बहादुर जवानों के साथ एकजुटता दिखाने का मौका मिला था। उस समय मैं जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के लिए पार्टी का काम किया करता था।' प्रधानमंत्री उन तस्वीरों में जवानों से बातचीत करते तथा अस्पताल में एक अधिकारी से मिलते दिख रहे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, 'हमारे जवानों के शौर्य, पराक्रम और शहादत को यह देश कभी भूल नहीं सकता।' उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 1965, 1971 और 1999 में हारने के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वह भारत के साथ पूर्ण और सीमित युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए छद्म युद्ध लड़ता है।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक शॉर्ट फिल्म 'इंमोर्टल ऑफ कारगिल' साझा करते हुए लिखा, 'मुझे इस क्रिएटिव फिल्म में आवाज देने का मौका मिला...लेकिन कभी देश के लिए खून देने का मौका मिला तो वह भी दूंगा...जय हिंद।' अभिनेता अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा, 'भारत के वीरों को लाखों सलाम।' लता मंगेशकर ने 'जो समर में हो गए अमर' गीत साझा किया।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया, 'आपने हमारे लिए जो किया, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। आदर, प्यार व प्रणाम।'

युद्ध के हीरो सतपाल को डबल प्रमोशन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने सीनियर कांस्टेबल से बनाया एएसआइ
- कारगिल में जिस शेर खां को मारा, उसे पाक ने सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार दिया
- पंजाब पुलिस में 2010 में भर्ती हुए थे सतपाल, अभी भवानीगढ़ में हैं तैनात

कारगिल युद्ध में दिखाई बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित पंजाब पुलिस के सीनियर कांस्टेबल सतपाल सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक साथ दो पदोन्नति दी है। उन्हें एएसआइ बना दिया गया है और इस पद पर उनकी नई भर्ती होगी। सतपाल ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना में कर्नल शेर खां को मार गिराया था। बाद में शेर खां को पाकिस्तान ने सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार निशान-ए-हैदर दिया था।

सतपाल 2010 में पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। इस समय वह संगरूर जिले के भवानीगढ़ कस्बे में ट्रैफिक पुलिस में तैनात हैं। इतने समय तक प्रदेश सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को पूरी तरह से अनदेखा करने पर कैप्टन ने अफसोस जताया। उल्लेखनीय है कि सतपाल सेना की उसी बटालियन से संबंधित हैं, जिसमें कैप्टन अमरिंदर रहे हैं।

सतपाल ने कर्नल शेर खां सहित चार को मारा था : सात जुलाई 1999 को जब पाकिस्तान की सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था तो सतपाल भारतीय सेना की उस टीम का हिस्सा बने जिसने यह कब्जा छुड़वाया। सतपाल ने कहा कि पाकिस्तान की नार्दन लाइट इंफेंट्री का कमांडर कर्नल शेर खां बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन वह उनकी गोली का शिकार हुआ। उसके अलावा पाक के तीन और भी मारे गए। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्नल शेर खां को बहादुरी पुरस्कार देने की सिफारिश भारतीय ब्रिगेड कमांड एमपीएस बाजवा ने पाकिस्तान को की थी। बाजवा ने बर्फीली चोटियों पर शेर खां द्वारा दिखाई बहादुरी की पुष्टि की थी।

उम्र के नियमों में छूट देगी सरकार : पंजाब सरकार द्वारा सतपाल को एएसआइ भर्ती करने के लिए अधिकतम उम्र की शर्तों में छूट दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को विशेष निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने बताया कि सतपाल ने छह माह पहले ही अपना तबादला संगरूर से भवानीगढ़ में करने की मांग की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया। उनकी पदोन्नति संबंधी नियमों में छूट के बारे में कैबिनेट से बाद में मंजूरी ले ली जाएगी।

कारगिल युद्ध में दिखाई बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित पंजाब पुलिस के सीनियर कांस्टेबल सतपाल सिंह को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक साथ दो पदोन्नति देकर एएसआइ बना दिया है। जागरण

विजय दिवस पर द्रास में फिर गूंजी सेना की शौर्य गाथा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- सशस्त्र सेनाओं के तीन प्रमुखों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि
- दुश्मन को दी चेतावनी, कारगिल की ओर मुंह करने की कोशिश न करे

कारगिल विजय दिवस पर द्रास में शुक्रवार को भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टरों में भारतीय चोटियों को आजाद करवाने वाले शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। मुख्य कार्यक्रम कारगिल पहाड़ियों की ओट में बने द्रास वार मेमोरियल में हुआ। यहां पर सशस्त्र सेनाओं के तीन प्रमुखों ने सेना के शहीदों को सलामी दी। इसके साथ ही दुश्मन को कड़ी चेतावनी भी दी कि वह फिर कभी कारगिल की ओर मुंह करने की कोशिश न करे। अगर फिर हिमाकत हुई तो अबकी बार खून के आंसू रोना पड़ेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खराब मौसम के कारण द्रास न पहुंचने के कारण मुख्य समारोह के कार्यक्रम में तब्दीली करनी पड़ी। ऐसे में थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह ने सुबह सेना और वायुसेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

चीता हेलीकॉप्टरों ने वार मेमोरियल पर फूल बरसाए : सेना के चीता हेलीकॉप्टरों ने वार मेमोरियल पर फूल बरसाए। शहीदों की याद में बिगुल पर सैनिकों की लास्ट पोस्ट धुन ने सबको भावुक कर दिया। हर किसी की आंखों में उन सैनिकों के लिए आंसू थे, जिन्होंने दुर्गम चोटियों को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी।

दुश्मन के मंसूबों को नहीं होने देंगे कामयाब : थलसेना अध्यक्ष

थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि शहीदों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों से शहीदों को याद कर उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। इस दौरान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ ने कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से भी बातचीत की।

पांच साल में हर तरह के हथियार बनने लगेंगे देश में : डीआरडीओ

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने शुक्रवार को बड़ी बात कही।

संगठन प्रमुख सतीश रेड्डी ने कहा, भारत आने वाले पांच साल में रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तब हम जटिल तकनीक वाले हथियार और रक्षा उपकरण भी हम तैयार करेंगे, किसी भी उत्पाद के लिए हमें विदेश का रुख नहीं करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि हथियारों और रक्षा उपकरणों के विकास के मामले में डीआरडीओ का इतिहास उपलब्धियों से भरा हुआ है। रेड्डी ने बताया कि कई क्षेत्रों के रक्षा उपकरणों के निर्माण के मामले में भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। इनमें विभिन्न क्षमताओं के रडार, युद्ध के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तारपीडो और कम्युनिकेशन सिस्टम प्रमुख हैं। इस समय हम अपना विमानवाहक युद्धपोत तैयार कर रहे हैं और कई तरह के टैंक विकसित कर रहे हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस को बनाने के बाद डीआरडीओ अब मार्क 2 आरवी स्टील्थ एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। विश्वास है कि आने वाले पांच साल में हम इन सारी परियोजनाओं पर सफलता प्राप्त कर चुके होंगे।

विवादित एलएसी पर भारत-चीन वार्ता सही दिशा में : नरावने

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख ने पाकिस्तान और चीन को किया सतर्क
- कहा- जो अतीत से सीख नहीं लेते, उन्हें सबक सिखाना आता है

सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने शुक्रवार को कहा कि विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन से बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। हर चरण की वार्ता के बाद मतभेद कम होते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त मुद्दे के हल के लिए समय सीमा तय करना मुश्किल होगा।

लेफ्टिनेंट जनरल ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा-'उम्मीद है कि हमारे हित एक बिंदु पर पहुंचेंगे और हम औपचारिक तौर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। नरावने से जब यह पूछा गया कि वार्ता किस चरण में पहुंच गई है, तो उन्होंने कहा-'हम बातचीत के 23वें व 24वें चरण में हैं। इस संबंध में कोई समय सीमा तय करना मुश्किल होगा। जितनी जल्द मुद्दा सुलझ जाएगा, उतनी जल्दी ये दो बड़े एशियाई पड़ोसी इन बाधाओं से आगे निकलकर प्रगति की राह पर बढ़ पाएंगे।' गौरतलब है कि डोकलाम विवाद के बाद दिल्ली और बीजिंग के बीच कूटनीतिक स्तर पर चर्चा शुरू हुई है।

सेना के फोर्ट विलियम स्थित पूर्वी कमान में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में मिली विजय की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर नौसेना और वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस मौके नरावने ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'पश्चिम के हमारे पड़ोसी की तरह ही उत्तर के हमारे पड़ोसी के साथ भी अगर शांति बनी रहती है तो दोनों तरफ के लोग उच्च्वल भविष्य की कामना कर सकेंगे। चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। उन्होंने नाम न लेते हुए चीन और पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि जो अतीत में हुई भूल से सबक नहीं लेते हैं, उन्हें कैसे शिक्षा देनी है, यह भारतीय सेना अच्छी तरह जानती है। किसी भी कीमत पर देश की आन-बान और शान पर आंच नहीं आने दी जाएगी।

दुश्मन पर कहर ढाएंगी नई होवित्जर तोपें

विवेक सिंह, जम्मू : सेना के बेड़े में शामिल होने जा रही नई होवित्जर तोपें दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगी। बोफोर्स तोप के नाम से मशहूर 155 एमएम की एफएच-77 होवित्जर तोपों की जगह अब जल्द आधुनिक एम 777 होवित्जर तोपें लेंगी। थलसेना अध्यक्ष अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना आधुनिकीकरण की राह पर है। साल 2020 तक की आर्टिलरी में नई होवित्जर तोपें शामिल की जाएंगी।

लद्दाख सुरक्षा दृष्टि से भारतीय सेना के लिए अहमियत रखता है। पश्चिम लद्दाख में नियंत्रण रेखा पार पाक नापाक इरादे रखता है तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कारगिल से सीख लेकर भारतीय सेना और वायुसेना लगातार सशक्त होने की मुहिम पर है।

कारगिल के द्रास में शुक्रवार को विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद रावत ने कहा कि आधुनिक हो रही आर्टिलरी के लिए अब के-9 वज्र तोप देश में ही तैयार की जा रही हैं। बोफोर्स जैसी दो तोपें भी देश में निर्मित हो रही हैं। बोफोर्स तोप का असली नाम 155-एमएम होवित्जर तोप है। भारतीय सेना के बेड़े में 1980 में शामिल हुई इस तोप ने युद्ध में पासा ही पलट दिया था।

वार मेमोरियल पर शहीदों को किया नमन

कारगिल विजय दिवस की 20 वीं वर्षगांठ पर देशभर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चला। अमृतसर स्थित वार मेमोरियल पर शुक्रवार को शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंची इन महिलाओं का जज्बा देखते ही बनता था। एएफपी

नई व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दोनों सदनों में चार विधेयक हुए पारित, उद्योगों की स्थापना में आड़े आ रही जमीन की दिक्कत को दूर किया जाएगा

उप्र में लीज पर दी जा सकेगी खेती की जमीन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दोनों सदनों में शुक्रवार को चार विधेयक पारित हुए। निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए रविवार को आयोजित होने वाले भूमि पूजन समारोह से पहले योगी सरकार ने शुक्रवार को विधानमंडल से उप्र राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित कराकर उद्योग जगत को बड़ा संदेश दिया है। विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे उद्योगों की स्थापना में आड़े आ रही जमीन की दिक्कत को दूर किया जा सकेगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सभी विधेयक प्रभावी हो जाएंगे।

उप्र राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 में यह प्रावधान है कि प्रदेश में खेती की जमीन कृषि और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पट्टे (लीज) पर दी जा सकेगी। यदि कोई भूमिधर जिसे जमीन हस्तांतरित करने का अधिकार है, यदि वह अपनी जमीन या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए करेगा तो उप जिलाधिकारी उसके आवेदन पर इसकी जांच कर उस भूमि को गैर कृषिक घोषित करेगा। एसडीएम को आवेदन मिलने के 45 दिन के अंदर जमीन को गैर कृषिक घोषित करने के बारे में निर्णय करना होगा।

योगी आदित्यनाथ फाइल फोटो

राज्य के प्रतीक चिह्न के अनुचित प्रयोग पर सजा

विधान सभा में उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक विधेयक, 2019 भी पारित हुआ। इस में राज्य के प्रतीक चिह्न का अनुचित प्रयोग किये जाने पर दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। वहीं विधेयक को सपा सदस्य उज्ज्वल रमण सिंह ने प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग की।

भू-गर्भ जल प्रदूषित करने पर 20 लाख तक जुर्माना

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2019 के जरिये सरकार ने भू-गर्भ जल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। यह विधेयक लागू होने के बाद भू-गर्भ जल उपभोक्ताओं को शुल्क देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना और कारावास की भी सजा हो सकती है। भू-गर्भ जल प्रदूषित करने पर तीन वर्ष कारावास और दस लाख रुपये से लेकर सात वर्ष कारावास और 20 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

जयपुर के अस्पतालों में पंजीकरण के लिए धर्म बताना जरूरी

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए यदि किसी मरीज को पंजीकरण कराना है तो उसे अपना धर्म बताना पड़ेगा। प्रबंधन का कहना है कि जनसंख्या आधारित डाटाबेस तैयार करने के लिए ऐसा किया गया है।

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी ने 12 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा है कि सभी अस्पतालों की ओपीडी में पंजीकरण के समय मरीजों से एक आवेदन पत्र भरवाया जाए। इसमें मरीजों से जुड़ी सभी जानकारियां, इसमें उनके धर्म की जानकारी भी शामिल है, वह ली जाए। इसके लिए आवेदन पत्र में धर्म का एक कॉलम भी बनाया गया है। अस्पताल के अधीक्षक डीएस मीणा का कहना है कि मरीज के लिंग, उम्र, क्षेत्र आदि के बारे में जानकारी लेने से चिकित्सा क्षेत्र में शोध के लिए आवश्यक डाटाबेस तैयार होता है। इससे यह पता लगाने में भी आसानी होती है कि किसी क्षेत्र में, कितनी जनसंख्या में किस तरह का रोग फैल रहा है।

अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमले का मुख्य आरोपित गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

गुजरात के अक्षरधाम में 17 साल पहले हुए आतंकी हमले के मुख्य आरोपित मोहम्मद यासीन बट को गुजरात आतंक रोधी दस्ता (एटीएस) ने शुक्रवार को कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यासीन की गिरफ्तारी पर कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन गुजरात एटीएस ने शुक्रवार को गांधीनगर में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि यासीन को अनंतनाग से पकड़ा गया है, जहां वह एक आरा मिल पर काम कर रहा था।

अनंतनाग स्थित सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद यासीन बट को राज्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सुराग के आधार पर पकड़ा गया है। वह मूलतः कुलगाम जिले का रहने वाला है और कुछ साल पहले ही गुलाम कश्मीर से नेपाल के रास्ते भारत लौटा था। उसके खिलाफ वादी में कोई बड़ा मामला दर्ज नहीं था। वह 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम हमले के बाद ही सुरक्षाबलों से बचने के लिए पाकिस्तान भाग गया था। उसे खन्नाबल बटपोरा इलाके से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यासीन बट ने ही अक्षरधाम हमले में लिप्त लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों और उनके मददगारों को कश्मीर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरात पहुंचाने के अलावा उनके लिए हथियारों का भी बंदोबस्त किया था।

हमले में 33 लोगों की हुई थी मौत : गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एक कमांडो समेत 33 लोगों की मौत हो गई थी। हमले में लिप्त दो आतंकी भी मारे गए थे। इस हमले की साजिश में जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जो 2003 में पीडीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे, उनका नाम भी आया था। उक्त नेता की मौत हो चुकी है। कहा यह भी जाता है कि हमले की साजिश उनके घर पर तैयार हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2014 में इस मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों को रिहा कर दिया था।

125 हवाई अड्डों का प्रबंधन संभालता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) देश में। उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करने वाला यह प्राधिकरण उड़ान को कम खर्च में सुरक्षित बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

न्यूज गैलरी

भाजपा कार्यकर्ता की हत्या मामले में पांच को उम्रकैद

कन्नूर (केरल) : केरल के कन्नूर जिले की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा कार्यकर्ता केवी सुरेंद्रन की हत्या मामले में शुक्रवार को पांच माकपा कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया गया है। तेल्लीचेरी की अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश पीएन विनोद ने जिन माकपा कार्यकर्ताओं को सजा सुनाई गई है, वे हैं- अखिलेश, एम. लिजेश, के. विनीश, कलेष और शैजेश। हालांकि अदालत ने दो अन्य आरोपितों को बरी कर दिया। मालूम हो कि 62 वर्षीय सुरेंद्रन पेशे से स्वर्णकार थे। सात मार्च, 2008 को कुछ लोगों के समूह ने तेल्लीचेरी के नजदीक स्थित घर पर उन पर धारदार हथियारों से हमला किया था। पुलिस घायल सुरेंद्रन को लेकर अस्तपाल पहुंची, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई थी। (आइएएनएस)

सड़कों पर न हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी न होगी नमाज

अलीगढ़ : अलीगढ़ में सड़क पर हनुमान चालीसा व नमाज न पढ़ने संबंधी डीएम के आदेश के चलते शुक्रवार को प्रशासन अलर्ट रहा। शहर में किसी भी स्थान पर सड़क पर जुमे की नमाज होने की कोई सूचना नहीं मिली। अब शनिवार के लिए भी प्रशासन सतर्क है ताकि कहीं भी सड़क पर हनुमान चालीसा न पढ़ा जा सके। ऐसा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मंगलवार व शनिवार को कुछ लोगों ने शहर में सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। पहला मामला 19 जून को सासनी गेट क्षेत्र में सामने आया था। इससे सड़क भी जाम हो गई थी। शांति व्यवस्था बिगड़ने की भी आशंका होने लगी। ऐसे में अब चार दिन पहले डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इस पर सख्त फैसला लिया। उन्होंने सड़क पर बिना अनुमति के सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी। (जासं)

बड़े मदरसों में अनिवार्य हो राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत : वक्फ बोर्ड

लखनऊ : शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बड़े मदरसों में राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत अनिवार्य करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि देवबंद व नदवा जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों में भारतीय ध्वज फहरा कर रोज राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाए। इससे यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। अपने पत्र में रिजवी ने लिखा कि आइएसआइएस, लश्करे-तैएबा, सिमी जैसे आतंकी और कट्टरपंथी संगठन देश के मदरसों में साजिश रच रहे हैं। यह सब दुश्मन मुल्कों की साजिश के तहत हो रहा है। इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए। (राब्यू)

बीकानेर में डीएसपी 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर : राजस्थान में बीकानेर जिले की नोखा तहसील के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी रजनीश पुनिया ने बताया कि पनाराम जाट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दहेज के कारण उसकी बहन की हत्या से जुड़े मामले में नोखा के डीएसपी महमूद खान आरोपितों को गिरफ्तार करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मामले की जांच में पता चला कि महमूद खान दो लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। शुक्रवार को पनाराम तय रणनीति के तहत खान के बुलावे पर उसके घर पहुंचा और जैसे ही उसने महमूद खान को 50 हजार रुपए दिए टीम ने उन्हें दबोच लिया। (जासं)

आगरा में मेयर काउंसिल का राष्ट्रीय अधिवेशन आज

आगरा : स्वच्छता सर्वेक्षण में हैट्रिक मार चुका इंदौर हो या छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर या फिर देश का अन्य कोई शहर। देशभर के शहरों की सीरत और सूरत बदलने को शनिवार को ताजनगरी आगरा में मेयर जुट रहे हैं। मौका होगा ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन का। दो दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन स्मार्ट सिटी, 74वें संविधान संशोधन को लागू करना, एक समान मेयर का कार्यकाल पांच साल का होना सहित अन्य मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। (जासं)

झारखंड में महिला की अस्मत की ग्राम सभा ने लगाई कीमत

शर्मनाक ▸ खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र के कुरुंगा गांव की घटना

मामले को रफादफा करने की कोशिश में लगी ग्राम सभा

जागरण संवाददाता, खूंटी

झारखंड के खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के कुरुंगा गांव में ग्रामसभा ने सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता की अस्मत की कीमत एक लाख रुपये लगाई है। ग्राम सभा ने आरोपितों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को रफा-दफा करने का फरमान सुनाया है। साथ में यह भी फरमान सुनाया गया है कि इसकी जानकारी पुलिस-प्रशासन को नहीं दी जाए। यह वही कुरुंगा गांव है, जो पत्थलगड़ी की आड़ में देशद्रोहियों द्वारा लोगों को भड़काने और कानून हाथ में लेने को लेकर चर्चा में रहा है। यहां पूर्व में पुलिस-प्रशासन के पदाधिकारी व अफसर बंधक भी बनाए गए हैं।

एक लाख रुपये देकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला रफ-दफा करने की लिखित जानकारी वहीं के कुछ लोगों ने खूंटी के पुलिस अधीक्षक को दी है। खूंटी एसपी ने अड़की पुलिस को इस मामले में संवेदशीलता से काम करने का निर्देश दिया है। उधर, सामूहिक दुष्कर्म की घटना से आहत पीड़िता अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई है। महिला के मायके के लोग भी इस घटना के बाद से आक्रोशित हैं। सामूहिक दुष्कर्म की घटना 21 जुलाई की है। बताया जाता है कि उस दिन पीड़िता के नए घर की पूजा थी। आयोजन के बाद देर रात लंबू उर्फ डोडा उर्फ बुधु मुंडा, कुदापीड़ी गांव निवासी शीतल मुंडा और कुरुंगा गांव निवासी लाटेया मुंडा ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अगले दिन 22 जुलाई को दिनभर इस घटना की चर्चा रही। इस मामले को लेकर कुरुंगा के सलगाडीह में 23 जुलाई को ग्राम सभा की बैठक हुई। बैठक में ग्राम प्रधान सागर मुंडा सहित अन्य सदस्यों ने दुष्कर्म के आरोपितों से जुर्माने के तौर पर एक लाख रुपये देने का आदेश देकर मामले को रफा-दफा करने का फरमान सुनाया। पीड़िता का पति अब उसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। उसने अपनी पत्नी पर ही चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया है। बताया जाता है कि गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश में लगे हैं।

> संबंधित घटना को लेकर दो लोगों ने आवदेन दिया है। थानेदार को उक्त आवेदन की जांच का आदेश दिया गया है। गांव की मुखिया समेत अन्य सदस्यों से पुलिस ने पूछताछ की है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
> **-आलोक, एसपी, खूंटी**

पंजाब में कांग्रेस नेता ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, रूपनगर : पंजाब के नूरपुरबेदी में कांग्रेस के जिला महासचिव हरजीत सिंह पर 16 साल वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

आनंदपुर साहिब के डीएसपी दविंदर सिंह ने बताया कि पीड़िता ने इस साल दसवीं की परीक्षा दी थी। अंग्रेजी और गणित में उसकी कंपार्टमेंट आ गई। आरोपित हरजीत सिंह लोकसभा चुनावों के समय उसके घर वोट मांगने आया था। पीड़िता ने बताया कि गत एक जुलाई को जब परिवारवालों ने उससे पास कराने की बात की तो हरजीत तैयार हो गया। वह उसे व उसकी मां को अपनी गाड़ी में मोहाली ले गया। वहां मां से कहा कि उनका पास नहीं बना, जिस कारण उन्हें पार्क में ही बैठना पड़ेगा। आरोपित उसे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय ले गया। वहां एक फार्म पर हस्ताक्षर करा कहा कि वह उसका आज ही पेपर दिला देगा। इसके बाद झांसा देकर उसे एक होटल में ले गया जहां पिस्तौल के बल पर दुष्कर्म किया।

शिक्षक ने छात्राओं को चोटी पकड़कर पीटा छात्रों को जड़े थप्पड़

बैतूल, नईदुनिया प्रतिनिधि : मध्य प्रदेश के बैतूल में शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से मारपीट का मामला सामने आया है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में शिक्षक छात्रों को थप्पड़ जड़ते और छात्राओं की चोटी पकड़कर पिटाई करते दिख रहा है। 23 जुलाई को हुई इस घटना की शिकायत अभिभावकों ने प्राचार्य से की है। प्राचार्य ने शिक्षक को नोटिस देकर जवाब तलब किया है।

जानकारी के मुताबिक, कोठीबाजार स्थित शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के शिक्षक वीरेंद्र जायसवाल ने कक्षा 11वीं के गणित संकाय के विद्यार्थियों की पिटाई की है। शिक्षक ने कोई सवाल पूछा था, जिसका विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे पाए थे। इस पर उसने बारी-बारी से आधा दर्जन से ज्यादा विद्यार्थियों को पीटा। छात्राओं की चोटी पकड़कर पिटाई की। छात्रों को भी बाल पकड़कर चांटे मारे। अगले दिन विद्यार्थी डर के कारण स्कूल नहीं जा रहे थे। इसके बाद अभिभावकों को घटना की जानकारी मिली। गुरवार को अभिभावकों ने प्राचार्य से शिकायत की तो सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इसमें सारा घटनाक्रम नजर आ गया। शिक्षक वीरेंद्र जायसवाल का कहना है कि उन्होंने विद्यार्थियों से सवाल पूछे थे। जवाब नहीं मिलने पर पढ़ाई करके आने को कहा था। किसी से मारपीट नहीं की। आरोप गलत हैं।

नोटिस दिया है : अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जवाब आने के बाद मामले की जांच होगी। उच्च अधिकारियों को भी घटना के बारे में जानकारी दे दी है।

सड़क पर साइड नहीं देने पर मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में ही उतरवा ली सिपाही की वर्दी

जागरण संवाददाता, आगरा

- अदालत में ही आधा घंटे तक बिना वर्दी के खड़ा रहा सिपाही
- एसएसपी ने कहा, जिला जज और हाई कोर्ट में भेजी जाएगी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस वाहन के चालक ने एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी को साइड नहीं दी तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नाराज मजिस्ट्रेट ने अपनी अदालत में तबल कर उस चालक सिपाही की वर्दी-पेटी उतरवा ली। सूचना मिलने पर कोर्ट पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने उसे दोबारा वर्दी पहनवाई। एसएसपी ने चालक समेत मौके पर मौजूद सिपाहियों से घटना की जानकारी लेने के बाद इसकी रिपोर्ट प्रशासनिक जज और जिला जज को भेजी है। कोर्ट पहुंची पुलिस ने वर्दी उतारकर खड़े सिपाही घूरेलाल का वीडियो बना लिया था। यह वीडियो पुलिस के पास है। इसको भी पुलिस रिपोर्ट के साथ भेज सकती है।

आया मजिस्ट्रेट को गुस्सा : पुलिस लाइन से वज्र वाहन लेकर शुक्रवार सुबह कांस्टेबल चालक घूरेलाल, कांस्टेबल राजेश कुमार, आलोक भारती और मनीष कुमार जिला जेल पहुंचे थे। वहां से दो किशोरों को लेकर वे किशोर न्याय बोर्ड जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे वज्र वाहन ग्वालियर रोड से सिरौली जाने वाली लिंक रोड पर चल रहा था। तभी पीछे मजिस्ट्रेट की गाड़ी पहुंच गई। मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने हॉर्न के साथ ही हूटर और सायरन भी बजाया, मगर करीब दो किमी दूरी तक उन्हें वज्र वाहन से साइड नहीं मिला। इस पर मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया।

कोर्ट में कुछ नहीं बोल सके पुलिसकर्मी : अपनी कोर्ट पहुंचते ही उन्होंने वज्र वाहन के चालक घूरेलाल को तलब कर लिया। घूरेलाल का आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने एसएसपी से बात करके नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। इसके बाद टोपी, बेल्ट निकालकर वर्दी उतारने को कहा। डरे-सहमे घूरेलाल ने अपनी वर्दी उतार दी। अन्य पुलिसकर्मी और कोर्ट में मौजूद कर्मचारी कुछ न बोल सके। करीब तीस मिनट तक सिपाही उसी हालत में खड़ा रहा। किसी ने करीब 12 बजे पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद यूपी 100 की पीआरवी 46, चीता मोबाइल और एसओ मलपुरा महेश यादव पहुंचे। थोड़ी देर में सीओ अछनेरा नम्रता श्रीवास्तव भी पहुंचीं। तब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट से जा चुके थे। सीओ ने सिपाही को वर्दी पहनवाई।

सिपाहियों के बयान लिए : एसएसपी बबलू कुमार ने दोपहर बाद चारों सिपाहियों को पुलिस लाइन में बुलाया। बंद कमरे में घटना के बारे में जानकारी ली। सीओ अछनेरा ने भी इससे पूर्व सिपाहियों के बयान लिए।

बरेली में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बरेली

- दो समुदायों के बीच बढ़ा तनाव, हिंदू महिलाएं दे चुकीं पलायन की चेतावनी

मंदिर में पूजा करने से रोकने के बाद महिलाओं की ओर से पलायन की चेतावनी के बाद चर्चा में आए मिलक पिछौड़ा गांव में नए विवाद ने सिर उठाया है। गांव निवासी युवक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

गांव के कई लोगों के मोबाइल फोन पर शुक्रवार को एक वीडियो पहुंचा तो चर्चा होने लगी। वीडियो में गांव का एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। पुलिस को पता चला कि टिप्पणी करने वाला मिलक पिछौड़ा गांव का जाबिर है। पुलिस ने आरोपित को गांव से गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस ने एफआइआर में माना कि मिलक पिछौड़ा गांव में दो समुदायों के बीच तनाव चल रहा। ऐसे में वीडियो में प्रधानमंत्री पर टिप्पणी किए जाने से एक पक्ष व राजनीतिक लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा। हालांकि, वीडियो लोकसभा चुनाव से पहले का होने का अंदेशा जताया जा रहा है। चूंकि इस वक्त गांव का माहौल तनावपूर्ण है, ऐसे में अचानक यह वीडियो वायरल होना तनाव बढ़ा सकता है। पुलिस जांच रही है कि वीडियो कब का है। दूसरी ओर गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस तैनात है। सावन के चलते अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

> **इसलिए गांव में है तनाव**
> गांव में 150 हिंदू परिवार हैं, जबकि 450 मुस्लिम। हिंदू महिलाओं ने वीडियो वायरल कर आरोप लगाया था कि दूसरे समुदाय के लोग उन्हें मंदिर नहीं जाने दे रहे। ऐसा ही रहा तो वे गांव से पलायन कर जाएंगी। हालांकि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि गांव में मंदिर निर्माण कराया जा रहा था। दूसरे समुदाय ने शिकायत की थी, जिस पर निर्माण रोका गया। किसी भी धार्मिक आयोजन व पूजा-पाठ पर कोई रोक नहीं है। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी।

पीलीभीत में सड़क हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत

उत्तर प्रदेश में बरेली हाईवे पर रोडवेज बस की तेज रफ्तार ने शुक्रवार दोपहर एक परिवार के सात लोगों की जिंदगी छीन ली। पूर्णागिरी से दर्शन कर लौट रहे अलीगढ़ निवासी परिवार की कार में बस सीधे जा भिड़ी। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के सात लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद करीब दो घंटे तक बरेली-पीलीभीत हाईवे पर जाम लगा रहा।

दोपहर करीब दो बजे बरेली से टनकपुर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस तेज गति के कारण अनियंत्रित हुई और सामने से आ रही आल्टो कार में जा भिड़ी। हादसे में कार सवार अलीगढ़ निवासी राजीव कुमार, उनकी पत्नी सविता और एक वर्षीय पुत्री भक्ति, हृदेश, उनकी पत्नी पल्लवी और तीन वर्षीय पुत्री आराध्या के अलावा परिवार के एक अन्य सदस्य रिशांत की मौके पर मौत हो गई। हृदेश का एक वर्षीय बेटा उत्कर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क दुर्घटना के चलते बरेली-पीलीभीत हाईवे पर करीब दो घंटे तक जाम लग गया।

पीलीभीत में हादसे के बाद क्षतिग्रस्त ऑल्टो कार। जागरण

कांवड़ियों की संख्या बढ़ते ही दिल्ली-देहरादून हाईवे बंद

जागरण संवाददाता, मेरठ : कांवड़ियों की संख्या बढ़ते ही शुक्रवार को दिल्ली-देहरादून हाईवे आम वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। पहले दिन हाईवे पर पहुंचे इक्का-दुक्का वाहनों को पुलिस ने किसी तरह निकाला। अब इस हाईवे पर एक तरफ कांवड़िये चलेंगे और दूसरी तरफ सिर्फ कांवड़ पास वाले वाहनों को निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर पास वाले वाहन भी रोके जा सकते हैं। एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी ने बताया कि दिल्ली से देहरादून जाने वाले वाहनों के लिए हाईवे को बंद कर वैकल्पिक मार्ग दिया गया है, जिससे वाहन जा सकेंगे। हाईवे पर सामान्य यातायात तीस जुलाई की रात 12 बजे के बाद बहाल होने की उम्मीद है। दूध, ब्रेड, एवं सब्जी आदि के हल्के चार पहिया सप्लाई वाहनों को कांवड़ के पास जारी किए गए हैं।

आज से चार दिन बंद रहेगा लखनऊ-गोरखपुर हाईवे : अयोध्या: अयोध्या में शनिवार से कांवड़ियों की भीड़ बढ़ेगी। इसी को देखते हुए शुक्रवार मध्यरात्रि से लखनऊ-गोरखपुर नेशनल हाईवे-28 और अयोध्या-अंबेडकरनगर स्टेट हाईवे पर चार दिन यानी 30 जुलाई तक सामान्य वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।

रिहायशी बिल्डिंग में आग...

अहमदाबाद के जगतपुर के समीप बहुमंजिली इमारत की छठी मंजिल में शुक्रवार को एसी का कंप्रेशर फटने से आग लग गई। इमारत में फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि एक महिला की मौत होने की सूचना है। प्रेट्र

आतंक पीड़ितों के बच्चों के आरक्षण पर अधिसूचना जारी करे पंजाब : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- मेडिकल के विद्यार्थियों की याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने जारी किए संक्षिप्त आदेश
- निजी और गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में देना होगा एक फीसद आरक्षण

पंजाब में निजी और गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल संस्थानों में आतंक पीड़ितों के बच्चों को एक फीसद आरक्षण पर स्पष्टता लाने के आदेश देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार इस पर नई अधिसूचना जारी करे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश को लेकर हाई कोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं पर संक्षिप्त आदेश जारी करते हुए जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने कहा है कि इन याचिकाओं पर विस्तृत आदेश लिखवाने में समय लगेगा इसलिए इन मामलों के महत्व को देखते हुए अदालत अपने संक्षिप्त निर्देश जारी कर रही है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने आतंक पीड़ितों के बच्चों को एक फीसद आरक्षण देते हुए स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण मैनेजमेंट कोटा की सीटों पर भी मान्य होगा।

इसके साथ नई अधिसूचना में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में खिलाड़ियों को तीन फीसद आरक्षण देने के आदेश भी दिए। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन में किसी विद्यार्थी के पास समान ग्रेड होने पर उसके नीट के अंकों को मेरिट का आधार बनाने के आदेश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से आर्थिक तौर से कमजोर छात्रों को दिए गए 10 फीसद आरक्षण को भी स्वीकार किया है।

गौरतलब है कि आतंक पीड़ितों के बच्चों को सिर्फ सरकारी मेडिकल संस्थानों में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ कुछ विद्यार्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि निजी संस्थानों में भी आतंक पीड़ितों के बच्चों और पौत्रों को आरक्षण मिलेगा। इन याचिकाओं पर सुनवाई के चलते ही बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू नहीं हो पाई थी।

> **दाखिला न मिलने पर पीड़ित पहुंचे थे कोर्ट**
> गौरतलब है कि हाई कोर्ट पहुंची इन याचिकाओं में से एक में कहा गया था कि आतंक पीड़ित व्यक्ति के बच्चों या पोत्रों को मेडिकल कोर्स में मिलने वाला एक फीसद आरक्षण सिर्फ सरकारी कॉलेजों में सीमित कर दिया गया है और निजी कॉलेजों में यह आरक्षण लागू नहीं किया गया है। एक अन्य याचिका में पंजाब में खिलाड़ियों को मेडिकल संस्थानों में एक फीसद आरक्षण दिए जाने को चुनौती देते हुए कहा गया था कि राज्य की खेल नीति में खिलाड़ियों को तीन फीसद आरक्षण देने की बात कही गई है।

चिंताजनक

> छत्तीसगढ़ में 454 करोड़ खर्च करने बाद भी सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, बिलासपुर में मिले सर्वाधिक 35 हजार कुपोषित बच्चे

करोड़ों का पोषण फिर भी पांच लाख बच्चे कुपोषित

संजीत कुमार, रायपुर

छत्तीसगढ़ के पांच लाख नौनिहाल कुपोषण का शिकार हैं। यह स्थिति तब है, जबकि राज्य सरकार ने बच्चों को सुपोषित करने के लिए एक वर्ष में करीब 454 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया है। बिलासपुर में कुपोषण का आंकड़ा सर्वाधिक है। वहां 35 हजार से अधिक बच्चे कुपोषित मिले हैं। इनमें 102 विशेष संरक्षित जनजाति (पहाड़ी कोरवा) बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि जनसंख्या की तुलना में कुपोषित बच्चों का औसत राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में अधिक है।

राज्य में फरवरी 2019 में हुए वजन त्योहार से यह आंकड़ा निकलकर आया है। सरकार ने कुपोषण की जांच के लिए वजन त्योहार का आयोजन करती है। वर्ष 2018-19 में फरवरी 2019 में आयोजित वजन त्योहार के दौरान राज्य में कुल चार लाख 92 हजार 176 बच्चे कुपोषित मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार ने कुपोषण मुक्ति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर 454 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इनमें अकेले पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 40 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है।

कुपोषण में दूसरे नंबर पर पूर्व सीएम का निर्वाचन जिला : वजन त्योहार के आधार पर तैयार कुपोषण की रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर के बाद सर्वाधिक 32 हजार कुपोषित बच्चे पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने निर्वाचन जिले राजनांदगांव में हैं। तीसरे नंबर बलौदाबाजार में 29737, चौथे नंबर पर रायगढ़ में 24759 और रायपुर में 28683 कुपोषित बच्चे मिले हैं।

आबादी के अनुमान में वनांचलों की स्थिति खराब : आंकड़ों के लिहाज से भले ही मैदानी जिलों में कुपोषित बच्चों की संख्या अधिक है, लेकिन आबादी के लिहाज से आदिवासी क्षेत्रों में हालात ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों की संख्या वाले बिलासपुर में 2011 की जनगणना के हिसाब से कुपोषण का औसत 1.79 है, जबकि सातवें स्थान पर स्थित आदिवासी जिला बस्तर में यह आंकड़ा 2.91 का आता है।

> **राज्य में 38 और आदिवासी क्षेत्र में 44 फीसद कुपोषण**
> छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 38 फीसद है, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 44 फीसद है। महिला बाल विकास विभाग के अफसरों के अनुसार इसी एक बड़ी वजह यह है कि वनांचलन के बड़े हिस्से में आज भी सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं।

जनसंख्या की तुलना में कुपोषित बच्चों का औसत राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में अधिक है। (फाइल फोटो)

कश्मीर में पबजी गेम ने ले ली युवक की जान

जागरण संवाददाता, श्रीनगर

- अपने दोस्त के घर रुककर देर रात तक खेल रहा था गेम
- कई राज्यों की सरकारों ने इस गेम को किया है प्रतिबंधित

भारत के कई राज्यों में प्रतिबंधित पबजी गेम ने कश्मीर में पहली बार एक युवक की जान ले ली। मृतक की पहचान 19 वर्षीय आसिम बशीर पुत्र बशीर अहमद निवासी बागात कनीपोरा, श्रीनगर के रूप में हुई है।

आसिम गुरुवार को अपने दोस्त शोएब असलम पुत्र मोहम्मद असलम के मेथन छानपोरा स्थित घर में रुका था। शोएब और उसके परिजनों के अनुसार आसिम ने यहां आते ही अपने मोबाइल पर पबजी गेम खेलना शुरू कर दिया। वह खेल में इतना मशगूल था कि रात का खाना भी काफी कहने पर खाया। इसके बाद वह फिर से गेम खेलने लगा।

शोएब के अनुसार, आसिम मेरे साथ ही कमरे में सोने गया। हम दोनों रात 12:30 बजे तक जाग रहे थे। इसके बाद मुझे नींद आ गई। मैंने आसिम से भी कहा कि वह मोबाइल बंद कर सो जाए। जवाब में आसिम ने कहा कि वह थोड़ी देर बाद सो जाएगा।

शोएब ने बताया कि मैं सुबह जाग गया, लेकिन आसिम सो रहा था। मुझे लगा कि रात में देर तक जागने से आसिम की आंख नहीं खुल रही है। इसके बाद मैं नाश्ता करने चला गया। बहुत देर बाद भी जब आसिम नहीं जागा तो उसके घरवालों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह अचेत अवस्था में था। इस पर उसे तत्काल पास के निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत लाया घोषित कर दिया। गौरतलब है कि वादी में पहली बार पबजी खेल के दौरान किसी की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन शुरू कर दी है।

सर्पदंश से दो छात्राओं की मौत

नईदुनिया, जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले के एक प्राथमिक स्कूल के कक्षा कक्ष में विषैले सांप ने दो छात्राओं को डस लिया। स्कूल की शिक्षिका ने उनका इलाज कराने के बजाय उन्हें घर भेज दिया। घर पहुंची छात्राओं की मौत हो गई। इस मामले में कलेक्टर ने प्रधानाध्यापक व शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।

जनमत मुद्दा

क्या जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहां वे भी अल्पसंख्यकों की सहूलियतों-सुविधाओं के हकदार हैं?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

Downloaded from: www.iascgl.com

दैनिक जागरण

सब कुछ लुट जाने पर भी भविष्य बाकी रहता है

जल्दबाजी का आरोप

राज्यसभा में कुछ विपक्षी दलों के सहयोग से सूचना अधिकार संबंधी संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विपक्ष के 17 सांसदों की ओर से इस सदन के सभापति को लिखी गई इस चिट्ठी का औचित्य समझना कठिन है कि सरकार विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि यह चिट्ठी ऐसे समय आई जब संसद के मौजूदा सत्र को इसलिए बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्य किया जा सके। ऐसा लगता है कि राज्यसभा सभापति को चिट्ठी लिखने वाले सांसद इससे परेशान हैं कि सूचना अधिकार संबंधी विधेयक पर कई विपक्षी दल सत्तापक्ष के साथ खड़े हो गए। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं। अतीत में कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी विधेयक पर विपक्षी दल एकमत न रहने के कारण एकजुट भी नहीं रहे। किसी विधेयक पर विपक्षी एकता कायम न रहने का यह मतलब नहीं कि विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है अथवा सरकार विधेयकों को पारित कराने में जल्दबाजी कर रही है। 17 विपक्षी सांसदों को यह शिकायत है कि सरकार विधेयकों को प्रवर समिति के पास नहीं भेज रही है। निःसंदेह व्यापक महत्व के विधेयक प्रवर समितियों के पास भेजने की परंपरा है, लेकिन यह कोई नियम भी नहीं है कि हर विधेयक को प्रवर समिति के हवाले किया जाए।

कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाए या नहीं, इसका निर्धारण सदन की सहमति से ही होता है। यदि विपक्ष यह चाहेगा कि हर विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाए तो यह संभव नहीं। ऐसा तभी संभव होगा जब विपक्ष का संख्याबल मजबूत होगा। विपक्षी सांसदों को यह स्मरण रहना चाहिए कि अतीत में ऐसा भी समय रहा जब कांग्रेस का लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी बहुमत रहा। इसी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में राज्यसभा में विपक्षी दल अपने बहुमत के बल पर लोकसभा से पारित विधेयकों की राह रोकते दिखे हैं। विपक्षी दलों के इसी रवैये के कारण राष्ट्रीय महत्व के कई ऐसे विधेयक फिर से पारित कराने पड़ रहे हैं जो पिछली लोकसभा से तो पारित हो गए थे, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सके थे। अगर तत्काल तीन तलाक संबंधी विधेयक को लोकसभा से तीसरी बार पारित कराना पड़ा तो राज्यसभा में विपक्षी दलों के रवैये के कारण ही। विपक्षी नेताओं को तब शिकायत हो सकती है और होनी भी चाहिए जब उन्हें अपनी बात कहने या फिर विधेयकों के मसौदे के अध्ययन का पर्याप्त समय न मिले। यह अच्छा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयकों का मसौदा मिलने में देरी का संज्ञान लिया।

बम बांधकर पशु तस्करी

पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में पशुओं, खासकर गाय की तस्करी आज से नहीं, बल्कि दशकों से चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में पशु तस्करी रोकने को लेकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद अब बांग्लादेशी पशु तस्करों ने खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। 'तुम डाल-डाल, हम पात-पात' वाली कहावत इन दिनों बांग्लादेश की सीमा पर चरितार्थ हो रही है। बारिश के मौसम में उफनती नदियों के जरिए तस्करों ने पशुओं की बांग्लादेश में तस्करी शुरू कर दी है। गायों के शरीर पर केले के पत्ते बांधकर उन्हें नदियों में छोड़ दे रहे थे। इस पर जब बीएसएफ ने कार्रवाई शुरू की तो अब तस्करों ने गायों के गले में केले के पत्ते के साथ बम बांधना शुरू किया, ताकि सीमा सुरक्षा बल के जवान उन्हें पकड़ने जाएं तो बम विस्फोट हो जाए और गायों के साथ जवान भी मारे जाए। ये सॉकेट बम काफी शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनमें लोहे के टुकड़ों से लेकर स्पलिंटर और अन्य घातक तत्व मौजूद होते हैं, जिनकी चपेट में आने पर एक साथ कई लोगों की जानें जा सकती हैं। यानी अब गायों के साथ-साथ बमों की भी तस्करी होने लगी है। इसमें आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन (बांग्लादेश) का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि बर्द्धमान के खागड़ागढ़ में जब बम धमाके हुए थे, तब पता चला था कि यहां से बम तैयार कर बांग्लादेश भेजा जा रहा था। उसके पीछे जेएमबी का हाथ था। हालांकि किसी अप्रिय घटना से पहले ही सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेशी पशु तस्करों के इस खतरनाक खेल का भंडाफोड़ कर दिया है। इससे पहले गाय तस्करों ने कार्रवाई करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर बमों से हमला किया था। कुछ दिन पहले एक बीएसएफ जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। उसका एक हाथ बम से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उससे पहले दो जवानों की तस्करों द्वारा फेंके गए बम से मौत भी हो चुकी है। अब यह मामला सामने आया है। बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने एक दिन पहले देर रात को सर्च ऑपरेशन चलाकर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों के विभिन्न स्थानों से सीमा पार भेजे जा रहे 365 मवेशियों को जब्त किया। सीमा सुरक्षा बल ही नहीं, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की पुलिस को भी सक्रिय होना होगा कि आखिर इन तस्करों को गाय समेत अन्य मवेशी कहां से मिल रहे हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

राजनीतिक नेतृत्व का नया अध्याय

डॉ. एके वर्मा

हमारे राजनीतिक दलों को यह समझना ही होगा कि विचारधारा और सक्षम नेतृत्व के बिना उनका काम चलने वाला नहीं है

देश की राजनीति में नेतृत्व को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ सा लगता है। कांग्रेस में बहुत दिन के बाद नेहरू-गांधी वंश के नेतृत्व के अंत की संभावना उभरी है। भाजपा में अटल-अडवाणी-जोशी के नेतृत्व का भी अंत हुआ और नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में भाजपा नई ऊंचाइयों को छू रही है। क्षेत्रीय पार्टियों में तमिलनाडु में द्रमुक के करुणानिधि और अन्नाद्रमुक की जयललिता, बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बंगाल में ज्योतिबसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य आदि का अंत या पराभव हो चुका है। कांशीराम के बाद बसपा भी कमजोर हो गई है और मायावती का राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में शिवसेना और आंध्र में तेलुगु-देसम पार्टी सहित अन्य अनेक क्षेत्रीय दलों का भी दिखता है, लेकिन यदि इन सभी का विश्लेषण करें तो भाजपा और वामपंथी दलों को छोड़ कर अन्य सभी दल व्यक्ति या वंश केंद्रित रहे हैं।

वामपंथी विचारधारा को देश ने कभी स्वीकार किया नहीं और इसीलिए वह काफी समय तक बंगाल, त्रिपुरा और केरल तक सिमटी रही और अब तो बंगाल और त्रिपुरा में भी उसका वर्चस्व समाप्त हो गया है। विचारधारा के स्तर पर भाजपा ही एक मात्र राजनीतिक दल शेष है जिसका राजनीतिक अस्तित्व सबल है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक विचारधारा और नेतृत्व की त्रासदी है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना तक कांग्रेस की विचारधारा का प्रमुख तत्व स्वाधीनता और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना था, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर सामाजिक एकता की स्थापना का लक्ष्य था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता गांधीजी और पटेल के शीघ्र निधन और कांग्रेस से आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और डॉ. लोहिया के अलग होने के बाद पार्टी की पकड़ विचारधारा पर कमजोर होती गई और कांग्रेस नेहरू-केंद्रित होती गई, जिसने कालांतर में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया और राहुल गांधी को जैसे पार्टी नेतृत्व का एकाधिकार सौंप दिया। अन्य दलों का तो कहना ही क्या? उन्होंने विचारधारा का मुखौटा लगा व्यक्ति केंद्रित दलों का निर्माण किया। अब जब इनके नेताओं का पराभव हो चुका है तो वे असमंजस की स्थिति में हैं। विचारधारा है नहीं, नेतृत्व बचा नहीं तो दलीय संगठन कैसे अक्षुण्ण रहे? इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें जर्मन विद्वान मैक्स वेबर के नेतृत्व के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। वेबर ने तीन प्रकार के नेतृत्व की परिकल्पना की थी-करिश्माई नेतृत्व, परंपरागत नेतृत्व और विधिक-बौद्धिक नेतृत्व। करिश्माई नेतृत्व चुंबकीय व्यक्तित्व चाहता है और उसके इर्द-गिर्द का संगठन तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक नेतृत्व का करिश्मा बना रहता है। नेहरू और इंदिरा का करिश्माई व्यक्तित्व था, पर दुर्भाग्य से इंदिरा के बाद नेहरू-गांधी वंश के नेतृत्व में वह चुबंकीय तत्व दिखा नहीं जिससे धीरे-धीरे कांग्रेस संगठन का ह्रास होने लगा।

अवधेश राजपूत

कांग्रेस में नेतृत्व करिश्माई से परंपरावादी हो गया, जिसमें नेतृत्व से निष्ठा केवल इस आधार पर होती है कि हमारे पूर्वज भी नेतृत्व देने वालों के पूर्वजों से निष्ठा रखते थे। ऐसा नेतृत्व सामंतवादी व्यवस्था में होता है। कांग्रेस अपने सामंतवादी नेतृत्व को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग के अनुरूप नहीं रख सकी, जिसे विधिक-बौद्धिक नेतृत्व की तलाश थी। इसमें व्यक्ति या वंश के आधार पर नहीं वरन योग्यता के आधार पर नेतृत्व की रचना की जाती है। अन्य सभी दलों का भी यही हाल रहा।

यह विडंबना ही है कि राजनीतिक व्यवस्था हम लोकतांत्रिक चाहते हैं और दलीय व्यवस्था का स्वरूप सामंतवादी रखना चाहते हैं। यह अंतर्विरोध आज हमारी राजनीति की केंद्रीय समस्या है और सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक दूरगामी नीति अपनानी होगी, अन्यथा वे एक ऐसे भंवर में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग बचेगा नहीं। संभवतः राहुल गांधी का पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र इसी का संकेत है और सभी दलों से भाजपा की ओर पलायन इसका परिणाम।

प्रत्येक समस्या में ही समाधान भी छिपा रहता है। यदि राजनीतिक पार्टियां अब भी मैक्स वेबर के विधिक-बौद्धिक मॉडल को स्वीकार कर लें और दलीय नेतृत्व को लोकतांत्रिक शैली में योग्यता के आधार पर संगठित करें तो अब भी देश में लोकतांत्रिक राजनीति की दिशा और दशा, दोनों बदल सकती है। सभी पार्टियों के पास योग्य लोग हैं। जरूरत केवल एक संकल्प, दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदृष्टि की है, लेकिन केवल नेतृत्व से ही काम नहीं चलने वाला। जरूरत तो विचारधारा की भी पड़ेगी। आज कांग्रेस और कांग्रेसजनों को अपनी विचारधारा का ही पता नहीं। अन्य कोई दल भी अपनी विचारधारा को आगे नहीं रखना चाहता। वह तो केवल उसे एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहता है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक कोई भी विचारधारा के बारे में न तो जानता है और न ही उस पर अमल करना चाहता है। स्पष्ट है कि सभी दलों को इस पर गंभीर मंथन करना चाहिए कि उनकी विचारधारा है क्या? क्या वर्तमान संदर्भों में उसकी कोई जन-स्वीकार्यता है भी? उसे कैसे आज के समाज और समस्याओं से जोड़ा जाए और उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं?

स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की विचारधारा से पूरा देश जुड़ा था, जिससे उसकी जन-स्वीकार्यता पर कोई प्रश्नचिन्ह ही नहीं था। इससे काफी समय तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा जिसे भारतीय राजनीतिक विद्वान रजनी कोठारी ने 'कांग्रेस-सिस्टम' का नाम दिया। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने भी अपनी विचारधारा को विकास और समावेशी राजनीति से आबद्ध कर कुछ ऐसी ही जन-स्वीकार्यता हासिल कर ली है जिससे देश 'भाजपा-सिस्टम' की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हाल के लोकसभा चुनावों में 17-18 राज्यों में भाजपा को कैसे 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं का समर्थन मिल पाता? भाजपा के पास विचारधारा और नेतृत्व दोनों हैं और दोनों को जनता का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भाजपा सदैव ही सत्ता में रहेगी। आगे चल कर कोई और पार्टी उसका स्थान ग्रहण कर सकती है, पर अगर विभिन्न दलों के द्वारा इसकी समुचित तैयारी नहीं की गई तो नतीजा सिफर ही रहेगा। अब समय आ गया है कि विचारधारा और नेतृत्व को केंद्र में रख कर 'प्रोफेशनल' तरीके से पंचायत से संसद तक के लिए राजनीतिक-पर्यावरण का निर्माण किया जाए जिससे देश की लोकतांत्रिक संस्कृति, लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ हो सके और उसका लाभ देश, समाज और आम नागरिक को मिल सके।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

संघ लोक सेवा आयोग की हिंदी

डॉ. विजय अग्रवाल

आज हर कोई 'सर्जिकल स्ट्राइक' शब्द से परिचित है, पर सिविल सेवा के प्रश्न पत्र में इसे 'शल्यक प्रहार' लिखा जा रहा है

कृपया इस वाक्य को ध्यान से पढ़ें-भारत में संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विस्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिरोध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। ये दो वाक्य भी देखेंः पहला-'वार्महोल' से होते हुए अंतरा-मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। दूसरा-यूएनसीएसी अब तक का सबसे पहला विधितः बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार विरोधी लिखत है। क्या आप इन वाक्यों को समझ सके? ये हैं क्या? ये सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछे गए प्रश्नों की हिंदी भाषा के कुछ नमूने हैं। मूल प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तैयार होता है और उसी प्रश्न के नीचे उसका हिंदी अनुवाद दिया जाता है यानी यह 'अनुदित हिंदी' है।

अब मैं आता हूं मूल समस्या पर। आइएएस बनने के लिए आपको 200 अंकों वाले सौ प्रश्नों के सामान्य अध्ययन के पेपर में सामान्यतया 100 अंक लाने ही होते हैं। परीक्षा में कुल लगभग 5-6 लाख युवा बैठते हैं, जिनमें से 10-12 हजार का चयन होना होता है। इन आंकड़ों से आप इस तथ्य का अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि 0.01 अंक का भी कितना अधिक महत्व होता होगा। दूसरी बात यह कि परीक्षार्थी को 120 मिनट में 100 प्रश्न हल करने होते हैं। यदि उसका उत्तर गलत हुआ तो दंड के बतौर उसके नंबर काट लिए जाते हैं यानी यहां उसके सामने चुनौती यह भी है कि वह प्रश्नों को तेजी से समझे और सही-सही समझे। नहीं तो लेने की जगह देने पड़ जाएंगे। इस पृष्ठभूमि में आप हिंदी और अन्य भारतीय भाषा के माध्यम वाले परीक्षार्थियों की समस्या और उनके सामने प्रस्तुत उस भयावह संकट पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करें, जो 'अनुदित हिंदी' ने खड़ा कर दिया है। सौ प्रश्नों में से प्रतिवर्ष औसतन आठ-दस प्रश्न ऐसे होते ही हैं, जो इस तरह की अबूझ, क्लिष्ट एवं अव्यावहारिक हिंदी से सुसज्जित होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं प्रश्नों को अंग्रेजी में आसानी से समझा जाता है। ऐसी हिंदी के कारण परिणाम यह हो रहा है कि 2011 से पहले तक प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी माध्यम से सफल होने वाले प्रतियोगियों का प्रतिशत जहां 40 से भी अधिक था, वहीं अब गिरकर 10-12 प्रतिशत के आसपास आ गया है। स्वाभाविक है कि जब प्रारंभिक परीक्षा में ही हिंदी वाले बाहर हो गए हैं तो अंतिम चयन सूची में उनकी उपस्थिति अपने-आप दाल में नमक की तरह रह जाएगी। कुछ बुद्धिजीवियों और नीति-निर्माता प्रशासकों द्वारा इसे हिंदी वालों की अयोग्यता-अक्षमता का प्रमाण घोषित कर दिया जाता है।

यह भाषाई अन्याय केवल हिंदी वालों के साथ ही नहीं, बल्कि उन सभी भारतीय भाषाओं के युवाओं के साथ भी हो रहा है, जो स्वयं को माध्यम के रूप में अंग्रेजी लेने की स्थिति में नहीं पाते। सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र केवल दो ही भाषाओं में छपते हैं-अंग्रेजी और हिंदी में। स्पष्ट है कि प्रश्नों को समझने के लिए गैर हिंदीभाषी भी हिंदी भाषा का ही सहारा लेते हैं। यदि उन्हें अंग्रेजी आ रही होती तो वे उसे ही अपना माध्यम बना लेते। साफ है कि बड़ी चालाकी से उन्हें भी प्रारंभिक स्तर पर ही बाहर कर दिया जा रहा है। जहां तक मुख्य परीक्षा की हिंदी का प्रश्न है, उसमें स्थिति उतनी बुरी नहीं है, फिर भी ऐसे कई शब्दों की भरमार देखने को मिलती है, जिनसे हिंदीभाषियों की भेंट नहीं होती है। आज आम आदमी 'सर्जिकल स्ट्राइक' शब्द से परिचित हो चुका है, लेकिन सिविल सेवा का पेपर इसे 'शल्यक प्रहार' लिखता है। अंकीयकृत प्रजनक, विधीयन, प्रोत्कर्ष, प्रमात्रा, प्रवसन जैसे अनेक ऐसे शब्दों को चुन-चुनकर लाया जाता है, जो समझ से परे हों।

हिंदी में 'डिजिटलीकरण' के लिए पता नहीं क्यों संघ लोक सेवा आयोग को 'अंकीयकृत' शब्द अधिक अच्छा लगता है। यूपीएससी का अनुवादक अंग्रेजी के एक ही शब्द के लिए अलग-अलग जगहों पर हिंदी के अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे 'मैनडेटरी' के लिए कहीं अनिवार्य, कहीं अधिदेशित तो कहीं आज्ञापरख। यदि आप 'साइंटिस्ट ऑबजर्ब्ड' को हिंदी में 'वैज्ञानिकों ने प्रेक्षण किया' लिखेंगे तो थोड़ी देर के लिए हिंदी वाला सहमेगा ही। साफ है कि संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में अनुवाद को लेकर बहुत ही उपेक्षापूर्ण रुख धारण किए हुए है। उसमें न तो हिंदी भाषा के प्रति कोई दायित्वबोध दिखाई दे रहा है और न ही संवेदनशीलता, बल्कि उसकी इस भाषाई गतिविधि ने जाने-अनजाने हिंदी वाले के लिए इस परीक्षा को दुरूह बना दिया है। इस बात को लेकर गैर अंग्रेजीभाषियों में न केवल खदबदाहट है, बल्कि आक्रोश भी है। इस अन्याय को जल्दी से जल्दी दूर किए जाने की सख्त आवश्यकता है। यह कोई नीतिगत मामला नहीं है।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

विश्व की चहेती हस्तियां

(वर्ष 2019 में लोगों की पसंद का प्रतिशत)

स्रोत : yougov.com

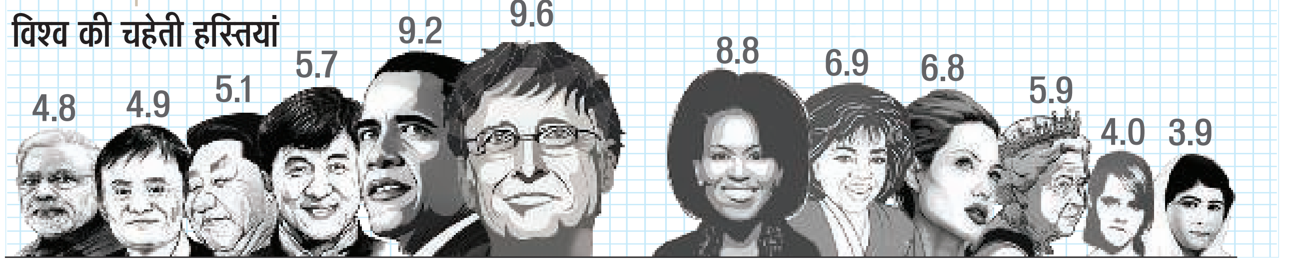

ऊर्जा

जीवन दृष्टि

सकारात्मकता नैतिक साहस को बढ़ाती है। हमें जीवन को नए आयाम देने और कुछ हटकर करने के लिए अपना नजरिया बदलना होगा। अंधेरों से लड़ने के लिए गली और मोहल्ले के हर मुहाने पर नन्हें-नन्हें दीपक जलाने होंगे। साहसी फैसला लेने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जीवन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आप स्थिति का सही विश्लेषण करके उसके संदर्भ में सही पृष्ठभूमि बनाएं। हम जो भी महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहे हैं, यदि उनके संदर्भ में हमें पृष्ठभूमि की सही जानकारी नहीं है तो हमारे कार्य करने की दिशा गलत हो सकती है। गांधी जी ने अपनी बात को कहने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसकर अपने अनुभव के आधार पर पुष्ट किया, उसके बाद उसे सही पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार की आलोचना करते हुए भी, उन पर सीधा प्रहार करने के स्थान पर पहले अपनी बात के समर्थन में सही पृष्ठभूमि निर्मित की। फिर उसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया।

एक सफल जीवन का निर्वाह करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर ऐसे गुणों का विकास करें, जिनके द्वारा सभी को एक साथ लेकर चलने की कला में दक्षता प्राप्त कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं को तैयार करना होगा। जब तक हम दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दूसरे भी हमारे प्रति आदर का भाव नहीं रखेंगे। मानवीय गुणों के विकास के बिना आप अपने आपको समाज में प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते। समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके विरोधी न हों। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हम अपने कार्यों के द्वारा समर्थक अधिक बना रहे हैं या विरोधी। जिंदगी को एक ढर्रे में नहीं, बल्कि स्वतंत्र पहचान के साथ जीना चाहिए। जब तक जिंदगी है, जिंदादिली के साथ जीना जरूरी है। बिना उत्साह के जिंदगी मौत से पहले मर जाने के समान है। उत्साह और इच्छा व्यक्ति को साधारण से असाधारण की तरफ ले जाती है। जिस तरह सिर्फ एक डिग्री के फर्क से पानी भाप बन जाता है और भाप बड़े-से-बड़े इंजन को खींच सकती है, उसी तरह उत्साह हमारी जिंदगी के लिए काम करता है। इसी उत्साह से व्यक्ति को सकारात्मक जीवन-दृष्टि प्राप्त होती है।

बेला गर्ग

बाहर का खाना खाने का बढ़ता ट्रेंड

सौरभ सिंह

हमारे खानपान में आए इस बदलाव की एक वजह हमारी आधुनिक जीवनशैली और शहरीकरण भी है

हाल ही में जारी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआइ) के एक सर्वे के मुताबिक भारत में लोग महीने में औसतन 6.6 बार बाहर खाने जाते हैं या बाहर का खाना घर मंगवाते हैं। हालांकि कई एशियाई देशों के मुकाबले में यह आंकड़ा अब भी काफी कम है। पड़ोसी देश सिंगापुर में तो यह औसत 30 पर पहुंच गया है। एशिया के कुछ शहरों की बात करें तो बैंकॉक में यह आंकड़ा 45 और शांघाई में 60 है। जाहिर है, बाहर का खाना खाने का ट्रेंड भारत में नया है, लेकिन इसके बढ़ने की गति काफी तेज है। सर्वे के अनुसार बाहर के खाने पर एक भारतीय परिवार महीने में औसतन 2500 रुपये खर्च करता है। खाने को लेकर भारतीयों की बदलती रुचि के कारण देश में फूड इंडस्ट्री का आकार भी लगातार बढ़ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में यह इंडस्ट्री सबसे ज्यादा संगठित है, जहां इसका कारोबार 41,000 करोड़ रुपये तक चला गया है। दिल्ली में यह आंकड़ा 31,132 करोड़ तो बेंगलुरु में 20,014 करोड़ पर पहुंच गया है। लोगों के सामने आज खाने के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। वे घर बैठे विभिन्न तरह के खान-पान का आनंद उठा रहे हैं।

एनआरएआइ के सर्वे से यह बात सामने आई है कि मुंबई के लोग दक्षिण भारतीय खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा 33 फीसद लोग इटैलियन, जबकि 29 प्रतिशत चाइनीज खाने की मांग करते हैं। दिलचस्प बात यह कि दक्षिण भारतीय लोग उत्तर भारत के व्यंजन ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि दिल्ली के लोगों की रुचि स्थानीय खाने में अधिक है। समूचे भारत में देखें तो उत्तर भारतीय खानों (41 प्रतिशत) की सबसे ज्यादा मांग है। उसके बाद चाइनीज (27 प्रतिशत), दक्षिण भारतीय (27 प्रतिशत), मुगलई (22 प्रतिशत) और इटैलियन (16 प्रतिशत) की मांग है। इस सर्वे रिपोर्ट से एक बात साफ हो जाती है कि हमारी खानपान की आदतों में काफी तेजी से बदलाव आ रहा है। अब लोग पूरे दिन घर में चूल्हा के सामने बैठे रहने और घर का खाना खाने के बजाय रेस्टोरेंट में बने खाने ज्यादा खाने लगे हैं। इस तरह वे या तो रेस्तरां में जाकर खाते हैं या घर बैठे तमाम तरह के फूड-एप के जरिए खाना मंगवा ले रहे हैं।

हमारे खानपान में आए इस बदलाव की एक वजह हमारी आधुनिक जीवनशैली और शहरीकरण भी है। बदलते समय में समाज में अब कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी हैं। इसके साथ ही शहरीकरण के चलते एकल परिवारों का चलन तेजी से बढ़ा है। जाहिर है जब महिलाएं भी पुरुषों की तरह बाहरी काम-काज में जुट गई हैं तो दोनों के पास घर में खाना बनाने का समय नहीं ही रहेगा। ऐसे में बाहर के खाने पर निर्भरता बढ़ना वाजिब है। परिवार की आय बढ़ने से उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ी है। लिहाजा वे खाने पर पहले की तुलना में ज्यादा खर्च करने में संकोच भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उनकी शरीर की जरूरतों से लेकर स्वाद की प्राथमिकता भी पूरी हो जा रही है। इसकी पूर्ति करने के लिए सूचना तकनीक इसमें अपने तरीके से योगदान दे रही है। नए-नए एप आ रहे हैं जिनसे लोगों को अपनी पसंद का खाना जल्दी मंगवाना मुमकिन हो गया है।

(लेखका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

कारगिल एक थोपा हुआ युद्ध

कारगिल संघर्ष के सही सबक शीर्षक से लिखे अपने लेख में सी उदयभास्कर ने पाक द्वारा थोपे गए कारगिल युद्ध के पीछे की कमजोरियों पर नए सिरे से विचार करने की जिस जरूरत पर बल दिया है, वह सर्वथा उचित है। भारत ने भले ही अपने पड़ोसी देशों पर हमला न किया हो, लेकिन वह 1948 से लेकर अब तक अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की साजिशों का शिकार होता रहा है। भारत पर थोपा गया कारगिल युद्ध पाकिस्तानी साजिश का ही परिणाम था। विषम स्थितियों में लड़े गए इस युद्ध में भारत को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। इस दृष्टि से कारगिल जैसी साजिशों से बचने के लिए जिन कारगर उपायों की जरूरत थी, वे अभी तक नहीं हुए हैं। यद्यपि भारत से हुए आमने-सामने के युद्धों में पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है। बावजूद इसके वह अपनी साजिशों से बाज नहीं आया और कश्मीर घाटी की आजादी की ओट में उसने आतंकवाद के जरिये भारत से छद्म-युद्ध छेड़ दिया, जो आज भी जारी है। भारत चाहता तो पिछले तीन दशकों से जारी इस आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर सकता था, लेकिन अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की कुत्सित राजनीति के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका। दूसरी ओर पाक समर्थित आतंकी सरगनाओं ने इसे भारत की कमजोरी मानकर एक के बाद एक आतंकी हमले जारी रखे। 2014 के बाद पहली बार मोदी सरकार ने उड़ी आतंकी हमले के प्रतिकार स्वरूप पीओके में घुसकर पाक पोषित आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद किया था। उसके बाद पुलवामा आतंकी हमले के प्रतिकार स्वरूप बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक से पहली बार पाकिस्तान दहशत में आया था। पाक द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की 24 घंटे में सकुशल वापसी इसी दहशत का प्रतिफलन थी। अब भारत को ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है कि पाकिस्तान पर यह दहशत बरकरार रहे। इसके लिए चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ पाकिस्तान की हर साजिश को बेनकाब करना जरूरी है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

पीड़ितों को मिले लाभ

आखिरकार सत्तारूढ़ भाजपा ने तत्काल तीन तलाक का बिल लोकसभा में तो पास करवा लिया, लेकिन अभी असली लड़ाई राज्यसभा में होनी बाकी है जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है। इसके पहले भी दो बार लोकसभा में यह बिल पास किया जा चुका है, लेकिन यह राज्यसभा में जाकर धड़ाम हो जाता है। अगर यह राज्यसभा से पास होने में सफल हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बन जाएगा और कानून बनने से सबसे बड़ा फायदा तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को होगा जो पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवा कर भी न्याय की तलाश में भटकती रहती हैं।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

संयुक्त परिवार का महत्व

एकल परिवार प्रणाली ने बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है। यही कारण है कि आज लोग सोशल मीडिया पर दोस्त बना रहे हैं। लेकिन इनमें सच्चे दोस्त कितने हैं? कितने लोगों से अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं, हर किसी से तो नहीं? कितने लोगों को अपनी तकलीफ में मदद के लिए पूछ सकते हैं? तमाम समस्याओं से जूझ रहे लोग समस्या का निदान नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुधा तनाव के चलते तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि घर में बड़े-बुजुर्गों की उपस्थिति मात्र से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है, किंतु वर्तमान पीढ़ी शादी के बाद अन्य परिजनों के साथ रहना पसंद नहीं करती। भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम विचारधारा की रही है, जबकि एकांकी परिवार पाश्चात्य की देन है। संयुक्त परिवार की एकता में वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी जिंदगी की परेशानियों में भी साथ देकर, उसे दूर कर देती है। संयुक्त परिवार के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।

sonimohit895@gmail.com

जनता समझती है

भीड़ की हिंसा पर विभिन्न क्षेत्रों की 49 विशिष्ट विभूतियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जय श्री राम का नारा युद्ध जय घोष बन गया है। ऐसे आरोप सिर्फ और सिर्फ झूठ की पोटली हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव के समय मोदी को वोट ना देने की अपील की थी, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। वह सब समझती है।

बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

90 लाख आदिवासी देश भर में अनेक वजहों से अपने ही घरों से बेदखल किए जा चुके हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान या फिर आने वाले समय में उनके अपने ही घरों से बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है।

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

आजकल

सरकार को बदनाम करने की साजिश !

भीड़ की हिंसा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। इसलिए यदि देश की कुछ जानी-मानी हस्तियां इसे लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किंतु 49 लोगों के हस्ताक्षर वाला जो पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है वह इस श्रेणी का नहीं कि उसका समर्थन किया जाए। भाषा में पत्र भीड़ की हिंसा को रोकने की भावना वाला नहीं दिखता है। यह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को निशाना बनाने पर लक्षित है। जिसका हृदय भीड़ की हिंसा को लेकर विह्वल होगा उसकी भाषा बिल्कुल अलग होगी

देश भर में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इन घटनाओं को नियंत्रित करने के प्रयास में लगातार जुटी है। इन परिस्थितियों के बीच देश के एक खास वर्ग के चुनिंदा 49 लोगों के हस्ताक्षर से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे गए एक खत से इन लोगों की मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर होती है। सच कहा जाए तो भीड़ की हिंसा के बहाने राजनीति साधने की रणनीति है। इससे यह भी जाहिर होता है कि यह केंद्र सरकार को बदनाम करने की एक साजिश भी है। और जब आप किसी गंभीर सामाजिक या कानून-व्यवस्था के प्रश्न पर राजनीतिक नजरिये से कुछ लिखेंगे और बोलेंगे तो उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक आएंगे।

पत्र पढ़ने से ऐसा लगता है मानो पूरे देश में हिंदुओं की कुछ विशेष जातियां उन्मादग्रस्त होकर धर्म के नाम पर हिंसा कर रही हैं। यानी जय श्रीराम का नारा लगाते हुए अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमला किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को कहा गया है कि आपकी सरकार आने के बाद यह ज्यादा बढ़ा है। उनसे पूछा गया है कि आपने इसे रोकने के लिए क्या किया? यह नरेंद्र मोदी के शासनकाल को फासीवादी शासन साबित करना है। इस पत्र की पंक्तियां देखिए- इन दिनों जय श्रीराम का नारा युद्ध उन्माद जैसा बनता जा रहा है। राम बहुसंख्यक समुदाय के लिए पवित्र हैं, राम का नाम लेना बंद कर दें।

क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? जुलाई में ही भीड़ की हिंसा की जितनी दुखद घटनाएं हुई हैं उनमें एक झारखंड में वीडियो सामने आया जिसमें पेड़ से बांधे गए चोर को कहा जा रहा है कि जय श्रीराम बालो, जय हनुमान बोलो। यह व्यवहार निंदनीय और आपत्तिजनक है, किंतु यह कहना कि लोगों ने उसका मजहब जानकर जय श्रीराम कहते हुए हमला किया और मार डाला, बिल्कुल झूठ है। उस घटना की छानबीन के बाद सरायकेला जिले के उपायुक्त द्वारा गृह सचिव को 24 जून को जो रिपोर्ट भेजी गई उसके अनुसार मोहम्मद तबरेज अंसारी 17-18 जून की रात अपने दो साथियों नुमैर अली और शेख इरफान के साथ कमल महतो के घर में चोरी की नीयत से घुसा था। घर के लोग जग गए और शोर मचाया। तबरेज हाथ लग गया। ग्रामीणों ने तबरेज को पेड़ से बांधा और पिटाई की। जेल में 22 जून को उसकी तबियत बिगड़ी जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उसके प्राण निकल गए। इसका विवरण इसलिए जरूरी है ताकि साफ हो जाए कि लोगों ने उसे चोर के रूप में पकड़ा था न कि जय श्रीराम का नारा लगाते हुए हमला किया था। जय श्रीराम का नाम लेकर पीटने या हिंसा करने या अपमानित करने के उसके बाद जितनी शिकायतें आईं, जांच के बाद ज्यादातर झूठी निकली।

> **मॉब लिंचिंग के स्वरूप को समझे बिना इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना कहीं से जायज नहीं है**

पत्र का दूसरा अंश देखिए- आदरणीय प्रधानमंत्री... मुस्लिम, दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लिंचिंग तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसमें से कुछ निजी संस्थानों द्वारा जुटाया गया है तथा एक आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दलितों के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि की बात की गई है। इसके बाद एक निजी वेबसाइट को आधार बनाते हुए कहा गया है कि जनवरी 2009 से 29 अक्टूबर 2018 के बीच धर्म की पहचान के आधार पर 254 हिंसा की घटनाएं हुईं। मई 2014 के बाद से आपकी सरकार सत्ता में आई, तब से ऐसे 90 प्रतिशत हमले दर्ज किए गए। इसके बाद ये कहते हैं कि मुस्लिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रही लिंचिंग पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा गया है कि आप संसद में मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा कर देते हैं, जो पर्याप्त नहीं है।

सवाल यह है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हम मानते हैं कि अगर मजहब या जाति के नाम पर एक भी हिंसा की घटना हो तो यह हमारे मुंह पर कालिख पोतने के समान है। किंतु यह सच नहीं है। इन दिनों ऐसे आंकड़ों की बाढ़ आई है जो अमेरिका की तर्ज पर हेट क्राइम यानी घृणा अपराध की गिनती कर रही हैं। यहां हमें यह भी समझना होगा कि निहित उद्देश्य से बनाए गए ये आंकड़े किसी तटस्थ व्यक्ति के गले नहीं उतरने वाले। जरा कुछ तथ्य देखिए। जुलाई महीने की भीड़ की हिंसा की सबसे चर्चित घटना 19 तारीख को बिहार के छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र के पिठौरी नंदलाल टोला में हुई। इसमें चोरों ने पहले बकरी को अपने पिकअप वैन में लादा, फिर भैंस खोलने लगे। उसी समय उन्हें देख लिया गया और हल्ला हो गया जिससे वे पकड़े गए। यह बात ठीक है कि भीड़ ने अत्यंत बेरहमी से पिटाई की। किंतु ध्यान रखिए, जिनकी मवेशी चोरी हुई वे दलित थे। यहां मजहब और जाति का कोई मामला नहीं है। जो गांवों से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें इसका अंदाजा नहीं होगा कि मवेशी चोरी की बढ़ती घटना के खिलाफ कितना गुस्सा है। किसी का जीवन मवेशी पर टिका हुआ है और वह चोरी हो जाए तो उसके लिए यह वैसी ही क्षति है जैसे किसी उद्योगपति के लिए उद्योग का बंद हो जाना।

दूसरी घटना 13 जुलाई को राजस्थान के राजसमंद जिले की है जहां जमीन विवाद से जुड़े एक मामले की जांच करने गए हेड कांस्टेबल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह आपराधिक कार्रवाई है। तीसरी घटना 21 जुलाई की झारंखड के गुमला की है जहां लोगों ने डायन बताकर चार लोगों को अत्यंत ही क्रूरता से मार डाला। चौथी घटना 20 जुलाई की मध्य प्रदेश के नीमच की है। यहां मोर चोरी करने आए चार चोरों को लोगों ने खदेड़ा जिसमें से तीन तो भाग गए, लेकिन एक चोर पकड़ में आ गया जिसे लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला।

असल समस्या पर गौर जरूरी

इन सभी के साथ झारखंड के पूर्व वर्णित घटना को आधार बनाएं तो तीन इसमें चोरी के हैं, एक अंधविश्वास तथा एक शुद्ध अपराध। इसे कोई यह साबित करे कि मोदी सरकार आने के बाद भीड़ निर्भय होकर किसी विशेष समुदाय या जाति पर हमले कर रही है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है तो इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। भीड़ चोरों, अपराधियों को पकड़कर स्वयं कानून हाथ में न ले, पुलिस के हवाले करे, यह समाज का चरित्र बनना चाहिए किंतु जिस तरह से यह पत्र लिखा गया है उससे तो गुस्सा पैदा होगा और तनाव बढ़ सकता है। ध्यान रखने की बात है कि ज्यादातर घटनाओं में हिंसा करने वाले समाज के निचले तबके के लोग हैं। तबरेज के मामले में भी गरीब आदिवासियों ने पिटाई की। दूसरा, कोई घटना नहीं हुई जिसके आरोपी पकड़े नहीं गए और उन पर मुकदमा नहीं चला है। इस तरह से देखा जाए तो यह पत्र देश और दुनिया को गुमराह करने वाला है। यह समाज का चरित्र रहा है कि अगर चोर पकड़ा गया तो उसकी जमकर पिटाई करो। लोगों को लगता है कि पुलिस गिरफ्तार करेगी, फिर मुकदमा चलेगा, उसे जमानत मिल जाएगी और रिहा भी हो सकता है। इसलिए इसे मार ही डालो। इसके लिए राज्यों की कानूनी एजेंसियों के चरित्र तथा न्यायिक प्रक्रिया को दुरुस्त करना होगा। किंतु पत्र लिखने वालों को इससे कोई लेना-देना नहीं। गोरक्षा के नाम पर इस वर्ष एक भी मौत नहीं हुई है। क्या पत्र लिखने वाले ये तथ्य भूल गए?

सरकार विरोधी एजेंडा का हिस्सा

इस पत्र में ये लोग आगे जो बात कहते हैं उनसे इनका असली चेहरा उजागर हो जाता है। ये कहते हैं कि सरकार के विरोध के नाम पर लोगों को राष्ट्र-विरोधी या शहरी नक्सल नहीं कहा जाना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करना देश की आलोचना करने जैसा नहीं है। सरकार के खिलाफ लिए जानेवाले कदम को राष्ट्र के खिलाफ उठाया कदम नहीं करार दिया जा सकता। यहीं से पता चलता है कि पत्र लिखने वालों की असली मानसिकता राजनीतिक है। ये प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि जिन्हें शहरी नक्सली कहा जा रहा है वे सब केवल सरकार का विरोध करने वाले हैं। यह तो न्यायालय तय करेगा कि वो वाकई नक्सली हैं या नहीं। अब तो यह भी खुलासा हुआ है कि शहरी नक्सली आरोप का सामना कर रहे एक नामी बुद्धिजीवी का संबंध आतंकवादी संगठनों से रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि असंतोष का दमन नहीं किया जाए। यानी यह सरकार असंतोष का दमन करती है। सच कहा जाए तो यह पत्र मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी यानी फासिस्ट करार देकर दुनिया भर में बदनाम करने के घटिया एजेंडा का हिस्सा है। इसमें हस्ताक्षर करने वाले ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल से हैं। वहां जय श्रीराम का नारा जनता के बीच चल पड़ा है। जाहिर है, इसको ममता बनर्जी को मदद करने के एजेंडा का अंक कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा है कि पत्र बिल्कुल सही लिखा गया है।

उदार चेहरों से मुखौटा उतारने की कोशिश

इस बीच 49 हस्तियों के जवाब में 62 हस्तियों का पत्र भी आ गया है। इससे पता चलता है कि देश का वातावरण कितना बदल गया है। इससे साफ हो गया है कि अब यह संभव नहीं है कि आप अपनी हैसियत का लाभ उठाकर राजनीतिक मंसूबे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को तथा समाज के एक बड़े वर्ग को धर्म के आधार पर बदनाम करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसमें बड़ी बात यह है कि इन 62 लोगों में गीतकार और लेखक प्रसून जोशी, मालिनी अवस्थी, सोनल मानसिंह, पंडित विश्वमोहन भट्ट, डॉ. स्वप्न दासगुप्ता, पृथ्वीराज सेन और प्रो. सिराजुल इस्लाम जैसे लोग शामिल हैं। इनमें से अनेक लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के पक्ष में पहले शायद ही कभी इस तरह से मुखर हुए हों। जवाबी पत्र लिखने वालों ने 49 हस्तियों को कहा है कि ये देश के स्वयंभू अभिभावक हैं। इनके पत्र को गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने वाला बताया है। यह पत्र एकपक्षीय और विशेष राजनीतिक मंसूबे से लिखा गया है।

यह सही है कि ये पत्र लिखने वाले तब कुछ नहीं बोलते जब माओवादी आदिवासियों और सामान्य लोगों को गोलियों से भून देते हैं। जब कश्मीर में अलगाववादी भारत विरोधी नारा लगाते हुए जुलूस निकालते हैं और स्कूल तक बंद करवा देते हैं तब भी इन तथाकथित उदारवादियों के मुंह नहीं खुलते हैं। आतंकवादियों की करतूतों पर भी ये कभी पत्र जारी नहीं करते। अभी कुछ वर्ष पहले ही जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारा लगता है, देश को टुकड़े-टुकड़े करने की बात की जाती है तो उसके विरोध कभी सामने नहीं आते हैं। ऐसे में इन 62 हस्तियों ने ये सारी बातें सामने लाकर इन तथाकथित लिबरल चेहरों से मुखौटा उतारने की कोशिश की है। यह सच है कि मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा की दुखद घटनाओं को लेकर इन 49 लोगों ने बिल्कुल अतिवादी, एकपक्षीय तस्वीर प्रस्तुत की है जिससे यह साबित हो कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खरी-खरी

कविता का भविष्य : चिंतन सत्र

जगदीश ज्वलंत

कविता के भविष्य को लेकर चिंतन सत्र प्रारंभ हुआ। जिनका स्वयं का भविष्य अनिर्णित था, वे कविता के भविष्य का निर्णय करने पर आमादा थे। सच कहा जाए तो इन्हीं की घुसपैठ से कविता का भविष्य चिंताजनक हुआ था। क्राइम पेट्रोल की भाषा में- यही हैं वे कातिल दरिंदे, जिन्होंने कविता के स्वरूप को इतना विकृत किया कि श्रोता अब इसे ही सौंदर्य मान बैठे। स्वरूप मान बैठे। सच मान बैठे हैं। मंचों पर केकड़ों सी चढ़ी इस प्रजाति ने आत्ममुग्ध हो, भीड़ को भ्रमित कर, मसखरी को कविता का नाम दे उसे चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया था। चिंता स्वाभाविक थी।

कुछ गुप्त, पंत, निराला की सी मुखमुद्रा एवं परिधान धारण किए थे, तो कुछ सुभद्रा, महादेवी से मैच करती साड़ी पहिन बहिन भी पधारीं थी। मंचों के बहरूपिये काव्य के तत्वों पर दबंगई दिखाने को शालीनता से आतुर थे। गिरी हुई या यों कहें गिराई हुई कविता को उठाने के नाम पर और गिराने को तत्पर थे। बचाव के नक्कारखाने में तूती की तरह कविता चीख-चीखकर कह रही थी, 'पीछे हटो, बहुत हुआ उठाने का नाटक। तुम्हीं लोगों ने गिराया है मुझे। मेरे स्तर, चरित्र, स्वरूप को तुम्हारी ही काली सोच, काली स्याही ने ही कलुषित किया है। सत्रों के योजनाबद्ध षड्यंत्रों से तुम स्वयं को भ्रमित कर सकते हो, मुझे नहीं।'

किंतु कविता के मंदिर की आवाज को ये तथाकथित पंडे-पुजारी जनमानस तक जाने दें तब न! ये दुभाषिए काव्य में स्वार्थ को मिलाकर शीर्ष के नाम पर कविता को रसातल में पहुंचाने पर आमादा हैं। दिवंगत काव्य तपस्वियों की साधना पर स्याही मल चुके कुछ कवियों ने तो उनकी कविताओं पर पैरोडी, रैप-सांग तक बना डाले। आज उन्हीं की तस्वीरों के नीचे बैठे उन्हें मुंह चिढ़ाकर मानो कह रहे हों- 'वह सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है।'

तभी अध्यक्षता कर रहे कवि बोले- 'कविता के प्रति चिंता आपकी उपस्थिति की सार्थकता सिद्ध करती है। एक सच्चे कवि का चिंतित होना स्वाभाविक है।'

कुछ इसलिए चिंतित थे कि दूसरे चिंतित नहीं थे। एक मौन था जो सत्र को कविता पर चिंतन होने का भ्रम पैदा कर रहा था। तभी पोहे-पकौड़ों के प्रवेश ने चिंतन की दिशा बदल दी। अध्यक्ष महोदय कहना कुछ चाह रहे थे, किंतु कुछ और ही कह बैठे। बोले- 'मुझमें नींबू मत डालना।' जबकि नींबू पहले ही निचोड़ा जा चुका था।

ट्वीट-ट्वीट

अरे यार, ये ट्विटर ने फिर अपनी सूरत बदल दी! पहले वाला ही ठीक था, लेकिन कोई क्या करे। बदलाव जीवन की परिभाषा है। इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए, उतना अच्छा होगा!
अमिताभ बच्चन@SrBachchan

दम मारो दम... बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम... क्या मैं यह सदाबहार गीत गा सकती हूं या नहीं?
आशा भोसले@ashabhosle

राजनीति ने हमारे फिल्म जगत को भी काफी हद तक बांट दिया है। 'उनका' बनाम 'हमारा'। आप किसके साथ हैं? 'टुकड़े टुकड़े' या 'भक्त'। अरे, हम बिना किसी का नाम लिए संवाद क्यों नहीं कर सकते?
राजदीप सरदेसाई@sardesairajdeep

लिंचिंग एक जघन्य अपराध है, तबरेज की हो या गौरव की हो, या फिर किसी पर चोरी का आरोप लगाकर हो। लिंचिंग रुकनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं रोका तो कल इसका शिकार हम सब बन सकते हैं, 49 वाले भी, 62 वाले भी। सेलेक्टिव ये दोनों ही हैं।
साक्षी जोशी@sakshijoshii

कारगिल विजय

सबक सीखने को तैयार नहीं पाकिस्तान

कर्नल पीएन खेड़ा

भारतीय सैनिकों के कौशल, धैर्य और साहस से कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के दोगलेपन को जगजाहिर हुए दो दशक हो चुके हैं। कारगिल युद्ध ने भारत को सैन्य कला और भू-राजनीति के कई सबक सिखाए हैं। दो महीने से भी अधिक समय तक चले इस युद्ध में भारतीय थलसेना व वायुसेना ने 'लाइन ऑफ कंट्रोल' पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे घुसपैठियों को मार भगाया था।

कारगिल युद्ध के बारे में प्रथम सूचना मोर्चे पर तैनात सैनिकों को मिली कि कुछ दुर्गम पहाड़ी शिखरों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। कारगिल का क्षेत्र लगभग 168 वर्ग किमी इलाके में फैला हुआ है और इसका 80 वर्ग किमी का इलाका बर्फ से ढका रहता है। मारपोला, विमबाट और चोरबाटला को छोड़कर इस क्षेत्र में सर्दी के दिनों में जवान तैनात नहीं रहते थे। सेना की चैकियों के बीच बड़े-बड़े फासलों का लाभ उठाकर पाकिस्तानी सेना तथाकथित मुजाहिदीनों के रूप में यहां घुस आई और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इंफेंट्री के जवानों को, जो कि चोरी से आकर यहां घुस बैठे थे, बाहर खदेड़ना आसान काम नहीं था। इसलिए भारतीय सेना ने सुनियोजित ढंग से 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया। 13 जून को भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद टाइगर हिल से दुश्मन को मार भगाने की जिम्मेदारी 18 ग्रिनेडियर को दी गई। चार जुलाई को टाइगर हिल पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने थलसेना की सहायता के लिए 'ऑपरेशन सफेद सागर' शुरू किया। 12 जुलाई तक वायुसेना के विमानों ने 580 उड़ानें भरीं। हेलीकॉप्टरों ने घायल जवानों को युद्ध क्षेत्र से अस्पताल तक लाने का कार्य किया।

दो महीने तक चले साहसिक जवाबी हमलों द्वारा भारतीय सेना ने एक के बाद एक पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि घुसपैठिये कश्मीरी मुजाहिदीन नहीं थे। वे पाकिस्तान की सेना के जवान थे। पाकिस्तानी सैनिकों की उपस्थिति के ठोस प्रमाण डायरियों, पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों के

रूप में उपलब्ध होते गए। स्पष्ट हो गया कि यह एक सुनियोजित सैन्य आक्रमण था।

कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तान की नार्दर्न लाइट इंफेंट्री की यूनिटों का पता लगने के कुछ महीने पहले, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लाहौर में मिले थे। जब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वार्ता की गर्मजोशी के माहौल का आनंद ले रहे थे, उसी समय पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में घुसपैठ करके हमला कर दिया। प्रधानमंत्री की लाहौर बस यात्रा का मकसद मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद दोनों देशों द्वारा आपसी संबंधों को सामान्य करना था। जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री संबंधों को सुधारने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तभी पाकिस्तान की सेना, भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की योजना बना रही थी।

कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की कमान जनरल वीपी मलिक के हाथों में थी। उनका मानना है कि सेनाओं और सैनिकों की अंतिम परीक्षा युद्ध में ही होती है। लड़ाइयां जीती जाती हैं, इसलिए युद्ध में सफलता मिलती है। हर लड़ाई में, हथियारों और उपकरणों की गुणवत्ता के साथ-साथ सैनिकों का युद्ध कौशल, सखाभाव, रेजीमेंट भावना और सबसे ऊपर जीतने की इच्छा-शक्ति और पक्का इरादा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय सेना को निस्वार्थता, कर्तव्य परायणता, बलिदान और शौर्य की अपनी पुरानी और बेजोड़ परंपरा पर नाज है। कारगिल के युद्ध में ठोस शौर्य का प्रदर्शन हुआ, जब कभी भी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, इस युद्ध की वीरता को याद किया जाएगा। सभी यूनिटों ने तत्परता से कार्रवाई की और दृढ़ता और परिश्रम के अपने पुराने गुणों का प्रदर्शन किया। राजनयिक दृष्टि से पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया और विश्व बिरादरी में उसकी विश्वसनीयता निचले स्तर पर पहुंच गई। जबकि भारत का रुतबा दुनिया में बढ़ा।

भारतीय सेना के कई सैनिकों ने अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कई सैनिक जीवन भर के लिए अपंग हो गए। कारगिल युद्ध के 20 साल बाद भी पाकिस्तान सेना ने सबक नहीं लिया और वह लगातार जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध द्वारा भारत को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। इस कारण से उसको काफी नुकसान हो रहा है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वह लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। कोई भी संस्था पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने जहां से भी कर्ज लिया है वह उसको चुका नहीं पा रहा है। इसके बावजूद भी वह लगातार आतंकवादियों की मदद कर रहा है। यह परिस्थिति भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है।

कारगिल युद्ध के दौरान जो सैनिक शहीद हो गये थे अब उनमें से कई परिवारों के बच्चे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हो गए हैं और वे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। **- अडनी।**

जागरण जनमत | कल का परिणाम

क्या प्रस्तावित संशोधनों से आरटीआइ कानून कमजोर हो जाएगा?

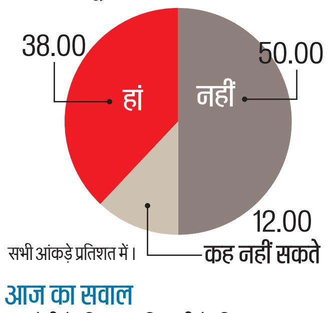

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

रमा देवी के खिलाफ टिप्पणी के लिए आजम खां को लोकसभा से निलंबित किया जाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

येद्दयुरप्पा फिर से हुए कुर्सी पर आसीन,
कर्नाटक में आज फिर बदल गया है सीन।
बदल गया है सीन शुरू अब नई कहानी,
नृप कोऊ होइ जाय न परजा को कछु हानी।
मतदाता का काम मारना केवल ठप्पा,
स्वामी हों सरताज चहे सीएम येद्दयुरप्पा।
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

क्या मिलेगा वनवासियों को नया मसीहा

कौशल किशोर
सामाजिक कार्यकर्ता

वनवासियों के अधिकारों के लिए आगे आने वाली प्रियंका के तेवर को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जहां वनवासियों को एक नया मसीहा मिल सकता है, वहीं कांग्रेस की नैया भी पार हो सकती है, लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना होगा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के उम्भा नरसंहार में मारे गए आदिवासियों के परिजनों से मिल कर लौट चुकी हैं। विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर कभी दंडक वन के नाम से ख्यात क्षेत्र का यह जघन्य हत्याकांड है। यह घटना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड समेत कई अन्य राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। शायद यही कारण है कि एक तीर से कई निशाने सधते दिख रहे हैं।

यह एक ऐसे दौर की दास्तान है, जब देश के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी वनवासी होने का प्रमाण पत्र जुटाने में लगे हैं। हालांकि उनके लिए यह काम पढ़े-लिखे शहरी लोगों की तरह आसान नहीं है। आज देश के करीब 90 लाख आदिवासी इसी वजह से अपने ही घरों से बेदखल होने को मजबूर हैं। यह देश के 16 राज्यों के तमाम जनजातियों के ऐसे लोगों की ज्वलंत समस्या है, जो नागरिक समाज का हिस्सा नहीं हो सके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वनाधिकार कानून में बदलाव की आड़ में आदिवासियों की जमीन हड़पने के षड्यंत्र पर सवाल खड़ा किया था। सरकार नेहरू के जमाने से ही आदिवासियों के हितों की पैरवी कर रही है। उच्चतम न्यायालय लंबे अर्से से उनके हितों की रक्षा में लगी प्रतीत होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम समेत दलितों और वंचितों के हितों की रक्षा में लगे अनेक संगठन आदिवासियों की रक्षा में खड़े हैं। अब प्रियंका गांधी की इस नरमदिली से वनवासियों को एक नया मसीहा मिला है।

इस दौर की एक सच्चाई यह है कि जलवायु परिवर्तन पर सक्रिय अंतरराष्ट्रीय समूह वनवासियों के वनाधिकार को पर्यावरण के हित में मानने लगी है। संयुक्त राष्ट्र के 197 देश आठ अगस्त को आइपीसीसी की एक विशेष रिपोर्ट जारी करने जा रहे हैं जिसमें जनजातियों का वनाधिकार सुरक्षित रखने की पैरवी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी बीच यह भी कहा, 'जंगल में रहने वाले आदिवासियों को उनके हक की जमीन सौंप देनी चाहिए। उन्होंने सदियों से जंगल को बचाकर रखा है। वे जंगल को बचा सकते हैं।'

इसके ठीक विपरीत भारतीय संदर्भ में वन संरक्षण की नीति जंगल से आदिवासियों को साफ करने की ही रही है। आजादी के पहले से ही कबीले के आदिवासी जमीन पर दखल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। आज भी झारखंड में संथाल आदिवासी जमीन के बदले पैसे का विरोध करते हैं। अब भारत में जलवायु परिवर्तन की इस नई नीति को कैसे व कब लागू किया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा।

जनजातीय समुदाय की जमीन पर कब्जे के इस मामले की पृष्ठभूमि 1950 के दशक में रची गई। आइएएस अधिकारी प्रभात कुमार मिश्रा ने एक सोसायटी बनाई और ग्रामसभा की 112 बीघा जमीन इसके नाम कर दी। इसी बात की ओर इशारा कर योगी ने कांग्रेस को दोषी ठहराया था। इस बीच घटना वाले दिन नंबरदार हथियारबंद दस्ता लेकर उम्भा पहुंचा और इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 11 लोग मारे गए और करीब 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यहां हैरत में डालने वाली दो बातें हैं। पहली, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। दूसरी, यह जनसंहार वनवासी बनाम वनवासी जंग का नतीजा है। यहां गोड्डा के संथाल आदिवासियों की भदेस परंपरा का अंत हो जाता है। यह भूमि को धरती माता मानने की बजाय खरीद-फरोख्त की वस्तु मानने का ही परिणाम है। इसका असर नियामगिरी जैसे तमाम खनिज संपदा संपन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा।

मीडिया के एक खास वर्ग में प्रियंका की इस यात्रा की तुलना 1977 की इंदिरा गांधी की बेल्छी यात्रा से की जा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, ऐसा माना जाता है। क्या यह फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करेगी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही बताएगा, पर उन्होंने आम जन के करीब पहुंचने का साहसिक प्रयास किया है।

आजकल आदिवासियों की राजनीति को प्रभावित करने में सुप्रीम कोर्ट अहम भूमिका निभा रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब आदिवासियों को अपने पैतृक जगह से हटने को मजबूर किया गया हो। ऐसे ही अदालती आदेशों के कारण वर्ष 2002 से 2004 के बीच आदिवासियों को अपनी जगह से हटना पड़ा था। करीब तीन लाख वनवासी परिवारों के विस्थापन की इस प्रक्रिया में हिंसा, मौत और विरोध की घटनाओं की भरमार है। बीते बुधवार को उच्चतम न्यायालय में इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। किंतु फरवरी में विस्थापन पर रोक लगा कर कोर्ट ने आदिवासियों को राहत पहुंचाने का काम किया था। इस विषय में बीते 17 सालों में जारी आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सरकार, न्यायालय और तमाम पक्षकारों के वकील मिल कर आदिवासियों का हित साधने के बाद ही चैन की सांस लेंगे।

सही मायनों में यह 'श्याम' की जमीन हथियाने के पुराने खेल का नवीनतम अध्याय है। इसके बारे में दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टुटु की बात को नजरअंदाज कर की गई कोशिशों को उदार और आधुनिक तो कहा जाएगा, वाजिब नहीं। उन्होंने कहा था, 'जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास भूमि थी। वे बोले- हमें प्रार्थना करने दो। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब हमने आंखें खोलीं तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास जमीन थी।'

आज भारत के आदिवासियों की दशा अफ्रीका के उन लोगों से बहुत भिन्न नहीं रह गई। कांग्रेस महासचिव की यह संवेदनशीलता सराहनीय है, पर क्या यह भावुकता अस्तित्व के संकट से जूझ रहे वनवासियों व वंचितों की अस्मिता बचाने में मददगार साबित होगी? यह मुश्किल सवाल मुंह बाए खड़ा है।

जियो बनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी

नई दिल्ली, प्रेट्र : रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी बन गई। वोडाफोन आइडिया ने शुक्रवार को कहा कि जून 2019 तक उसकी ग्राहक संख्या घटकर 32 करोड़ पर आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पिछले सप्ताह जारी हुए वित्तीय नतीजों के मुताबिक जियो के ग्राहकों की संख्या जून तक 33.13 करोड़ थी। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने ग्राहक संख्या के मामले में मई में भारती एयरटेल को पीछे छोड़ दिया था।

हवाई अड्डों के निजीकरण की दिशा में सबसे उपयुक्त हवाई अड्डों की पहचान के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है। इस बार विदेशी कंपनियां भी बोली लगा सकेंगी।

— गुरुप्रसाद मोहापात्रा
चेयरमैन, एएआइ

संसेक्स	37,882.79	▲ 51.81
निफ्टी	11,284.30	▲ 32.15
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 35,730	▼ ₹140
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 42,150	▼ ₹150
डॉलर	₹ 68.89	▼ ₹0.15
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 63.17	

भ्रामक विज्ञापनों में नजर आए तो जाएंगे जेल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भारी जुर्माना व जेल की सजा तक का सख्त प्रावधान
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित होने का इंतजार

उत्पादों के भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापनों का हिस्सा बनने वाली नामचीन हस्तियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसा करने वाली लोकप्रिय हस्तियों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। जुर्माने की राशि 50 लाख रुपये तक की जा सकती है, जबकि जेल की सजा की अवधि पांच साल तक की हो सकती है। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के संसद से पारित होने का इंतजार है।

सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धौनी का नाम आम्रपाली बिल्डर्स के ब्रांड एंबेसडर के रूप में आया था। इससे पहले जब मैगी की गुणवत्ता विवादों में थी, तो उसके ब्रांड एंबेसडर रहे अमिताभ बच्चन भी सवालों के घेरे में आए थे। ऐसे ही कई दिग्गज हस्तियों पर उत्पादों की गुणवत्ता जांचे बगैर उसके विज्ञापन अभियान का हिस्सा बनने का आरोप लगाया गया था। इस तरह की नामचीन हस्तियों को दोयम दर्जे के उत्पादों के प्रचार आदि में हिस्सा लेने पर रोक लगाने के उद्देश्य से कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का नया मसौदा लोकसभा में आठ जुलाई को पेश कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी है। लेकिन संसद सत्र की सात दिन की बढ़ी अवधि के दौरान इस विधेयक के पारित हो जाने की संभावना है।

ऐसी होगी सजा

अगर कोई मशहूर हस्ती भ्रामक विज्ञापन में हिस्सा लेती है तो पहली बार 10 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान है। – अपराध दोबारा हुआ तो निर्माता, विक्रेता अथवा ब्रांड एंबेसडर पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सजा की अवधि पांच साल की जा सकती है

अपराध की बारंबारता बढ़ने पर जुर्माना व जेल दोनों में और वृद्धि की जा सकती है

उपभोक्ता संरक्षण के ये उपाय

उत्पाद व सेवा से उपभोक्ताओं के जीवन व संपत्ति के लिए पैदा हुए खतरे से संरक्षित करना

उत्पाद व सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी देना – उत्पाद व सेवा के प्रकार और उनकी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना

गलत वस्तुओं की बिक्री अथवा किसी तरह की धोखाधड़ी की शिकायत का अधिकार मुहैया कराना

इन पर लगेगी रोक

चमत्कारिक दवाओं व अचूक नुस्खों से गोरा बनाने, कद बढ़ाने और मोटापा घटाने जैसे लुभावने व कथित भ्रामक विज्ञापन देने वाले तथा इस तरह के विज्ञापनों में हिस्सा लेने वाले ब्रांड एंबेसडर कानून के दायरे में आएंगे।

33 वर्ष लग गए

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पहली बार बना था, जो बदलते परिवेश और उदारीकरण के बाद प्रभावकारी नहीं रह गया था। इसके लिए अधिनियम में इतने संशोधन हुए कि उस कानून की जगह नया मसौदा तैयार कर संसद में विधेयक पेश करना पड़ा है।

ताकि गुमराह न हो ग्राहक

देश में उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में लंबित है। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो भ्रामक या गुमराह करने वाले विज्ञापनों का हिस्सा बनने वाली हस्तियों पर शिकंजा कसेगा। अभी विज्ञापनों में उत्पादों की तमाम खूबियां गिनाई जाती हैं जबकि गुणवत्ता के लिहाज से वह वास्तविकता से परे होती हैं। चूंकि उसकी खूबियां ऐसी हस्ती बताती है जिसकी जनमानस में अच्छी छवि होती है, लिहाजा लोग बिना किसी शंका के उस उत्पाद को खरीद लेते हैं। हालांकि इस्तेमाल करने पर वे छले महसूस करते हैं।

भ्रामक विज्ञापन

एफएसएसएआइ के मुताबिक किसी उत्पाद को तब भ्रामक माना जाता है जब उसे गलत तथ्यों, भ्रामक विज्ञापनों के सहारे प्रदर्शित या बेचा जाए। विज्ञापन में कही गई बातें उत्पाद लेबल पर दी गई जानकारी से मेल न खाए। लेबल पर खाद्य पदार्थ के विषय में जानकारी न उपलब्ध हो। इस श्रेणी में आने वाले सभी उत्पादों को भ्रामक माना जाता है।

मिसाल की मशाल : कई सेलेब्रिटी ने विज्ञापन उत्पादों के चयन से मिसाल कायम की है।

एक फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन को मना किया। उनका मानना है कि सांवला होना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं।

कंगना रनोट

महान क्रिकेटर ने शराब का विज्ञापन करने से मना कर दिया था क्योंकि यह उत्पाद सेहत के लिए हानिकारक है।

सचिन तेंदुलकर

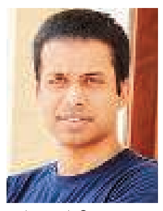

बैडमिंटन खिलाड़ी ने सेहत के लिए नुकसानदेह सिगरेट का विज्ञापन करने से मना कर दिया था।

पुलेला गोपीचंद

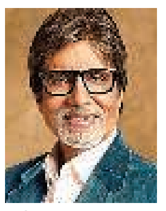

सदी के महानायक ने एक कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट की खामियां जानने के बाद विज्ञापन अस्वीकार कर दिया था।

अमिताभ बच्चन

भारतीय विधान

देश में उपभोक्ता हितों के सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कई नियम-कानून हैं।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट

यदि कोई सेलेब्रिटी किसी खाद्य पदार्थ का भ्रामक विज्ञापन करता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट (एफएसएसएआइ) 2006 की धारा 2 (जेडएफ) के प्रावधान के तहत उसे दस लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी तक यह देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलेब्रिटी को जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था की गई है।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट

किसी ऐसी दवा का विज्ञापन नहीं किया जाएगा जो डायबिटीज, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के रोकथाम या इजाज का दावा करती हो। इस श्रेणी में मोटापा, गाल ब्लैडर में पथरी, कम लंबाई जैसी 50 बीमारियां शामिल हैं।

ड्रग एंड मैजिकल रैमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट) एक्ट

इस कानून के अंतर्गत दवाओं के इस्तेमाल से संबंधित चार तरह के विज्ञापनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें गर्भनिरोधक दवाएं और कैंसर, डायबिटीज, मोतियाबिंद, गठिया, ब्लडप्रेशर व एड्स जैसी बीमारियों के जांच व उपचार से संबंधित विज्ञापन शामिल हैं। उल्लंघन पर सजा का प्रावधान न होने की वजह से प्रभावशाली नहीं।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986

यदि किसी उत्पाद के विषय में विज्ञापन के जरिए कुछ ऐसे दावे किए जाते हैं जिसपर यह खरा नहीं उतरता तो यह छलपूर्ण कारोबारी गतिविधियों में आएगा। इस तरह के भ्रामक विज्ञापन की शिकायत करने पर इसे हटाने का आदेश दिया जा सकता है। इससे यदि कोई क्षति होती है तो विज्ञापनदाता को इसके लिए मुआवजा देना पड़ सकता है। विज्ञापनदाता को इसके सुधार के लिए दूसरा विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया जा सकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो

यदि कोई उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित है तो निर्माता इसके संबंध में किसी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन नहीं चला सकता। यदि वह इसके संबंध में विज्ञापन चलाता है तो उत्पाद के विषय में वही बातें बतानी होंगी जिसके आधार पर सर्टिफिकेशन मिला हुआ है।

परदेस में प्रावधान

अमेरिका : यहां का फेडरल ट्रेड कमीशन किसी भी उत्पाद के विज्ञापन को लेकर बहुत सख्त है। हालांकि सामान्य नियम है कि विज्ञापनों में विज्ञापन करने वाले की ईमानदार राय, तथ्य, नतीजे, भरोसे, मान्यताएं की झलक होनी चाहिए। कई मामलों में यहां विज्ञापन करने से पहले सेलेब्रिटी द्वारा उत्पाद के इस्तेमाल किए जाने का भी नियम है। वास्तविकता से परे के दावे करने वाले विज्ञापनों के मामले में अगर जांच में झूठ पाया जाता है तो विज्ञापन करने वाला जिम्मेदार होता है।

चीन : चीन के फूड सेफ्टी लॉ में गुमराह करने वाले विज्ञापनों और सिफारिशों के लिए निर्माता, विज्ञापनदाता और विज्ञापनकर्ता को जिम्मेदार ठहराए जाने की व्यवस्था है।

दक्षिण कोरिया : यहां की स्व नियमन संस्थाओं के पास काफी अधिकार हैं। इन संस्थाओं के पास यह तय करने की ताकत है कि निर्माताओं द्वारा किस उत्पाद का विज्ञापन किया जा सकता है और किसका नहीं। यहां पर मेडिकल दवाओं का कोई सेलेब्रिटी विज्ञापन नहीं कर सकता है। कानून के किसी भी उल्लंघन की सूरत में निर्माता और विज्ञापन करने वालों को दंडित करने के कड़े नियम हैं।

संकट ▶ बिक्री घटने और अवमूल्यन खर्च बढ़ने से दबाव में रहा वित्तीय नतीजा

मारुति का लाभ 32 फीसद गिरा

कंपनी तीन साल बाद पैरेंट कंपनी को सिर्फ रुपये में करेगी रॉयल्टी का भुगतान

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 31.67 फीसद घटकर 1,376.8 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने कहा कि कारों की बिक्री में कमी और अवमूल्यन खर्चों में बढ़ोतरी के कारण शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की गई है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 2,015.1 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने कहा कि अगले तीन साल में वह अपनी पैरेंट कंपनी सुजुकी मोटर को रॉयल्टी का भुगतान येन की जगह पूरी तरह रुपये में करने लगेगी। उत्पादों की बिक्री से कंपनी को मिलने वाला राजस्व आलोच्य तिमाही में 14 फीसद घटकर 18,738.8 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 21,813.8 करोड़ रुपये था।

लगातार चौथी तिमाही में बिक्री सुस्त रही। फाइल

17.9 फीसद घटी बिक्री : अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की बिक्री में 17.9 फीसद की गिरावट आई। इस दौरान कंपनी ने कुल 4,02,594 वाहन बेचे। घरेलू बाजार में बिक्री 19.3 फीसद घटकर 3,74,481 यूनिट रही। आलोच्य तिमाही में अवमूल्यन का खर्च 919 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 720.3 करोड़ रुपये था

वाहन उद्योग की सुस्ती से भी कारोबार प्रभावित : कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी अजय सेठ ने कहा कि पहली तिमाही में घरेलू वाहन उद्योग में जारी सुस्ती का असर भी पड़ा। उद्योग की बिक्री में लगातार चौथी तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है। पिछली तिमाही में उद्योग में यात्री वाहनों की बिक्री 18 फीसद घटी है। इसका कंपनी पर भी असर पड़ा और घरेल बिक्री 19.3 फीसद घटी।

ग्रामीण बाजार ने भी कंपनी को किया निराश : बाजार की चुनौतियों के बारे में कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग एंड सेल्स) आरएस कलसी ने कहा कि ग्रामीण बाजार भी दबाव में है, जहां बिक्री करीब 17 फीसद घटी है। पहले ग्रामीण बाजार में बिक्री अच्छी खासी रहा करती थी।

बजाज ऑटो का शुद्ध लाभ 2.84 फीसद घटा

नई दिल्ली : बजाज ऑटो को अप्रैल-जून तिमाही में 1,012.16 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ हुआ। यह एक साल पहले की समान तिमाही में हुए शुद्ध लाभ के मुकाबले 2.84 फीसद कम है। आलोच्य तिमाही में कंपनी की बिक्री दो फीसद बढ़कर 12,47,174 यूनिट रही।

भारत में निसान के 1,700 से अधिक कर्मियों की नौकरी पर लटकी तलवार

नई दिल्ली : दुनियाभर में कर्मचारियों की संख्या घटाने की कवायद के तहत जापान की वाहन निर्माता कंपनी निसान भारत में भी 1,700 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालना चाहती है। इनमें अधिकतम कर्मचारी मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र से होंगे। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई में रेनों और निसान के संयुक्त संयंत्र से कर्मचारियों से निकाला जा सकता है। निसान मोटर इंडिया ने इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। कंपनी 2020 से 2022 के बीच दुनियाभर में 6,100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। कंपनी ने 2019 के अंत तक दुनियाभर में 6,400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का लक्ष्य रखा था।

नोटबंदी से जुड़े मामलों के मूल्यांकन की फिर बढ़ी समय सीमा

नई दिल्ली, प्रेट्र : नोटबंदी के बाद संदिग्ध जमा करने वाली करीब 87,000 इकाइयों का अंतिम मूल्यांकन पूरा करने के लिए टैक्स अधिकारियों को दी गई समय सीमा को दो महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि ऑपरेशन क्लीन मनी (ओसीएम) से जुड़े मामलों का जुलाई अंत तक मूल्यांकन पूरा करने में अधिकारियों के सामने आ रही दिक्कतों को देखने के बाद समय सीमा बढ़ाई गई है।

सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि ओसीएम मामलों में मूल्यांकन पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई जाती है और ये 30 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। ऑपरेशन क्लीन मनी की शुरुआत नोटबंदी के बाद काले धन पर रोक लगाने के लिए की गई थी। इनकम टैक्स विभाग के असेसिंग अधिकारियों ने इस महीने के शुरू में सीबीडीटी से समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। अधिकारियों ने कहा था कि इस काम को मानव श्रम से जुलाई अंत तक पूरा कर पाना असंभव है। क्योंकि इसमें काफी अधिक कागजी कार्य और श्रम बल की जरूरत होगी।

दो दर्जन और एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को सौंपे जाएंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 15 लाख से अधिक वार्षिक यात्री संख्या वाले एयरपोर्ट निजी हाथों में सौंपने की तैयारी
- सर्वाधिक उपयुक्त हवाई अड्डों के चयन के लिए परामर्शदाता नियुक्त

छह एयरपोर्ट के बाद सरकार का इरादा कई करीब 25 और हवाई अड्डों के निजीकरण का है। इस बार बड़ी संख्या में विदेशी एयरपोर्ट भी बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) के चेयरमैन गुरुप्रसाद मोहापात्रा ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में नवंबर, 2018 में सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम तथा गुवाहाटी समेत छह एयरपोर्ट के निजीकरण का निश्चय किया था। इनमें तीन में कैबिनेट की मंजूरी के साथ निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाकी तीन को भी शीघ्र कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद दूसरे चरण के तहत कई अन्य एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को संचालन, प्रबंधन एवं विकास के लिए सौंपे जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही मोहापात्रा को औद्योगिक संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) में सचिव नियुक्त किया गया है।

हालांकि एयरपोर्ट की संख्या पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका चयन अभी होना है। लेकिन ये वो एयरपोर्ट होंगे जहां वार्षिक यात्री संख्या 15 लाख से अधिक है। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख नगरों में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के स्वामित्व वाले 20-25 एयरपोर्ट इस श्रेणी में आते हैं। निजीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हवाई अड्डों का चयन करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त कर दिए गए हैं। चयन के बाद विमानन मंत्रालय को जल्द ही उनके नाम सौंपे जाएंगे। दूसरे दौर में कोई भी आवेदन कर सकता है। इस बार अनेक विदेशी कंपनियों द्वारा भी बोली लगाने की उम्मीद है। फरवरी में संपन्न हुई पहले चरण की बोली में सभी एयरपोर्ट के लिए सबसे ऊंची अडानी समूह ने लगाई। इसमें एएआइ ने सर्वाधिक प्रति यात्री शुल्क (पीपीएफ) के आधार पर अनुबंध दिया है।

आइएनएस ने की न्यूजप्रिंट से सीमा शुल्क वृद्धि वापस लेने की गुजारिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा – न्यूजप्रिंट निर्माताओं ने संपूर्ण मांग पूरी करने का सरकार को शायद गलत आश्वासन दिया
- घरेलू न्यूजप्रिंट की गुणवत्ता भी ठीक नहीं, आधुनिक छापाखानों में सीमित ही हो पाता है इस्तेमाल

इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी की कार्यकारी समिति ने अपनी आपात बैठक में सरकार से समाचार पत्रों के लिए इस्तेमाल होने वाले न्यूजप्रिंट, अनकोटेड पेपर तथा पत्रिकाओं में इस्तेमाल होने वाले लाइटवेट पेपर पर लगाए गए 10 फीसद सीमा शुल्क को वापस लेने की मांग की है। इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आइएनएस) के मुताबिक भारत में न्यूजप्रिंट की कुल खपत 25 लाख टन की है। जबकि स्वदेशी मिलों का कुल उत्पादन केवल 10 लाख टन का है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय न्यूजप्रिंट निर्माताओं ने सरकार को गलत भरोसा दिया है कि वे संपूर्ण जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। पिछले वर्ष दुनियाभर में न्यूजप्रिंट की भारी किल्लत थी। इसके बावजूद भारतीय निर्माता केवल 12,726 टन न्यूजप्रिंट का ही निर्यात कर सके थे। इससे पता चलता है कि भारत में उत्पादन क्षमता सीमित है और स्वदेशी निर्माताओं ने सरकार को गलत जानकारी दी है।

इतना ही नहीं, आयातित न्यूजप्रिंट के मुकाबले स्वदेशी न्यूजप्रिंट गुणवत्ता में भी कमतर है, जिससे आधुनिक छापाखानों में इसका सीमित इस्तेमाल हो पाता है। आयातित न्यूजप्रिंट के मुकाबले स्वदेशी न्यूजप्रिंट के छपाई के दौरान फटने की दर तीन गुना से भी ज्यादा है। इससे बर्बादी के अलावा उत्पादकता में कमी आती है। स्वदेशी मिलों से न्यूजप्रिंट की आपूर्ति में भी अनिश्चितता रहती है। क्योंकि अनेक मिलें केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की ओर से कारण बताओ नोटिस का सामना कर रही हैं। जहां तक अनकोटेड तथा लाइटवेट कोटेड पेपर का मामला है तो इनकी देश में कोई उत्पादन क्षमता ही नहीं है।

कम विज्ञापन आय, ऊंची लागतों तथा डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के छोटे और मझोले प्रकाशक पहले ही भारी वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं। सरकार के नवीनतम कदम से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यह भी संभव है कि उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़े। इसलिए सरकार को दखल देकर सीमा शुल्क बढ़ोतरी के इस कदम को वापस लेना चाहिए तथा समाचार पत्र उद्योग को असहनीय बोझ से बचा लेना चाहिए।

लाभ में आया पीएनबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) लाभ में आ गया। सरकारी बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए 1,019 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। फंसे कर्ज के प्रावधान में कमी और संपत्ति गुणवत्ता में हुए सुधार के कारण पीएनबी लाभ में आया। पिछले साल की समान तिमाही में बैंक ने 940 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। जनवरी-मार्च तिमाही में भी बैंक ने 4,750 करोड़ रुपये का भारी भरकम घाटा दर्ज किया था। संपूर्ण वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बैंक ने 9,975.49 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था। बैंक के एमडी और सीईओ सुनील मेहता ने कहा कि जनवरी-मार्च का तिमाही नतीजा जारी करते हुए हमने कहा था कि हम बुरे दौर से आगे बढ़ चुके हैं। अगली तिमाहियों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। लोन प्रोसेसिंग की केंद्रीयकृत प्रणाली, तनावग्रस्त संपत्तियों का मजबूत प्रबंधन और निगरानी प्रणाली में सुधार के बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। जून अंत में बैंक का ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 16.49 फीसद पर आ गया।

सीएसआर राशि चार वर्षों में खर्च करना जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चार लाख मुखौटा कंपनियों का नाम हटाया : वित्त मंत्री
- लोकसभा से कंपनी कानून संशोधन विधेयक पारित

लोकसभा ने शुक्रवार को कंपनी कानून में संशोधन का विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक के कानून का रूप लेने पर कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी नियम सख्त हो जाएंगे। जो कंपनियां नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। विधेयक में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कंपनियां सीएसआर की जितनी राशि को खर्च नहीं कर पाती हैं, उसे उन्हें एक विशेष खाते में रखना होगा। अगर कंपनियां निर्धारित अवधि में सीएसआर की राशि खर्च नहीं करतीं तो यह प्रधानमंत्री राहत कोष में चली जाएगी।

कंपनी संशोधन विधेयक, 2019 को सदन के विचारार्थ रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कंपनियां चार साल तक अपने लाभ की दो फीसद राशि सीएसआर गतिविधियों पर खर्च नहीं करती हैं, उन्हें एक विशेष खाते में धनराशि जमा करनी होगी।

कंपनी कानून में यह प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी पांच करोड़ रुपये से अधिक लाभ अर्जित करती है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक है, या उसका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक है तो उसे तीन साल के औसत शुद्ध लाभ की कम से कम दो फीसद धनराशि सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करनी होती है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सीएसआर खर्च करने की बाध्यता का प्रावधान कानून में किया है। कंपनियों को एक साल में सीएसआर का प्रस्ताव बनाना होगा और तीन साल में उस पर धनराशि खर्च करनी होगी। अगर धन खर्च नहीं हो पाता है तो वह राशि एक अलग खाते में चली जाएगी। यह खाता प्रधानमंत्री राहत कोष का भी हो सकता है।

ये हैं मुखौटा कंपनियां

मुखौटा कंपनियों के बारे में सदस्यों की चिंताओं को दूर करते हुए सीतारमण ने कहा कि मुखौटा कंपनियां नियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं लेकिन आशय उन कंपनियों से है जो निष्क्रिय हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय नहीं है।

इसलिए पड़ी संशोधन की जरूरत

वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनी कानून में संशोधन का उद्देश्य व्यवसाय की प्रक्रिया आसान बनाने और कंपनियों, खासकर छोटी कंपनियों पर नियमों के अनुपालन का बोझ हल्का करने का है। सरकार ने चार लाख मुखौटा कंपनियों को रजिस्टर से हटा दिया है। सदन में चर्चा के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक के विरोध में लाए गए वैधानिक प्रस्ताव को वापस ले लिया। उसके बाद सदन ने एकमत से विधेयक पारित कर दिया।

राहत

सेंसेक्स 51.81 अंकों की तेजी के साथ 37,882.79 पर बंद, निफ्टी 32.15 अंकों के उछाल के साथ 11,284.30 पर स्थिर

छह सत्रों की गिरावट से उबरा बाजार

मुंबई, प्रेट्र : शेयर बाजारों में छह सत्रों से जारी गिरावट शुक्रवार को थम गई और प्रमुख सूचकांक तेजी के दायरे में बंद हुए। कारोबारियों ने कहा कि फीके तिमाही नतीजों, विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी की निकासी और विदेशी बाजारों के कमजोर रुझानों के कारण बाजार पर दबाव दिखा, लेकिन अगले दो सप्ताहों में औसत से अधिक बारिश की उम्मीद ने निवेशकों का हौसला बढ़ा दिया।

बीएसई का सेंसेक्स 51.81 अंकों की तेजी के साथ 37,882.79 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 32.15 अंकों की तेजी के साथ 11,284.30 पर बंद हुआ। सप्ताहभर के कारोबार में सेंसेक्स में 454.22 अंकों और निफ्टी में 134.95 अंकों की गिरावट रही। सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के वाहन सेक्टर में सर्वाधिक 1.98 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर ऊर्जा सेक्टर में सर्वाधिक 1.01 फीसद गिरावट रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.53 फीसद और स्मॉलकैप में 0.22 फीसद तेजी रही। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अगले दो सप्ताह में औसत से अधिक बारिश होने की उम्मीद से बाजार में तेजी को बल मिला।

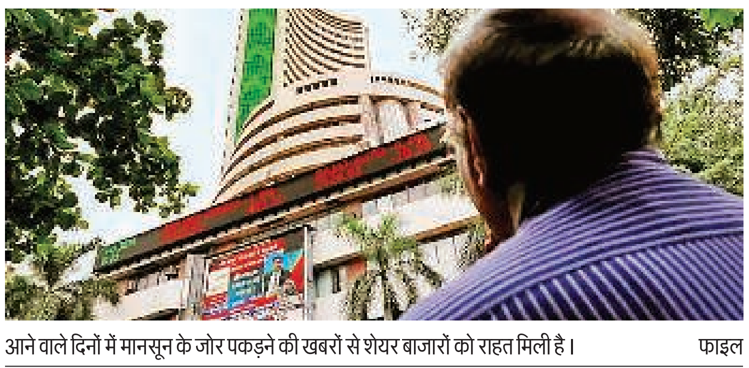

आने वाले दिनों में मानसून के जोर पकड़ने की खबरों से शेयर बाजारों को राहत मिली है। फाइल

यस बैंक 9.64 फीसद उछला : सेंसेक्स में यस बैंक में सर्वाधिक 9.64 फीसद तेजी रही। बजाज फाइनेंस 7.20 फीसद उछला। कंपनी ने जून तिमाही में 1,195 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो रिकॉर्ड तिमाही कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ है। हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा में तीन फीसद से अधिक, बजाज ऑटो में दो फीसद से अधिक, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, लार्सेन एंड टुब्रो और टाटा स्टील में एक फीसद से अधिक तेजी रही। मारुति सुजुकी में 0.78 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर वेदांता में 4.26 फीसद की सर्वाधिक गिरावट रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, भारती एयरटेल और एचसीएल टेक में एक फीसद से अधिक गिरावट रही। अन्य प्रमुख शेयरों में पंजाब नेशनल बैंक 2.95 फीसद उछला। साउथ इंडियन बैंक में 5.10 फीसद तेजी दर्ज की गई।

मांग में सुस्ती से सोना 140 रुपये लुढ़का

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्थानीय ज्वेलरों की ओर से मांग में सुस्ती के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 140 रुपये लुढ़ककर 35,730 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी घटने से चांदी भी 150 रुपये गिरकर 42,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

सराफा कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय ज्वेलरों द्वारा कम खरीदारी होने के कारण सोने की कीमत में गिरावट आई। हालांकि विदेशी बाजारों के मजबूत रुझानों ने कीमत को अधिक नहीं गिरने दिया। न्यूयॉर्क में सोने में 1,418.80 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 16.51 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी के हाजिर बाजार में 99.9 फीसद खरा सोना 140 रुपये लुढ़ककर 35,730 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही गिरावट के साथ 35,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी 27,500 रुपये प्रत्येक के भाव पर स्थिर रही।

तबादले से पहले ही गर्ग ने जताई थी वीआरएस की इच्छा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 18 जुलाई को प्रधानमंत्री कार्यालय में की थी वीआरएस के बारे में चर्चा
- कहा, तबादले और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फैसले में कोई संबंध नहीं

वरिष्ठ नौकरशाह सुभाष चंद्र गर्ग ने शुक्रवार को साफ किया कि उनके तबादले और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने 18 जुलाई को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ उनके वीआरएस लेने के इरादे को लेकर चर्चा की थी। गर्ग ने पिछले दिनों वित्त मंत्रालय से उर्जा मंत्रालय में तबादले के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने की पेशकश की थी। हालांकि चर्चा यह थी कि तबादले से नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति ने बुधवार को गर्ग का तबादला बिजली मंत्रालय के सचिव पद पर कर दिया था। गर्ग ने शुक्रवार को बिजली सचिव का पद संभालने के बाद कहा कि उन्होंने तबादला आदेश से काफी पहले 18 जुलाई को पीएमओ के साथ उनकी वीआरएस लेने की योजना के बारे में बातचीत की थी। इसलिए इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं है। वह सरकार के सहयोग के लिए आभारी हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या उनका वीआरएस का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है, गर्ग ने कहा कि इसकी एक स्थापित प्रक्रिया है और यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है। गर्ग ने गुरुवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर जानकारी दी थी कि उन्होंने वीआरएस लेने के लिए आवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआ) के रिजर्व फंड से सरकार को कितनी रकम मिलनी चाहिए, इसके लिए गठित जालान समिति में भी गर्ग सरकार के नामित सदस्य हैं। उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर दस्तखत क्यों नहीं किए, इस बारे में गर्ग ने कहा कि अब तक समिति ने विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

150 प्रवासी लापता हो गए हैं लीबिया के तट पर नाव डूबने के बाद। प्रवासियों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आइओएम) के प्रवक्ता सफा महिली ने कहा कि खोम्स शहर के तट पर यह घटना हुई। यह शहर राजधानी त्रिपोली से करीब 100 किलोमीटर दूर है। लीबियाई तटरक्षक बल ने करीब 145 प्रवासियों को बचा लिया।

मिसाइल परीक्षण दक्षिण कोरिया को चेतावनी

टकराव की बात ▸ उत्तर कोरिया ने कहा, अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास के जवाब में किया टेस्ट

अमेरिकी सेना ने कहा, नहीं है कोई खतरे की बात

सियोल, रायटर : कम दूरी की दो बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने यह परीक्षण दक्षिण कोरिया द्वारा हथियारों की खरीद और अमेरिकी सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में किया है। उसने कहा कि यह परीक्षण युद्ध को उकसावा देने वाले दक्षिण को रिया के लिए चेतावनी है। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने शीर्ष नेता किम जोंग उन की उपस्थिति में 600 किलोमीटर तक मार करने वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था।

उत्तर कोरिया की इस हरकत पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही अमेरिका-दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य कमान (सीएफसी) के प्रवक्ता ने कहा, 'इससे हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता।' उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद निरस्त्रीकरण को लेकर अमेरिका से चल रही बातचीत पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम की मुलाकात के वक्त दोनों के बीच बातचीत फिर शुरू करने पर सहमति बनी थी। उत्तर कोरिया के निरस्त्रीकरण को लेकर इस साल हनोई में दोनों नेताओं के बीच दूसरी शिखर वार्ता विफल हो गई थी, जिसके बाद उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उत्तर कोरिया ने हाल ही में यह चेतावनी दी थी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगर प्रस्तावित सैन्य अभ्यास को रद नहीं करते हैं तो परमाणु वार्ता पटरी से उतर सकती है। वाशिंगटन और प्योंगयांग में नए दौर की वार्ता अभी तक शुरू नहीं हुई है।

उत्तर कोरिया ने गुरुवार को तानाशाह किम जोंग उन की उपस्थिति में 600 किलोमीटर तक मार करने वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। रायटर

अमेरिका ने नए सिरे से बातचीत की संभावना जताई : उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और किम के बीच नए सिरे से बातचीत की अब भी संभावना है। उन्होंने कहा है कि अंतिम मुलाकात में किम ने मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों पर पाबंदी को लेकर सहमति जताई थी।

यूएन प्रतिबंध का हुआ उल्लंघन : उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पारित प्रस्ताव का उल्लंघन है। उत्तर कोरिया हालांकि यूएन प्रतिबंधों को मानने से इन्कार करता है।

कोरियाई सीमा पर मिले थे ट्रंप और किम : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने गत 30 जून को कोरियाई सीमा पर मुलाकात की थी। तब उत्तर कोरिया की सीमा में कदम रखने वाले ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। इस दौरान दोनों नेताओं में परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी। इस मुलाकात के बाद उत्तर कोरिया ने यह पहला मिसाइल परीक्षण किया है।

यूरोप में गर्मी का सितम जारी

अपने ठंडे मौसम के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध देशों में इस वर्ष झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। इसका सामान्य जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। इतना ही नहीं, गर्मी की वजह से रेल और हवाई मार्ग भी प्रभावित है। हाल यह है कि स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड आदि देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को तापमान रिकॉर्ड 42.06 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी से बचने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक सनस्क्रीन और फव्वारों का सहारा ले रहे हैं। कई स्थानों पर स्नान के लिए डे सेंटर भी खोले गए हैं। एएनएन

न्यूज गैलरी

बेल्जियम में भीषण गर्मी से महिला की मौत

ब्रसेल्स : यूरोपीय देश बेल्जियम में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से एक महिला की मौत हो गई। देश में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। गुरुवार को मिडलकर्क के तटवर्ती इलाके में 66 साल की एक महिला को मृत पाया गया। स्थानीय पुलिस ने महिला की मौत का कारण भीषण गर्मी बताया है। पश्चिमी यूरोप के अन्य हिस्सों की तरह गुरुवार को बेल्जियम का तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। (एपी)

इंडोनेशिया में ज्वालामुखी सक्रिय, अलर्ट जारी

जकार्ता : इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत की राजधानी बांदुंग से 30 किलोमीटर दूर स्थित एक ज्वालामुखी शुक्रवार को अचानक सक्रिय हो गया। तांगकुबान पराहु ज्वालामुखी के सक्रिय होने से इस पर्यटन क्षेत्र के आसमान में राख फैल गई और लोगों में अफरातफरी मच गई। सरकार ने अलर्ट जारी कर लोगों को ज्वालामुखी से दूर जाने को कहा है। आसपास के पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। (रायटर)

मुलर ने बहुत खराब काम किया : डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच के लिए नियुक्त विशेष अभियोजक रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट के मामले में साबित हो गया है कि उनके खिलाफ पूरा अभियान फर्जी था और जानबूझकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश गई थी। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एफबीआइ) के पूर्व निदेशक मुलर बुधवार को कांग्रेस की दो समितियों के सामने पेश हुए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, मुलर ने बेहद खराब काम किया–कांग्रेस की समितियों के सामने गवाही के दौरान भी और जांच में भी। मुलर के पास करने के लिए कुछ नहीं था। आप एक अच्छे बिल्डर हो सकते हैं, लेकिन अगर सही सामग्री न मिले तो आप अच्छी इमारत नहीं बना सकते। (प्रेट्र)

फ्लाइबोर्ड से इंग्लिश चैनल पार करने में असफल रहा फ्रांसीसी

सैनगाट्टे : फ्रांस के रोमांच प्रेमी फ्रैंकी जपाट ने अपने बनाए फ्लाइबोर्ड से इंग्लिश चैनल पार करने का प्रयास किया। गुरुवार को अपने प्रयास में असफल रहने के बाद वह समुद्र में गिर गया। लेकिन इस असफलता के बाद भी उसने फिर से प्रयास करने की ठानी है। पूरी सतर्कता के साथ तैयारी करने के बाद जपाट फ्रांस के तटीय शहर सैनगाट्टे से छोटे से उड़ने वाले प्लेटफार्म के साथ रवाना हुआ। यह प्लेटफार्म उसने खुद ही डिजाइन किया था। दूर से लग रहा था कि वह आसमान में खड़ा है। आधा रास्ता तय करने के बाद वह रिफ्यूलिंग स्टाप पर पहुंचा। लेकिन लैंड करने के लिए उसने जो प्लेटफार्म बनाया था वह लहरों के कारण तेजी से हिलने के कारण वह पानी में गिर गया। (एपी)

एंटी रैबीज व एंटी वेनम वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भर है पाकिस्तान

▸ कुत्ता, बंदर व सांप काटने के इलाज में भी आत्मनिर्भर नहीं है पड़ोसी देश

▸ पिछले 16 महीने में भारत से खरीदी 250 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन

द्विपक्षीय वार्ता बंद होने के बाद भी भारत से जारी है दवा की खरीद। फाइल

इस्लामाबाद, प्रेट्र : आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान अपने जख्मों के इलाज की भी कूवत नहीं रखता। आलम यह है कि नए पाकिस्तान की डींगे हांकने वाले पड़ोसी देश के पास कुत्ता, बंदर व सांप काटने के इलाज की भी पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह इसके लिए भी भारत पर निर्भर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एंटी रैबीज व एंटी वेनम जैसी वैक्सीन बनाने की क्षमता कम होने के कारण पाकिस्तान पिछले 16 महीने के दौरान भारत से करीब 250 करोड़ रुपये (36 मिलियन डॉलर) से ज्यादा की वैक्सीन खरीद चुका है।

द नेशन समाचार पत्र में गुरुवार को छपी खबर के अनुसार, सांसद रहमान मलिक ने भारत से खरीदी जाने वाली दवाओं की मात्रा व उनकी कीमत के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने सरकारी विभागों की वैक्सीन निर्माण क्षमता के बारे में भी जवाब मांगा था। इस क्रम में पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं सेवा (एनएचएस) मंत्रालय ने वहां की संसद की स्थायी समिति को बताया कि पिछले 16 महीनों के दौरान भारत से 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की एंटी रैबीज व एंटी वेनम वैक्सीन खरीदी गई हैं।

एनएचएस ने अपने जवाब में बताया है कि पाकिस्तान में एंटी रैबीज व एंटी वेनम सीरम का निर्माण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ करता है, जबकि एक निजी कंपनी भी एंटी वेनम सीरम का स्थानीय स्तर पर निर्माण करती है। हालांकि, इनकी क्षमता इतनी नहीं है कि लोगों की मांग पूरी की जा सके, इसलिए पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से इन वैक्सीन का आयात भारत से किया जाता है। एनएचएस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में वैक्सीन की मांग व आपूर्ति में बड़ा अंतर है।

मलिक ने सलाह दी कि पाकिस्तान दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर है, इसलिए यहां की कंपनियों को यह अनिवार्य निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे वैक्सीन का उत्पादन पाकिस्तान में ही करें। इससे वैक्सीन सस्ती भी होंगी।

उल्लेखनीय है कि द्विपक्षीय वार्ता बंद होने और खासकर पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मुहम्मद द्वारा सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले को अंजाम दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से इन वैक्सीनों की खरीद जारी रखी।

कराची के हिंदू जिमखाना में निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

कराची, प्रेट्र : कराची के हिंदू जिमखाना में निर्माण कार्य पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सिंध प्रांत के अधिकारियों को इस बाबत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिंदू जिमखाना कराची की विरासती इमारत है और इसके स्वरूप से छेड़छाड़ करना निषिद्ध है। याचिकाकर्ता श्री रत्नेश्वर महादेव कल्याण ने जिमखाना को कराची के हिंदू समुदाय की विरासत से जुड़ा बताया है। कहा है कि बंटवारे से पहले इस इमारत का निर्माण हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद सरकार ने ट्रस्ट की इस संपत्ति पर कब्जा कर लिया और अब वह इसे अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।

याचिका में सरकारी संस्था नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से इमारत खाली कराने और उसे वापस हिंदू समुदाय को सौंपने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही है। सुनवाई में पीठ ने विरासती इमारत में निर्माण की अनुमति देने के लिए प्रांतीय सरकार के अधिकारियों से नाराजगी जताई। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, निर्माण को अवैध ठहराते हुए उसे ध्वस्त कराया जा सकता है। उन्होंने इस बाबत प्रांत के मुख्य सचिव और संस्कृति विभाग के सचिव से जवाब मांगा है।

लाहौर में रैली करने पर शाहबाज और दो हजार अन्य पर मुकदमा

▸ हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के हुई कार्रवाई

▸ चंद रोज पर सरकार विरोधी सभा करने पर मरयम पर भी हुआ था मामला दर्ज

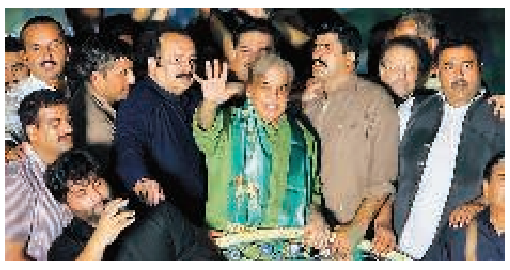
लाहौर में समर्थकों के साथ रैली के दौरान शाहबाज शरीफ। एपी

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान में हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर माल रोड पर जनसभा करने के लिए संसद में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ और उनके दो हजार समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहबाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी ने गुरुवार को लाहौर में सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसभा की थी।

जनसभा देश में इमरान खान सरकार के एक साल पूरा होने पर आयोजित की गई थी। जनसभा में पार्टी ने गो-इमरान-गो का नारा लगाते हुए काला दिन मनाने का आह्वान किया था। लाहौर के प्रशासन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि गुरुवार शाम माल रोड पर हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर जनसभा की गई। हाई कोर्ट ने शहर के व्यस्त माल रोड इलाके में जनसभा या सार्वजनिक गतिविधि करने पर रोक लगा रखी है। प्रशासन ने शाहबाज समेत करीब 50 नेताओं को एफआइआर में नामजद किया है जबकि दो हजार अज्ञात पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, जन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि की धाराएं लगाई गई हैं। इस सप्ताह के शुरू में फैसलाबाद पुलिस ने पार्टी की उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम नवाज और तीन हजार पार्टीजनों के खिलाफ भी निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।

उन्होंने फैसलाबाद शहर में सरकार के खिलाफ जनसभा की थी। विपक्षी दलों का आरोप है कि 25 जुलाई, 2018 को जनादेश के खिलाफ जाकर पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान देश के प्रधानमंत्री बने थे।

सतर्क रहते तो टाले जा सकते थे श्रीलंका में ईस्टर धमाके

▸ संसदीय समिति के सामने एसटीएफ के डीआइजी ने दर्ज कराए बयान

कोलंबो, प्रेट्र : अगर सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल होता तो श्रीलंका में ईस्टर संडे के दिन हुए आतंकी हमलों को टाला जा सकता था। यह बात हमलों की जांच करने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने संसदीय समिति को बताई। समिति हमलों के संबंध में मिली पूर्व सूचनाओं पर कार्रवाई नहीं करने के मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के वरिष्ठ उप महानिरीक्षक एमआर लतीफ ने कहा कि अगर सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल होता तो इन धमाकों को टाला जा सकता था। लतीफ ने समिति को बताया, हम चर्चों और होटलों में सुरक्षा बलों को भेज सकते थे। अगर हम ऐसा करते तो हमलावरों की योजना कामयाब नहीं होती। बता दें कि 21 अप्रैल को तीन चर्चों और कुछ होटलों पर किए गए नौ आत्मघाती हमलों में 258 लोग मारे गए थे। विश्व के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आइएस ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन सरकार ने बम विस्फोटों के लिए स्थानीय इस्लामी चरमपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) को दोषी ठहराया था।

हमलों में आइएस की भूमिका का पता नहीं चला

समिति के समक्ष बुधवार को गवाही देने वाले अपराध जांच विभाग के प्रमुख रवि सेनेविर्तने ने कहा कि जांच के दौरान आत्मघाती हमलों में आइएस की किसी भूमिका का पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि विस्फोट के बाद इस बारे में बयान जारी करने के लिए एनटीजे ने एक तीसरे पक्ष से आइएस से कहा था। विस्फोट करने वाला संगठन आइएस से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि हमलों के बारे में जो पूर्व जानकारी मिली थी, उसे हमलों से 12 दिन पहले नौ अप्रैल को पुलिस प्रमुख को बता दिया गया था। सेनेविर्तने ने कहा कि रिपोर्ट में जिन नामों का उल्लेख किया गया था, उनकी जांच हमने पहले ही कर ली थी। यही वजह थी कि हमलों के तुरंत बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने हमलों की पूर्व संध्या पर 20 अप्रैल को कहा, राज्य खुफिया प्रमुख ने मुझे हमलों की संभावना के बारे में सूचित किया था।

अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने गूगल पर किया पांच करोड़ डॉलर का मुकदमा

▸ तकनीकी दिग्गज पर लगाया चुनाव अभियान को लेकर भेदभाव का आरोप

▸ प्राइमरी बहस के बाद अकाउंट को छह घंटे तक कर दिया था बंद

अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड का फाइल फोटो। आर्काइव

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका की पहली हिंदू सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने की दावेदार तुलसी गबार्ड ने गूगल पर पांच करोड़ डॉलर (करीब 350 करोड़ रुपये) का मुकदमा किया है। तुलसी ने गूगल पर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी में बाधा डालने और उनके चुनाव अभियान के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया है। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए 20 से भी ज्यादा लोग मैदान में हैं।

गबार्ड की चुनाव अभियान समिति के अनुसार, 27 और 28 जून को हुई पहली प्राइमरी बहस के बाद तकनीकी दिग्गज गूगल ने उनके अभियान से जुड़े विज्ञापन का अकाउंट छह घंटे के लिए बंद कर दिया था। गूगल का यह कृत्य गबार्ड की बात संभावित वोटरों तक पहुंचाने और उनके अभियान के लिए फंड इकट्ठा करने में बाधा बना। इसी के चलते गूगल पर संघीय अदालत में मुकदमा किया गया है।

गबार्ड ने कहा, 'अकाउंट बंद कर गूगल ने मेरी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया। इससे यह भी पता चलता है कि इंटरनेट पर गूगल का प्रभुत्व अमेरिकी मूल्यों के लिए कितना खतरनाक है।' अपनी सफाई में गूगल के प्रवक्ता जोस कास्टानेडा ने कहा, 'गूगल का स्वचालित सिस्टम विज्ञापन दाता के अकाउंट से हो रही असामान्य गतिविधि को चिह्नित कर लेती है ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। गबार्ड के मामले में भी ऐसा ही हुआ है।'

फेसबुक, गूगल की निगरानी को ऑस्ट्रेलिया में बनेगा विभाग

सिडनी, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया की सरकार सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक और सर्च इंजन गूगल के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए एक नया विभाग बनाने जा रही है। देश में उपभोक्ताओं की निजता सुरक्षित रखने से संबंधित सुधारों के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर की अनुमति के बिना उनका निजी डाटा इकट्ठा करते हैं। यूजर को इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि उसके डाटा का इस्तेमाल कहां और किस लिए किया जा रहा है? उपभोक्ता अधिकारों की निगरानी करने वाले ऑस्ट्रेलियन कंप्टीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (एसीसीसी) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण की जांच के लिए सरकार से नया विभाग बनाने की सिफारिश की है। यह आयोग 2017 से सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रभाव का अध्ययन कर रहा था।

ईरान में भारत समेत सभी देशों के बंदी स्वस्थ और सुरक्षित

लंदन, रायटर : ईरान के कब्जे वाले ब्रिटिश व्यापारिक जलपोत स्टेना इंपेरो के चालक दल में शामिल सभी 18 भारतीय स्वस्थ और सुरक्षित हैं। भारतीय अधिकारी उनसे मिल चुके हैं। यह जानकारी ब्रिटेन में ईरान के राजदूत हामिद बेदीनेजाद ने दी है। भारतीय अधिकारियों ने भी सभी भारतीयों के सामान्य होने की पुष्टि की है।

ईरानी राजदूत ने बताया कि अन्य देशों के भी सभी पांच नागरिकों से उनके देश के राजनयिकों को मिलने की अनुमति दी गई है। वे भी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय 19 जुलाई को इस ब्रिटिश जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान ने यह कार्रवाई जिब्राल्टर में ब्रिटिश नौसेना द्वारा उसके तेल टैंकर को रोके जाने के जवाब में की है।

सुरक्षित है बेटा : दक्षिण गोवा के गांव चिकालिम में मौजूद सुरेश नाइक ने बताया है कि स्टेना इंपेरो जहाज पर तैनात उनका इंजीनियर बेटा गोविंद नाइक पूरी तरह सुरक्षित है। गोविंद जहाज के चालक दल का सदस्य है। उनकी बेटे से टेलीफोन पर बात हुई है। स्टेना जहाज 16 जुलाई को दुबई बंदरगाह से रवाना हुआ था, उसके बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उसे रोक लिया।

प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग एयरपोर्ट पर दिया धरना

'हांगकांग को स्वतंत्र कराओ' के लगाए नारे, चीन के लिए चुनौती बनता जा रहा है प्रदर्शन

विवादित प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। एपी

हांगकांग, एपी : हांगकांग में प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। इसे बीते कई दशकों में क्षेत्र का सबसे राजनीतिक संकट बताया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन ना सिर्फ हांगकांग के नेतृत्व बल्कि चीन की सरकार के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी शुक्रवार को हांगकांग अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उन्होंने एयरपोर्ट के आगमन कक्ष में धरना दिया। प्रत्यर्पण कानून के विरोध में सभी काले कपड़ों में आए थे। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों के सामने 'यहां दंगा नहीं बल्कि अन्याय हो रहा है', 'हांगकांग को आजादी चाहिए', जैसे नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले सांसद और पूर्व पायलट जेरेमी टैम ने कहा, 'विदेशी पर्यटकों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता एयरपोर्ट ही था।'

हांगकांग में प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून को लेकर एक महीने से भी ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इस कानून के तहत संदिग्धों और अपराधियों को मुकदमे के लिए सीधे चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान था। हांगकांगवासी इसे यहां की स्वायत्तता पर खतरा मान रहे हैं। वर्ष 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग इसी शर्त पर सौंपा था कि एक देश दो प्रणाली के तहत उसकी स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जून के मध्य में लाखों लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतरा आए थे जिसके बाद हांगकांग की नेता कैरी लाम ने संबंधित बिल को निलंबित कर दिया था।

ब्राजील के एयरपोर्ट से 750 किलो सोने की लूट

साओ पाउलो, आइएएनएस : पुलिस के भेष में आए आठ हथियारबंद लुटेरों ने ब्राजील के एक एयरपोर्ट से करीब 750 किलोग्राम सोना लूट लिया। दक्षिणी अमेरिका के व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल साओ पाउलो के गुआरुलहॉस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से गुरुवार को लूटे गए इस सोने की कीमत तीन करोड़ डॉलर (करीब 210 करोड़ रुपये) आंकी जा रही है। सुरक्षाकर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दो वाहनों से आए लुटेरों ने पुलिस की वर्दी और बैज भी पहन रखे थे।

इस वारदात के दौरान उन्होंने कार्गो गोदाम के सुपरवाइजर और एक अन्य कर्मी को बंधक बना लिया था। वारदात को अंजाम देकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले उन्होंने इस लूट की घोषणा भी की। एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने दोनों बंधकों को छोड़ दिया और सोने को दूसरी कार में डालकर निकल गए। पूछताछ में सुपरवाइजर ने बताया कि लुटेरों ने एक दिन पहले उसके परिवार को बंधक बना लिया था और कहा था कि लूट के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पुलिस सोने और लुटेरों की खोजबीन में जुटी है।

अमेरिका में दो दशक बाद मौत की सजा बहाल, तारीख तय

वाशिंगटन, प्रेट्र : एक बड़े निर्णय के तहत ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में दो दशक बाद मौत की सजा की बहाल करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही हत्या के मामले में पांच लोगों की मौत की सजा की तारीख भी मुकर्रर हो गई।

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र ने कहा, 'न्याय मंत्रालय ने इन पांच हत्यारों समेत सबसे बुरे अपराधियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग की है। इनमें से प्रत्येक को पूर्ण और निष्पक्ष सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया।' उन्होंने कहा, 'न्याय मंत्रालय विधि के शासन को कायम रखता है। हम पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्यायिक व्यवस्था द्वारा दी गई सजा की तामील करते हैं।' बर्र ने संघीय कारा ब्यूरो को संघीय मृत्युदंड प्रोटोकॉल में प्रस्तावित जोड़ को अपनाने का निर्देश दिया। यह संघीय सरकार द्वारा लगभग दो दशक के अंतराल के बाद मौत की सजा को फिर से शुरू करने और जघन्य अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने का रास्ता साफ करेगा। मौत की सजा पाने वालों में डेनियल लेविस ली, लेजमंड मिचेल, वेस्ली इरा पुर्के, अल्फ्रेड बॉर्गिअस और डस्टिन ली हांकेन शामिल हैं। इन्हें क्रमशः नौ दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 13 जनवरी 2020 और 15 जनवरी 2020 को मौत की सजा दी जाएगी।

मानव तस्करी के आरोप में 16 अमेरिकी नौसैनिक गिरफ्तार

लॉस एंजिलिस, रायटर : अमेरिकी नौसेना के 16 जवानों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी गुरुवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित कैंप पेंडल्टन नौसैनिक अड्डे से हुई। आरोप है कि ये नौसैनिक अमेरिका–मेक्सिको सीमा पर शरणार्थियों को अमेरिका में घुसपैठ करा रहे थे। इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए नौसेना के प्रवक्ता फर्स्ट लेफ्टिनेंट कैमरून एडिनबर्ग ने बताया कि यह गिरफ्तारी इसी महीने अवैध शरणार्थियों की घुसपैठ में संलिप्त दो नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बाद की गई।

मैं करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत माता की जय।

— गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

शतरंज टूर्नामेंट से जुड़ा परिंकर का नाम

पणजी : गोवा सरकार ने राज्य में होने वाले अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर परिंकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। सावंत ने राज्य में होने वाला अंतरराष्ट्रीय वार्षिक शतरंज टूर्नामेंट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर परिंकर के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने राज्य में शिक्षा और खेल को बढ़ावा दिया।

न्यूज गैलरी

निखत, दीपक समेत पांच मुक्केबाज फाइनल में

नई दिल्ली : पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निखत जरीन (51 किग्रा) शुक्रवार को बैंकॉक में चल रहे थाइलैंड अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज रहीं जबकि एशियाई रजत पदक विजेता दीपक सिंह (49 किग्रा) सहित चार पुरुष मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। दीपक के अलावा आशीष कुमार (75 किग्रा), मुहम्मद हसमुद्दीन (56 किग्रा) और ब्रजेश यादव (81 किग्रा) स्वर्ण पदक मुकाबला खेलेंगे। हालांकि पूर्व एशियाई युवा रजत पदकधारी आशीष (69 किग्रा) अपनी सेमीफाइनल बाउट में हार गए जिससे उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हैदराबाद की निखत ने थाइलैंड की जूटामास जिटपोंग के खिलाफ अपने लगातार पंच से प्रभावित किया और स्थानीय प्रबल दावेदार को 4–1 से शिकस्त दी। हसमुद्दीन (56 किग्रा) ने थाइलैंड के अमारित याओदाम पर 3–2 से जीत हासिल की। आशीष ने 75 किग्रा में उज्बेकिस्तान के फनत काखरामनोव को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ब्रजेश ने थाइलैंड के सारानोन क्लोमपियन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक के मुकाबले में पहुंचे। (प्रेट्र)

राजस्थान रॉयल्स ने स्टालेकर को बनाया सलाहकार

मुंबई : आइपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी लीजा स्टालेकर को अपने जूनियर प्रोग्राम के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। रॉयल्स ने पिछले वर्ष बालकों के लिए रॉयल्स कॉल्ट्स और बालिकाओं के लिए रॉयल स्पार्क्स कार्यक्रम लांच किया था। पिछले वर्ष जयपुर में करीब 3000 बच्चों ने ट्रायल में हिस्सा लिया था। इसके बाद चुने गए बच्चों को नागपुर में कैंप करने का मौका दिया गया था। (प्रेट्र)

सिर में चोट की वजह से मुक्केबाज की मौत

ब्यूनस आयर्स : अर्जेंटीना के मुक्केबाज हुगो सांटिलान की गुरुवार को बाउट के दौरान सिर में चोट लग गई थी। शनिवार को हुगो का निधन हो गया। पिछले दो दिनों में सिर में चोट लगने के कारण मौत का यह दूसरा मामला है। इससे पहले अमेरिका में रूस के मैक्सिम दादाशेव का बाउट के दौरान सिर में चोट लगने से निधन हो गया था। 23 वर्षीय सांटिलान उरुग्वे के एडुआर्डो अबरियू के खिलाफ दस राउंड तक चले ड्रॉ मुकाबले में परिणाम घोषित होते ही रिंग में गिर पड़े थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनके सिर में गंभीर चोट थी। (एएफपी)

माइ टीम–11 बना भारत–विंडीज सीरीज का प्रायोजक

नई दिल्ली : भारत के फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में से एक–माइटीम11 भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच वेस्टइंडीज में होने वाली टेस्ट, वनडे और टी–20 सीरीज का मुख्य प्रायोजक बन गया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने माइ टीम11 को मुख्य प्रायोजक के तौर पर चुना है और इस करार के बाद इस सीरीज का नाम माइ टीम11 अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगा। इस दौरे की शुरुआत अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाले टी–20 मैचों के साथ होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग माइ टीम11 के ब्रांड एंबेसडर हैं। (आइएएनएस)

नेशनल रैली का पहला दौर शनिवार से

कोयंबटूर : जेके टायर–एफएमएससीआइ नेशनल रैली चैंपियनशिप 2019 (जेकेएनआरसी) के 22वें संस्करण का पहला दौर शनिवार से शुरू होगा, जबकि समापन रविवार को होगा। इस साल इस चैंपियनशिप में देश के कई युवा चालक हिस्सा ले रहे हैं और इस साल नए प्रतिभाशाली चालकों को खोजने का लक्ष्य रखा गया है। चैंपियनशिप के 22वें संस्करण को नए सिरे से तैयार किया गया है। इसमें इंडियन फॉर्मूला एलजीबी–4 और एलजीबी नोवाइस कप को प्रमुख आकर्षण के तौर पर स्थापित किया गया है। (आइएएनएस)

अजीब तरीके से आउट हुए युवराज सिंह

टोरंटो, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद अपना पहला मैच खेलने उतरे युवराज सिंह के लिए ग्लोबल टी-20 कनाडा की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गुरुवार को टोरंटो नेशनल्स की ओर से खेलते हुए युवराज संघर्ष करते नजर आए। युवराज की कप्तानी वाली टोरंटो को क्रिस गेल की टीम वेंकुवर नाइट्स के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। इस दौरान युवराज 27 गेंदों में महज 14 रन बना सके और बहुत अजीब तरीके से आउट होकर पवेलियन लौटे।

पारी के 17वें ओवर में रिजवान चीमा की गेंद युवी के बल्ले का किनारा लेती हुए विकेटकीपर के दस्तानों में गई लेकिन विकेटकीपर टोबायस विसे ने वह आसान सा कैच टपका दिया। हालांकि गेंद उनके दस्तानों से लगकर स्टंप्स से टकरा गई। युवराज का पैर क्रीज के अंदर था लेकिन वह ऑन-फील्ड अंपायर द्वारा फैसला देने से पहले ही बाहर चले गए। युवराज की टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 159 रन बनाए लेकिन गेल की टीम ने 2.4 ओवर पहले ही दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

इंस्टाग्राम तक पहुंचा विराट कोहली–रोहित शर्मा विवाद

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में मतभेद खुलकर सामने आए थे और दैनिक जागरण ने उसे सबसे पहले आपके सामने भी रखा था। अब यह विवाद सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और वनडे व टी-20 टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा के बीच आपसी मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गए जब रोहित ने सोशल साइट इंस्टाग्राम से विराट की पत्नी और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा को अनफॉलो कर दिया।

विराट और रोहित इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे लेकिन अब यह स्पष्ट दिखने लगा है कि टीम में खटास है। 32 वर्षीय रोहित, विराट को भी कुछ समय से इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं लेकिन मजेदार बात यह है कि विराट अभी भी रोहित को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं। हालांकि रोहित की पत्नी रितिका सजदेह भारतीय कप्तान को फॉलो नहीं करती हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर अनुष्का भी ना तो रोहित को और ना ही उनकी पत्नी रितिका को फॉलो करती हैं। इंग्लैंड में हुए विश्व कप के दौरान दैनिक जागरण ने आपको बताया था कि अंबाती रायुडू को 15 सदस्यीय टीम में नहीं चुनने, विजय शंकर के चयन और अंतिम-11 में खराब प्रदर्शन के बावजूद कुछ खिलाड़ियों के चयन से टीम इंडिया में मतभेद हैं। विश्व कप में रोहित ने शानदार प्रदर्शन किया था और रिकॉर्डतोड़ पांच शतकों जड़े थे। वहीं विराट ने भी पांच अर्धशतक जड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था।

वाद–विवाद

- रोहित ने विराट की पत्नी अनुष्का को किया इंस्टाग्राम से अनफॉलो
- सीओए ने टीम इंडिया में दरार से किया इन्कार

अनुष्का का पलटवार : रोहित शर्मा द्वारा अनफॉलो किए जाने के बाद अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसने आग में घी डालने का काम किया। अनुष्का ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की जिसमें उन्होंने उपकप्तान रोहित को निशाना बनाया है। अनुष्का ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि एक बुद्धिमान इंसान ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। सच कभी झूठ के दिखावे में नहीं पड़ता है।

सीओए का इन्कार : भारतीय कप्तान और उपकप्तान के बीच दरार की खबरों को प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने निराधार बताया है। विराट और रोहित के बीच विवाद को लेकर किए गए सवाल को बेबुनियाद बताते हुए विनोद राय ने कहा कि ये सभी कहानियां मीडिया द्वारा गढ़ी जा रही हैं। सीओए ने कहा कि जब तक दोनों में से कोई एक खिलाड़ी इस मुददे को लेकर सवाल नहीं उठाता तब तक इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

विजय ▶ पहली पारी में 85 रन पर ढेर होने के बाद एकमात्र चार दिवसीय टेस्ट में इंग्लैंड ने 143 रनों से दी शिकस्त

आयरलैंड 38 रन पर ढेर, इंग्लैंड ने जीता टेस्ट

ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने झटके छह विकेट

लंदन, रायटर : इंग्लैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां लॉर्ड्स स्टेडियम में खेले गए चार दिनों के एकमात्र टेस्ट मैच की दूसरी पारी में आयरलैंड को महज 38 रनों पर समेटकर 143 रनों से जीत दर्ज की। मेजबान टीम के दिए 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के तीसरे दिन मेहमान टीम 15.4 ओवर में केवल 38 रन ही बना सकी, जो टेस्ट क्रिकेट में उसका अबतक का सबसे कम स्कोर है।

टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में किसी टीम का यह पांचवां सबसे कम कुल स्कोर है। न्यूजीलैंड के नाम क्रिकेट के पारंपरिक प्रारूप में सबसे कम रन (26) बनाने का रिकॉर्ड है। दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने सबसे अधिक छह विकेट चटकाए जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड को चार विकेट मिले। आयरलैंड के लिए सबसे अधिक रन जेम्स मैकलम (11) ने बनाए। उनके अलावा और कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया।

मेहमानों की खराब शुरुआत : लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 11 के स्कोर पर कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड (2) के रूप में पहला विकेट खोया। इसके बाद, पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड की धारदार तेज गेंदबाजी के आगे नहीं टिका। आयरलैंड के तीन बल्लेबाज पीटर स्टर्लिंग, गैरी विल्सन और एंडी मैकब्रायन खाता भी नहीं खोल सके थे। आयरलैंड की टीम चौथी पारी में 16 ओवर भी नहीं खेल सकी और एक सत्र में ही 38 रनों पर ऑलआउट हो गई। वोक्स ने सबसे ज्यादा छह विकेट। वहीं ब्रॉड ने चार विकेट चटकाए।

इससे पहले, मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 303 रन बनाए। बारिश से प्रभावित मैच के तीसरे दिन पहले सत्र में ही इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई थी। दूसरी पारी में 92 रनों की दमदार पारी खेलने वाले जैक लीच को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्रॉड 21 रन बनाकर नाबाद रहे थे। मैच की पहली पारी में इंग्लैंड महज 85 रनों पर सिमट गई थी। आयरलैंड ने पहली पारी में 207 रन बनाकर 122 रनों की बढ़त हासिल की थी। हालांकि, गेंदबाजों की सधी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड को एक शर्मनाक हार से बचा लिया। इंग्लैंड को एक अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज भी खेलनी है।

111 वर्षों में कोई टीम भी टीम पहली पारी में 85 या उससे कम स्कोर पर ऑलआउट होने के बाद टेस्ट मैच नहीं जीती है

0 रनों पर चारों पारियों में आउट हुए दोनों टीमों के छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए बल्लेबाज

जैक लीच के पिता नहीं देख पाए बेटे की पारी

लॉर्ड्स : इंग्लैंड के जैक लीच घर में अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे, लेकिन ज्यादा गर्मी होने के कारण लीच के पिता बेटे की शानदार पारी देखने से चूक गए। लीच ने आयरलैंड के खिलाफ 92 रन की पारी खेली थी।

कुछ लोग बल्लेबाजों के हीरो बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बायें हाथ के स्पिनर लीच ने यह कारनामा कर दिखाया। नाइटवाचमैन के रूप में वह गुरुवार को बल्लेबाजी करने उतरे थे। हालांकि लीच के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दो अर्धशतक हैं। उन्होंने करीब तीन घंटे बल्लेबाजी करके इंग्लैंड को 181 रनों की अहम बढ़त दिलाई। लीच ने बताया कि कैसे उनके पिता उनकी पारी देखने से चूक गए। उन्होंने कहा कि वह मैच देखने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने मौसम का पूर्वानुमान देखा, जो बहुत गर्म था। मुझे नहीं लगता कि यह यहां आना उनके लिए अच्छा होता, मुझे लगता है कि उनका घर पर रहना ही अच्छा रहा। मैंने उन्हें अपने घर की चाभी दी और उन्होंने टीवी पर सारा मैच देखा। लीच 100 रन तक नहीं पहुंच सके। इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि नर्वस 90 में मैं आउट हो सकता हूं। आप सोचते हो कि मैं शतक से सिर्फ दो शॉट दूर हूं और मेरे दिमाग में भी यह सब चल रहा था।

टेस्ट में सबसे कम स्कोर

टीम	स्कोर	बनाम	वर्ष
न्यूजीलैंड	26	इंग्लैंड	1955
द. अफ्रीका	30	इंग्लैंड	1896
द. अफ्रीका	30	इंग्लैंड	1924
द. अफ्रीका	35	इंग्लैंड	1899
द. अफ्रीका	36	ऑस्ट्रेलिया	1932
ऑस्ट्रेलिया	36	इंग्लैंड	1932
आयरलैंड	38	इंग्लैंड	2019

छह विकेट लेने वाले क्रिस वोक्स। एपी

पूरी तरह फिट हुआ तो विश्व चैंपियनशिप में खेलूंगा : नीरज

अनिल भारद्वाज, गुरुग्राम : भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा मैदान पर वापस लौट आए हैं। मई में कोहनी की सर्जरी के बाद नीरज ने दोबारा प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अक्टूबर में दोहा (कतर) में विश्व एथलीट चैंपियनशिप खेलने के लिए पूरी कोशिश है लेकिन वह तभी खेलेंगे, जब पूरी तरह फिट होंगे।

उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी स्थित जीएसडब्ल्यूडी सेंटर में प्रशिक्षण लेना शुरू किया है। नीरज का कहना है कि जिम के साथ हल्का प्रशिक्षण शुरू किया है। उनके पास खुद को फिट करने के लिए दो माह का समय है। नीरज ने कहा कि उनके सामने दुविधा की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इस समय उनके सामने दो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं। इन दोनों प्रतियोगिताओं में खेलना चाहते हैं लेकिन सब कुछ फिटनेस पर निर्भर करेगा। चोपड़ा ने कहा कि वह 2020 टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के बीच में कोई अड़चन नहीं आने देना चाहते। वह 2018 एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों के अलावा जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। नीरज ने दो मई को मुंबई के जाने-माने डॉ. दिनेश पर्डिवाला से कोहनी की सर्जरी कराई थी। पटियाला (पंजाब) में उन्हें प्रशिक्षण के दौरान चोट लगी थी जिसके बाद दर्द बढ़ रहा था जिसके बाद छोटी सी सर्जरी कराई थी।

पीवी सिंधू हारीं, बी साई प्रणीत सेमीफाइनल में पहुंचे

बैडमिंटन

▶ जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारीं पीवी, साई की आसान जीत

टोक्यो, प्रेट्र : ओलंपिक में देश को रजत पदक दिला चुकीं दिग्गज भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधू जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हारकर बाहर हो गई जबकि बी साई प्रणीत ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए शुक्रवार को सेमीफाइनल में जगह बनाई।

सिंधू को स्थानीय खिलाड़ी अकाने यामागुची ने लगातार दूसरी बार हराया। 50 मिनट तक चले महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में सिंधू को 18-21, 15-21 से पराजय झेलनी पड़ी। पिछले सप्ताह इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में भी यामागुची ने सिंधू को मात दी थी। उधर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रणीत ने इंडोनेशिया के टामी सुगिआर्तो को 21-12, 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां उनका सामना जापान के केंतो मोमोता से होगा। सिंधू पहले गेम में 12- 7 से आगे चल रही थीं लेकिन एशियन चैंपियन ने जल्दी ही वापसी करते हुए स्कोर को 14-14 कर दिया। इसके बाद यामागुची ने 18-15 और फिर 20-16 से बढत बना ली। सिंधू ने लगातार दो अंक लेकर अंतर को 18-20 किया लेकिन यामागुची ने अगला अंक लेकर पहला गेम अपने नाम किया।

पीवी सिंधू, फाइल फोटो, एपी

दूसरे गेम में शुरू में स्कोर 6-6 था लेकिन बाद में यामागुची ने लगातार दबाव बनाने लगीं और बिना किसी परेशानी के जीत दर्ज की। दूसरी ओर साई प्रणीत ने महज 36 मिनट में आसानी से मुकाबले को अपने नाम किया। पहले गेम में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता को कोई मौका नहीं दिया। दूसरे गेम में छोड़ा रोमांच पैदा हुआ लेकिन प्रणीत ने शुरुआत से ही अपनी बढ़त बरकरार रखी और अंत में 18-15 के स्कोर के बाद भारतीय शटलर ने लगातार तीन अंक लेकर मुकाबले को अपने नाम किया।

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच बने रह सकते हैं अरुण

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा गेंदबाजी कोच भरत अरुण का उनके पद पर बने रहना करीब-करीब तय माना जा रहा है जबकि दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज जोंटी रोड्स समेत कई दावेदारों के होने के बावजूद फील्डिंग कोच आर श्रीधर को तरजीह मिलने की संभावना है। हालांकि जब राष्ट्रीय चयनकर्ता भारतीय टीम के लिए सहयोगी स्टाफ चुनेंगे तो बल्लेबाजी कोच संजय बांगर की छुट्टी हो सकती है।

तीनों (भरत अरुण, आर श्रीधर और संजय बांगर) को मुख्य कोच रवि शास्त्री के साथ आगामी वेस्टइंडीज दौरे के आखिर तक कार्यकाल में विस्तार मिला है। इसके बाद नए सिरे से टीम के कोच और सहयोगी स्टाफ के लिए साक्षात्कार होंगे और सभी पदों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। कपिल देव की अध्यक्षता वाली नई क्रिकेट सलाहकार समिति मुख्य कोच के बारे में फैसला लेगी। चयनकर्ताओं को सहयोगी स्टाफ के लिए साक्षात्कार लेने को कहा गया है।

सूत्रों की मानें तो अरुण का रहना करीब-करीब तय है क्योंकि सभी प्रारूपों में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पिछले 18 से 20 महीने में अरुण ने बहुत अच्छा काम किया है। मौजूदा भारतीय गेंदबाजी आक्रमण टेस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मुहम्मद शमी फॉर्म में हैं और जसप्रीत बुमराह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जिसका श्रेय अरुण को जाता है। चयनकर्ताओं के लिए उनकी जगह किसी और को तरजीह देना मुश्किल होगा। हालांकि बांगर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई लोगों का मानना है कि चार साल पद पर रहने के बावजूद वह मजबूत मध्य क्रम नहीं तैयार कर सके। अधिकारी ने कहा कि बांगर के आने से पहले भी रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी सफलता में बांगर का कोई योगदान नहीं है। उनका काम मध्य क्रम को मजबूत बनाना था और विश्व कप में हमने देखा कि वह इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। तीनों विशेषज्ञ कोचों में से अरुण का पद पर बने रहना तय है और श्रीधर भी चयनकर्ताओं की पसंद होंगे। हालांकि उन्हें रोड्स से कड़ी चुनौती मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि रोड्स बड़ा नाम है और उसकी दावेदारी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालांकि हमें टीम का अब तक क्षेत्ररक्षण में प्रदर्शन भी देखना होगा।

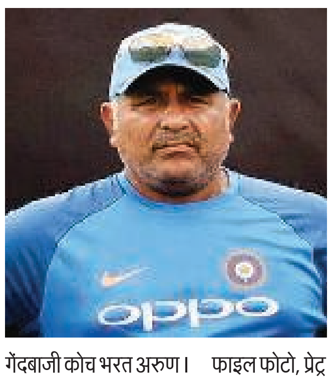

गेंदबाजी कोच भरत अरुण। फाइल फोटो, प्रेट्र

मेरी नियुक्ति से मिलेगी महिला क्रिकेट को सम्मान और पहचान : रंगास्वामी

नई दिल्ली : पुरुषों की सीनियर टीम को चुनने के लिए नियुक्त की गई क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल होने पर पूर्व महिला क्रिकेटर शांता रंगास्वामी ने अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि इससे पूरे महिला क्रिकेट को सम्मान और पहचान मिलेगी। रंगास्वामी ने कहा कि यह ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे महिला क्रिकेट जगत के लिए सम्मान की बात है।

कपिल देव की अगुआई वाली समिति चुनेगी नया कोच

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) ने शुक्रवार को यहां अपनी बैठक में फैसला किया कि कपिल देव की अगुआई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) को भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कोच को चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति में कपिल के अलावा पूर्व भारतीय कोच अंशुमन गायकवाड़ और महिला टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी भी शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि नये कोच के लिए अगस्त के मध्य में साक्षात्कार लिए जाएंगे। बैठक के बाद सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा कि ये तीनों नए कोच को चुनेंगे। यह एक एड–हॉक संस्था नहीं है। यह कानूनी तौर पर की गई नियुक्ति है, लेकिन हितों के टकराव के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। इसके लिए साक्षात्कार संभवत: 13 या 14 अगस्त को लिए जाएंगे। विराट कोहली का नए कोच की नियुक्ति में कोई योगदान नहीं रहेगा। नए सपोर्ट स्टाफ के बारे में चयनकर्ता फैसला लेंगे। राय ने कहा कि विश्व कप के प्रदर्शन पर कोई समीक्षा बैठक नहीं होगी, लेकिन मैनेजर सुनील सुब्रहमण्यम की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। मुख्य कोच और सपोर्ट स्टाफ के लिए आवेदन देने की अंतिम तारीख 30 जून है। सीओए जल्द ही न्याय मित्र से मिलकर चर्चा करेगी कि क्या गांगुली, लक्ष्मण आइपीएल फ्रेंचाइजी में पद पर बैठे हुए कमेंट्री कर सकते या नहीं।

सवाल

बजरंग के वर्ग में श्रवण का नहीं लिया गया ट्रायल, ट्रायल में जीतकर पूनिया ने विश्व चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई

कुश्ती संघ की मदद से आगे बढ़े पहलवान बजरंग पूनिया

योगेश शर्मा, नई दिल्ली

एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया यहां केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम में शुक्रवार को हुए विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल में पास जरूर हो गए लेकिन उनको पास कराने में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) का अहम योगदान रहा। उनके ट्रायल पर सवाल इसलिए उठा क्योंकि डब्ल्यूएफआइ ने उनके भार वर्ग 65 किग्रा फ्रीस्टाइल में श्रवण कुमार को ट्रायल में हिसा लेने से रोक दिया। यह विश्व चैंपियनशिप कजाखिस्तान के अस्ताना में 14 से 22 सितंबर को होगी।

डब्ल्यूएफआइ अपने पदक के दावेदार बजरंग को आसानी से विश्व चैंपियनशिप का टिकट देना चाहता था जिसके लिए उसने बजरंग के खिलाफ अन्य पहलवानों को आगे आने नहीं दिया। इसके कारण विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता बजरंग और हरफूल ही 65 किग्रा भार वर्ग में बचे। बीच मुकाबले में हरफूल के हटने के कारण बजरंग ने आसानी से क्वालीफाई कर लिया। श्रवण जूनियर से सीनियर कुश्ती में आए हैं। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, जूनियर एशिया चैंपियनशिप और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले श्रवण का बजरंग के खिलाफ पिछले साल भिवानी में एक करोड़ के इनामी दंगल में मुकाबला हुआ था जहां बजरंग मैच जीतने में सफल हुए थे। उनके खिलाफ भी श्रवण ने चार अंक हासिल किए थे। वहीं, शुक्रवार को हरफूल के खिलाफ भी बजरंग को यह मैच दूसरे राउंड तक खेलना पड़ा जबकि वह पहले राउंड में मैच को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। हरफूल को दूसरे राउंड में बायें पैर में चोट लगने के कारण मैच को बीच में छोड़ना पड़ा और उस दौरान बजरंग 7-0 से आगे चल रहे थे। इसके बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया। फिलहाल 74 किग्रा भार वर्ग के ट्रायल अभी नहीं हुए हैं। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार इस वर्ग में ही उतरते हैं। इस वर्ग के अन्य पहलवानों की चोट को देखते हुए यह ट्रायल अगस्त तक टाल दिए गए हैं।

भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया। फाइल फोटो, प्रेट्र

छत्रसाल स्टेडियम का छाया जादू

नई दिल्ली : शुक्रवार को फ्रीस्टाइल के पांच वर्गों के ट्रायल हुए जिसमें तीन वर्गों में छत्रसाल स्टेडियम के पहलवानों ने बाजी मारी। 57 किग्रा में रवि कुमार, 86 किग्रा में दीपक पूरनिया और 125 किग्रा में सुमित ने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। इनके गुरु महाबली सतपाल ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में छत्रसाल स्टेडियम से ही कोई पहलवान पदक लाएगा और इसके लिए मैं प्रतिदिन तैयारी करवा रहा हूं। मुझे खुशी है कि इन तीनों ने क्वालीफाई किया और सुशील भी क्वालीफाई करेगा।

साक्षी और गीता के पति हारे

नई दिल्ली : विश्व चैंयिनशिप के इन ट्रायल में अनुभवी पहलवानों पर युवा जोश भारी पड़ गया और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और गीता फोगाट को भी निराशा हाथ लगी जब उनके पति विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए। दिन का पहला उलटफेर राहुल ने सेमीफाइनल में किया जब उन्होंने ओलंपियन और एशियाई चैंपियन संदीप को 4–1 से हरा दिया। हालांकि वह फाइनल में रवि से एकतरफा मुकाबले में 2–12 से हार गए। 97 किग्रा में सबसे बड़ी उम्मीद साक्षी मलिक के पति सत्यवर्त कादियान से थी लेकिन वह फाइनल में मौसम खत्री से हार गए। खत्री ने एकतरफा अंदाज में कादियन को 8–1 से हरा दिया। वहीं, 86 किग्रा में गीता फोगाट के पति पवन भी एक युवा उभरते पहलवान दीपक पूनिया के युवा जोश के आगे बेदम नजर आए। दीपक ने यह मुकाबला 5–0 से जीतकर पहली बार विश्व चैंपियनशिप के दल में अपनी जगह बनाई। 125 किग्रा में कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता सुमित ने फाइनल में सतेंद्र को 3–0 से हराकर क्वालीफाई किया।

मुझे पहले पता चला था कि मेरे वर्ग में पांच पहलवान होंगे और मैं उसी हिसाब से तैयारी कर रहा था लेकिन जब ट्रायल के ड्रॉ में देखा तो सिर्फ हरफूल का ही नाम था। मुझे नहीं पता कि श्रवण को मौका क्यों नहीं दिया। इन चीजों का जवाब डब्ल्यूएफआइ देगा। मुझे हरफूल से खेलना था तो मैंने उस हिसाब से अपनी तैयारी की।

— बजरंग पूनिया

मुझे आखिरी समय पर मुकाबला लड़ने से रोक दिया गया। मैंने दो दिन पहले भी डब्ल्यूएफआइ के सहायक सचिव विनोद तोमर से बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ट्रायल में है लेकिन वजन कराने के ठीक पहले उन्होंने कहा कि तुम 57 या फिर 70 किग्रा भार वर्ग में लड़ लो। मैंने जब कहा कि यह संभव नहीं है तो उन्होंने कहा कि जिसने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है, हम उसी का ट्रायल लेंगे। सच्चाई यह है कि शुक्रवार को जितने भी ट्रायल हुए उसमें कई पहलवान ऐसे हैं जिनके नाम पर अभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण नहीं है। मैं तैयारी के साथ आया था लेकिन अब निराश हूं।

— श्रवण कुमार

श्रवण पिछले एक साल से किसी टूर्नामेंट में नहीं खेला है और ऐसे में हम उसे मौका नहीं दे सकते। बजरंग से हमें ओलंपिक पदक की उम्मीद है और हम उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। श्रवण कैंप में भी नहीं था और ऐसे में हमने उसे अनुमति नहीं दी।

— विनोद तोमर, सहायक सचिव, डब्ल्यूएफआइ

7.5 करोड़ लोग दुनियाभर में एचआइवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएंसी वायरस) से संक्रमित हो चुके हैं। हर साल 17 लाख लोग या तो इस वायरस से संक्रमित होते हैं या एचआइवी पॉजिटिव पाए जाते हैं।

बहुत पुराना रहा है बंदूक और बल्ले का नाता

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी टेरिटोरियल आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा हैं। क्रिकेट से दो महीने का ब्रेक लेकर धौनी इस यूनिट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्हें कश्मीर घाटी में पोस्टिंग दी गई है। 31 जुलाई से 15 अगस्त तक वे कश्मीर घाटी में रहकर पैट्रोलिंग टीम का हिस्सा होंगे। सीमा पर गश्त करने के अलावा वे सैनिकों के साथ समय भी बिताएंगे। इससे पहले भी तमाम ऐसे वाकए रहे हैं जिसमें क्रिकेट खिलाड़ियों ने बल्ला छोड़कर देश की रक्षा के लिए बंदूक पकड़ते हुए सेना का हिस्सा बने। देश-दुनिया के ऐसे मामलों पर पेश है एक नजर:

कर्नल कोट्टैरी कनकैया नायुडू

भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान केसी नायुडू 1923 में होल्कर राजा के न्योते पर इंदौर पहुंचे थे। होल्कर के राजा ने उन्हें अपनी सेना में कर्नल का पद दिया था।

लेफ्टिनेंट कर्नल हेमू अधिकारी

लेफ्टिनेंट कर्नल हेमू का टेस्ट करियर दूसरे विश्व युद्ध के कारण देर से शुरू हुआ। उन्होंने 29 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। उनके समय में खेले गए कुल 47 टेस्ट मैचों में वे सिर्फ 21 में ही भाग ले सके।

सर डॉन ब्रैडमैन

दुनिया के महान बल्लेबाज ब्रैडमैन एक साल के लिए लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत रहे। वह जून, 1940 में ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना में शामिल हुए। बाद उनका ट्रांसफर सेना में कर दिया गया। कुछ समय ट्रेनिंग के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट का पद दिया गया, लेकिन कमर की बीमारी के चलते उन्हें जून, 1941 में सेवामुक्त कर दिया गया।

सर लेन हटन

इंग्लैंड के बल्लेबाज हटन ने अपना 23वां और 29वां जन्मदिन सेना के ट्रेनिंग सार्जेंट के रूप में मनाया। इसी पद पर काम करते हुए उनकी कलाई में चोट लग गई। इसी वजह से वह अपने करियर में हुक शॉट नहीं खेल पाए।

युद्धबंदी के रूप में हुई मौत

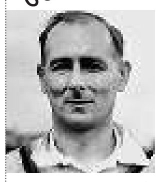

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई प्रथम-श्रेणी क्रिकेटर्स को लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ा। उस समय जंग देश के लिए पहली प्राथमिकता थी। इंग्लैंड के बाएं हाथ के स्पिनर हेडली वेरिटी (ब्रैडमैन को सर्वाधिक 8 बार आउट करने वाले) की मौत 1943 मे इटली में युद्धबंदी के रूप में हुई।

युद्ध के दौरान खेले मैच

डेनिस कांपटन ने युद्ध के दौरान इंग्लैंड के लिए 14 टेस्ट मैच खेले। इसके अलावा भारत में 17 प्रथम श्रेणी मैच भी खेले। इसी दौरान सार्जेंट मेजर के पद पर काम करते हुए उन्होंने जापान के खिलाफ युद्ध में अपने सैनिकों को तैयार किया। कांपटन ने अपने करियर में कुल 78 टेस्ट मैच खेले। बल्ले और बंदूक से कमाल दिखाने में पीछे नहीं रहे।

शानदार पायलट थे मिलर

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कीथ मिलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बतौर पायलट अपनी सेवाएं दी थीं। वह एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। उनके लुक्स के लोग दीवाने थे और उनका संगीत भी शानदार था।

अन्य भारतीय क्रिकेटर

इसके अलावा चंद्रशेखर गडकरी, नारायण स्वामी, रमन सुरेंद्रनाथ, अपूर्व सेनगुप्ता और वेंटप्पा मुद्दीआ ने भी सेना और क्रिकेट दोनों जगह सेवाएं दीं।

धौनी को नहीं सुरक्षा की दरकार, वह करेंगे लोगों की रक्षा : रावत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और टेरीटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी को कश्मीर में कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिलेगी। न ही हमें लगता है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। वह एक सैन्य अधिकारी के तौर पर यहां तैनात रहेंगे और वही काम करेंगे जो उनकी रैंक के अधिकारी की जिम्मेदारी है। धौनी कश्मीर में सामान्य सैनिक की तरह ही आम लोगों के रक्षक की भूमिका में रहेंगे।

महेंद्र सिंह धौनी इसी महीने 31 जुलाई से 15 अगस्त तक दक्षिण कश्मीर में सेना की 106 टीए बटालियन में एक्टिव आर्मी ड्यूटी निभाने के लिए आ रहे हैं। वह इसी यूनिट के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। जबसे उनके सेना के साथ कश्मीर में ड्यूटी देने की खबर आई है, कइयों ने उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं जताई हैं।

अपनी जिम्मेदारी जानते हैं धौनी : थलसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को द्रास में इस संदर्भ में पूछे जाने पर कहा कि महेंद्र सिंह धौनी दक्षिण कश्मीर में विक्टर फोर्स के साथ तैनात रहेंगे। वह सेना की जिम्मेदारियों से अच्छी तरह अवगत हैं, वह सेना के साथ अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसी अन्य सैनिक की तरह वह एक रक्षक की भूमिका निभाएंगे।

मुझे नहीं लगता उन्हें सुरक्षा की जरूरत है : जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जब कोई भारतीय नागरिक सेना की वर्दी पहनता है तो उसे वह सारे काम करने होते हैं जो उसकी वर्दी के साथ मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि धौनी ने बेसिक ट्रेनिंग की है और हमें पूरा यकीन है कि वह अपनी जिम्मेदारियों और कार्य को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब महेंद्र सिंह धौनी बहुत सारे लोगों की सुरक्षा का जिम्मा निभाएंगे, क्योंकि वह पैरा की 106 टीए बटालियन में लेफ्टिनेंट कर्नल की भूमिका निभाने जा रहे हैं। गौरतलब है कि यह बटालियन संचार व्यवस्था बहाल रखने, सुरक्षा कवच प्रदान करने की ड्यूटी बखूरी निभा रही है। अब धौनी भी इसका हिस्सा होंगे।

पानी, पानीपूरी, पंचायत व पाठशाला का कमाल

कायाकल्प ▶ ग्राम स्वावलंबन का प्रेरक उदाहरण बना उत्तर प्रदेश के जालौन का इटौरा अकबरपुर गांव

जागरण विशेष

बृजेश दुबे, कानपुर

सुविधा और सोच, समरसता और समन्वय कैसे किसी गांव की दशा और दिशा बदल सकते हैं, जालौन, उत्तर प्रदेश की कालपी तहसील का इटौरा अकबरपुर गांव इसकी मिसाल पेश कर रहा है। पंचायती राज और ग्राम स्वावलंबन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समृद्धि इस गांव को देश दुनिया में प्रसिद्ध कर रही है।

यह विरासत में नहीं मिला है। रोजगार के लिए गांव छोड़ने के बाद भी अपनी जड़ से जुड़े रहने की मंशा और एक युवा प्रधान की सोच ने पूरे गांव का नक्शा बदल दिया। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में चार सौ से अधिक परिवारों के लोग पानीपूरी का बिजनेस कर गांव के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। 85 फीसद से अधिक घरों में पाइप लाइन के जरिये जलापूर्ति है। 7000 लीटर क्षमता के तीन सोलर वाटर टैंक भी साफ पानी दे रहे हैं। गांव के एक दर्जन प्राइमरी स्कूल, दो इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज आसपास के डेढ़ दर्जन गांवों को शिक्षा मुहैया करा रहे हैं।

सुशासन के चलते पंचायत आन सोर्स रेवेन्यू (ओएसआर) के तहत हर साल एक लाख रुपये से अधिक आय अर्जित कर रहा है। सरीला-जाल्हूपुर हाईवे पर स्थित इस गांव की कारोबारी महत्ता वाली ग्राम समाज की बड़ी जमीन से अवैध कब्जे हटवाकर पार्क, श्मशान भूमि, यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए। नौ दुकानें बनवाकर बेरोजगारों को मामूली किराए पर दीं। यात्री प्रतीक्षालय बनने से वाहन रुक रहे। इससे करीब सौ ठेल के जरिये ग्रामीणों को रोजगार मिला।

24 घंटे सफाई के लिए तैयार रहने वाले इस गांव में मर रहे तालाब को जीवित कर नौका विहार का केंद्र बनाया ही, कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले को वृहद और व्यस्थित कर उससे पंचायत की आय बढ़ाई। गांव का हर खर्च ऑनलाइन है। सभी काम ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही होते हैं।

सेवा के बदले यूजर चार्ज के सिद्धांत पर ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं पा रहे हैं। पंचायत सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के ग्राम प्रधान अमित द्विवेदी 'इतिहास' को दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित कर ग्राम विकास के लिए 12 लाख रुपये भी दिए हैं। ग्राम प्रधान को समरसता, पंचायत विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।

पानी से शुरू हुई पानीदार होने की विकास गाथा : इस गांव को 27 साल पहले कृषि मंत्री चौधरी शंकर सिंह ने पाइप लाइन जलापूर्ति का तोहफा दिया था। दो साल पहले ग्राम प्रधान ने तीन सोलर वाटर टैंक लगवाए। स्वच्छ पेयजल मुहैया होने से यहां डायरिया, कॉलरा से कभी कोई मौत हुई हो, किसी को याद नहीं। गांव में फ्लोराइड, क्लोराइड जनित बीमारी के एक भी मरीज नहीं है। दरअसल लोगों ने अपनी जागरूकता और सुधार की कोशिश के साथ तमाम समस्याओं को पहले ही उभरने से दूर कर दिया है। उन्हें अब अपनी कोशिशों का सार्थक परिणाम मिलने लगा है।

ये हैं यूजर चार्ज : 15-15 रुपये सालाना पर सोलर स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप से पेयजल, ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की कॉपी, 50 रुपये में दुकानों का पंजीयन, 500 रुपये में भवन निर्माण एवं खरीद की एनओसी समेत कई सुविधाएं

समरसता भवन बढ़ा रहा सौहार्द : ग्राम प्रधान अमित द्विवेदी ने ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटाकर समरसता भवन एवं पार्क बनवाया। हर माह सभी वर्ग के लोग घर से खाद्य सामग्री लाकर यहां भोजन पकाते हैं। जाति-धर्म का भेद छोड़कर एक साथ बैठकर खाते हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/ jagran-special

विकास की राह पर दौड़ता गांव

1600 परिवारों में 1300 के पास पक्के मकान

400 परिवारों के पक्के मकान पानीपूरी के बिजनेस से

▶ ग्राम प्रधान की सोच से बज रहा देश दुनिया में डंका, मिले अनेक पुरस्कार

50 सभी पात्र लाभार्थी उच्वला रसोई गैस, शौचालय समेत पीएम आवास आदि सुविधाओं का उठा रहे लाभ

50 ट्रैक्टर, बीस निजी नलकूप

▶ गांव में शुरू की गई कई सेवाएं, इनके बदले देते हैं यूजर चार्ज

▶ पंचायत ऑनलाइन, सुशासन के साथ तमाम सुविधाएं सहज उपलब्ध

▶ गांव में बैंक की शाखा ही नहीं एटीएम तक की है सुविधा

जालौन जिले के इटौरा अकबरपुर गांव में पुनर्जीवन के बाद नौका विहार केंद्र बनाया तालाब।

इटौरा अकबरपुर गांव में पुनर्जीवित किया गया तालाब। जागरण

टपकते छप्पर, चूल्हे के धुएं से मिल गया छुटकारा

रेयाज की पत्नी गौसिया कहती हैं, पीएम आवास योजना में छत, रसोई गैस, शौचालय मिला तो टपकती छत और चूल्हे के धुएं से निजात मिली।

अवैध कब्जे हटाकर हमने राजस्व सृजित किया। बुनियादी योजनाओं का शतप्रतिशत अमल सुनिश्चित किया। ऑन सोर्स रेवेन्यू (ओएसआर) योजना भी ग्राम पंचायतों की ताकत बढ़ाती है। सभी को इसे अपनाना चाहिए।

-अमित द्विवेदी 'इतिहास', ग्राम प्रधान, अकबरपुर इटौरा, जालौन, उप्र।

उत्तराखंड सरकार ने बनाई गांवों में खुशहाली लाने की योजना

केदार दत्त, देहरादून : पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड में रीते होते गांवों को खुशहाल बनाने के लिहाज से राहतभरी खबर। सरकार 95 ब्लाकों वाले राज्य में इस साल प्रत्येक ब्लाक में एक गांव को कृषि के लिहाज से मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने जा रही है। फिर सरसब्ज गांव खुद बोलेंगे हां, 'मैं एक गांव हूं'। माहभर के भीतर प्रदेश सरकार 'आई एम ए विलेज' (मैं एक गांव हूं) योजना लांच करने जा रही है। इसके तहत पांच साल में 475 गांव चमकाने का लक्ष्य है।

घटती कृषि विकास दर और बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के बंजर में तब्दील होने से सरकार की पेशानी पर बल पड़े हैं। नौ साल पहले राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की जो भागीदारी सात फीसद थी, वह 4.67 फीसद पर आ गई है। अब तक करीब एक लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर में तब्दील हुई है। इसके पीछे पलायन सबसे बड़ी वजह है।

हालांकि, खेती-किसानी को संवारने के लिए किसानों की आय दोगुना करने की कवायद चल रही है, मगर इसके लिए कृषि को लाभकारी बनाना होगा। ग्रामीणों को खेती की तरफ उन्मुख करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है। इसी के दृष्टिगत कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की पहल पर खींचा गया 'मैं एक गांव हूं' योजना का खाका। इसके तहत अगले पांच साल तक हर ब्लाक में एक गांव को कृषि एवं उससे जुड़ी तमाम सुविधाओं से सुसज्जित कर मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।।

गांव ऐसे बनेंगे मॉडल : 'मैं एक गांव हूं' में चयनित गांव को विभिन्न योजनाओं के लिए दिए जाने वाले बजट से अतिरिक्त एक से डेढ़ की राशि दी जाएगी, जो गांव में कृषि सुविधाएं विकसित करने पर व्यय होगी। योजना में गांवों में वन सीमा पर सोलर पावर फैंसिंग, सिंचाई की सुविधा, फार्मर्स मशीनरी बैंक, कलेक्शन कक्ष, शॉर्टिंग-ग्रेडिंगप्लांट, पशुपालन, मुर्गी, मछली व मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां होंगी। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था भी अलग से होगी। योजना से होने वाले प्रत्येक कार्य की निगरानी को विशेष प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा।

सहजन के पेड़ के सहारे जंग लड़ रही उप्र की बड़ी आबादी

सार्थक पहल ▶ महराजगंज जिले के 33 गांवों के घर-घर में लगे सहजन के पेड़, दे रहे स्वस्थ समाज का संदेश

विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज

स्वस्थ समाज

सरकारी महकमा जब राहत नहीं दे सका, कागजी खानापूरी से अलग कुछ नहीं कर सका तो महराजगंज, उप्र के तीन ब्लॉकों फरेंदा, बृजमनगंज और धानी की महिलाओं ने आगे बढ़कर कुपोषण और रक्ताल्पता (एनीमिया) से लड़ने की कमान खुद संभाल ली। औषधीय गुण वाले सहजन के पेड़ को इस लड़ाई में हथियार बनाया। उसका नतीजा भी मिला है।

इन ब्लॉकों के 33 गांव आज पूरे जिले को स्वस्थ समाज का संदेश दे रहे हैं। नर्सरी तैयार करने और सहजन को भोजन में शामिल करने की जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाल रखी है। पुरुषों के जिम्मे पौधों की रोपाई और देखभाल का कार्य है। करमहा गांव की कमलावती ने कहा कि तीन वर्ष पूर्व अचानक तबीयत खराब हुई। शरीर कमजोर होने पर डॉक्टर से जांच कराई तो उन्होंने खून की कमी बताकर पोषक तत्वों को खाने की सलाह दी। सहजन का नियमित सेवन शुरू किया तो स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बरगदवा गांव की सुमित्रा देवी की भी यही राय है। बताती हैं कि जब से सहजन का प्रयोग शुरू किया तो बड़ी राहत मिली। रंगपुर की शकुंतला व नंदिनी ने कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्य सहजन का नियमित प्रयोग करते हैं। बच्चों में वजन कम होने पर डॉक्टरों ने खाने में सहजन का प्रयोग करने की सलाह दी थी। अमल किया तो फायदा हुआ।

क्षेत्र के बैसार, हरिहरपुर, खुर्रमपुर, गुलरिया, बख्तावरपुर और मोहनापुर में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर सहजन की नर्सरी तैयार की। आज इन नर्सरियों से ग्रामीण महज पांच रुपये में सहजन का पौधा लेकर अपने घर-आंगन में लगा रहे हैं। इससे जहां महिलाओं को आय हो रही है, वहीं उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। सहजन की नर्सरी का संचालन करने वाली उर्मिला देवी, अलीमुननिशा, मीना, कमलावती व बचगंगपुर के डेबा ने कहा कि यह पौधा स्वस्थ समाज का वाहक बना है।

फल, फूल, पत्तियों का सेवन... : ग्रामीण घर के आसपास सहजन के पौधे लगाकर उसके फल, फूल, पत्तियों का सेवन कर रहे हैं। गुदरीपुर निवासी दिनेश मौर्य ने बताया कि कुपोषण सहित अन्य बीमारियों से मुक्ति के लिए ग्रामीण सब्जी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सहजन की पत्तियों का चूर्ण बनाकर उपयोग में लाया जाता है। रोटी बनाते समय आटा में डालकर, सब्जी में मसाले के रूप में व कढ़ी में डालकर भी इसका प्रयोग होता है। प्रयास रहता है कि वर्ष भर उसके फल, फूल व पत्तियों का नियमित रूप से सेवन करें। इसमें आयरन के अलावा अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/ positive-news

महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) में सहजन के पौधों का रोपण करते ग्रामीण। जागरण

▶ **कुपोषण, रक्ताल्पता से जंग में सहजन बना हथियार, नर्सरी तैयार करने और भोजन में शामिल करने की जिम्मेदारी महिलाओं पर**

डेढ़ साल पहले महराजगंज में 52 हजार हजार बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार थे। इनमें 14 हजार 346 बच्चे अतिकुपोषित थे। पीड़ितों में खून की कमी की समस्या सर्वाधिक थी। जिससे इनका वजन काफी कम था। अब यह आंकड़ा घटकर 32 हजार 217 आ गया है, जबकि अतिकुपोषित बच्चे महज चार हजार रह गए हैं। पूरे जिले में इन 33 गांवों की स्थिति सबसे बेहतर है। इसमें यहां की महिलाओं की भूमिका अहम है।

-बृजेंद्र जायसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी

सहजन गुणों की खान है। सहजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। 100 ग्राम सहजन की पत्तियों में दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम मिलता है। सहजन की पत्तियों में कैल्शियम व विटामिन सी के साथ ही प्रोटीन, पोटैशियम, आयरन और विटामिन बी की मात्रा अधिक होती है। कुपोषण व रक्ताल्पता के साथ ही सहजन उच्च रक्तचाप, मोटापा घटाने, त्वचा को दुरुस्त रखने और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। एक पेड़ से वर्ष भर में 20-30 किलो फल प्राप्त होता है।

-डॉ. आरबी राम

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, महराजगंज, उप्र

मुरादाबाद व हरिद्वार स्टेशन पर कैश से नहीं होगा लेन-देन

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

रेलवे डिजिटल लेन-देन पूरी तरह से लागू करने जा रहा है। ट्रेन से स्टेशन परिसर तक किसी प्रकार का लेनदेन नकद के बजाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व ई-वालेट से करने की व्यवस्था होगी। इसके लिए रेलवे कुली, वेंडर व वाहन पार्किंग संचालक के पास विशेष व्यवस्था होगी। मुरादाबाद रेल मंडल के चार स्टेशनों (मुरादाबाद, देहरादून, बरेली व हरिद्वार) पर यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध होगी।

नोटबंदी के बाद से कैशलेस के लिए निरंतर प्रयासरत रेलवे प्रशासन फिर से कैशलेस-लगेजलेस योजना लागू करने जा रहा है। आरक्षण टिकट बुकिंग काउंटर व जनरल टिकट बुकिंग काउंटर पर डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लग रही है। कुली व वेंडर को पेटीएम जैसे ई-वालेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कोई भी यात्री खानपान की वस्तु खरीदने के बाद कैशलेस भुगतान कर सकेगा। कुली भी भाड़ा पेटीएम के माध्यम से लेगा। कुली को पेटीएम सुविधा रेलवे उपलब्ध कराएगा, जबकि वेंडर को यह सुविधा स्वयं लेनी होगी।

प्लेटफार्म पर सभी प्रकार के स्टाल में पेटीएम के साथ डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। ट्रेन के पेंट्रीकार के वेंडर के पास पेटीएम व डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा होगी। पेंट्रीकार में खाने का भुगतान ई-बैंकिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं। इसी तरह से वाहन पार्किंग स्टैंड पर भी पेटीएम व डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा होगी। रेलवे यह सुविधा रेल मंडल के मुरादाबाद, बरेली, देहरादून व हरिद्वार स्टेशनों पर शीघ्र उपलब्ध कराएगा।

कम से कम सामान पर जोर : यात्रा के दौरान कम के कम सामान लेकर चलने (लगेजलेस) के लिए यात्रियों को जागरूक करने की योजना है। एक यात्री 35 किलो से तक सामान लेकर चल सकता है। ट्राली बैग या कंधे पर टांगने वाले बैग लेकर चलें। अधिक सामान होने पर बुक कराकर चलने की सलाह दी जाएगी।

▶ **मुरादाबाद रेल मंडल के चार स्टेशनों पर कैशलेस, लगेजलेस योजना लागू करने की तैयारी**

मुरादाबाद में अहम पहल हुई है। फाइल

रेलवे कैशलेस सिस्टम शीघ्र लागू करेगा। नई व्यवस्था में यात्री को कुली, वेंडर व पार्किंग में नकद भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेटीएम, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान किया जा सकेगा।

-रेखा, वाणिज्य प्रबंधक, प्रवर मंडल

नारी शक्ति को सलाम

पहाड़ी सड़कों पर सरपट दौड़ती है कुलदीप कौर की लॉरी

कुलदीप कौर कोलकाता से लेकर नेपाल तक का पति के साथ कई बार सफर कर चुकी हैं। ट्राला लेकर रोज कहीं न कहीं सड़कों पर उतरती हैं। उनका हौसला सभी के लिए प्रेरणा है...

मनदीप कुमार, संगरूर

घर गृहस्थी में पति के साथ अगर पत्नी भी कदम से कदम मिलाकर चले तो कामयाबी कदम चूमती है। संगरूर की कुलदीप कौर ने सच कर दिखाया है। पंजाब के संगरूर शहर की कुलदीप कौर जहां अपना घर चलाने के लिए 18 टायरों वाला ट्रक (ट्राला) चलाती हैं, वहीं घरेलू व पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बाखूबी निभा रही हैं। कुलदीप कौर अपने पति के साथ ट्राला चलाती हैं। वह कोलकाता से लेकर नेपाल तक का पति के साथ कई बार सफर कर चुकी है। ट्राला लेकर रोज कहीं न कहीं सड़कों पर उतरती हैं। कुलदीप अपने पति लक्खा सिंह के साथ ही जाती हैं।

बकौल कुलदीप कौर, मैं अपने पति के साथ उनकी मदद करने के लिए जाती थी। एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं भी ट्राला चलाऊं। पति ने मेरी इच्छा देख मुझे ट्राला चलाना सिखाने के लिए हां कर दी। मन में जोश और जज्बा था। इसलिए मैंने जल्द ट्राला चलाना सीख लिया। इसके बाद वह मुंबई, नेपाल व गुजरात ट्राला चला कर जाने लगीं।

परिवार वालों ने तो घर से निकाल दिया था : कुलदीप कौर ने बताया कि उनके घरवालों को उनका ट्राला चलाना रास नहीं आया। उन्हें इस पर आपत्ति थी। हर कोई यही कहता था कि एक महिला के लिए यह काम करना ठीक नहीं है। परिवार वालों ने तो हमें यह कह कर घर से निकाल दिया था कि वह गलत काम करती है। कुलदीप ने कहा कि उनके पति ने उनका हमेशा साथ दिया। यही वजह है कि आज वह अपने हुनर के बल पर अपना खुद का ट्राला सकी हैं। कुलदीप कहती हैं कि मैंने हर मुश्किल का सामना किया। पति के सहयोग और अपने बलबूते मैं एक कामयाब ट्रक ड्राइवर बनी। वह घर का भी सारा काम करती हैं। उनका एक बेटा है, जिसे वह पढ़ा रही हैं।

पहाड़ी इलाके में ट्राला चलाने का है हुनर : सड़कों पर गाड़ी व ट्राला चलाना बेशक आसान दिखाई देता है, लेकिन पहाड़ी इलाके में ट्रक-ट्राला चलाना आसान नहीं है। अच्छे-अच्छे ड्राइवरों के पहाड़ी इलाके में पसीने छूट जाते हैं लेकिन कुलदीप हिमाचल की पहाड़ियों में भी कुशलता से ट्राला दौड़ाती हैं। कुलदीप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पानी का ट्राला लेकर जाने पर हिमाचल के राज्यपाल ने 2018 में उन्हें प्रशंसा पत्र दिला था। वह कहती हैं कि मुझे दुख भी है कि आज तक पंजाब सरकार ने उनकी प्रशंसा नहीं की। कुलदीप ने कहा, औरतों को पीछे हटना नहीं चाहिए। जमाना कुछ भी कहे, बस आगे बढ़ता रहना चाहिए।

कुलदीप ने ट्राला चलाना सिखाने को कहा तो हैरान रह गया था: लक्खा : पति लक्खा सिंह ने बताया कि जब पहली बार कुलदीप ने ट्राला चलाना सिखाने को कहा तो मैं हैरान रह गया था। मुझे अजीब लगा था मगर उसे ट्राला चलाने से कभी नहीं रोका। कुलदीप को ट्राला चलाना सिखाया। आज हम दोनों नेपाल, मुंबई, गुजरात तक ट्राला इकट्ठे ही चलाते हैं। मुझे खुशी भी है कि कुलदीप को हिमाचल सरकार ने प्रशंसा पत्र दिया है।

▶ **पति ने इच्छा देखी तो ट्राला चलाना सिखाने के लिए हां कर दी। जज्बे के बल पर ड्राइवर बन गई : कुलदीप**

ट्राला चलाने वाली संगरूर की कुलदीप कौर

18 टायरों वाला ट्राला चलाकर संगरूर की कुलदीप कौर ने मिसाल पेश की है। वह पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं।

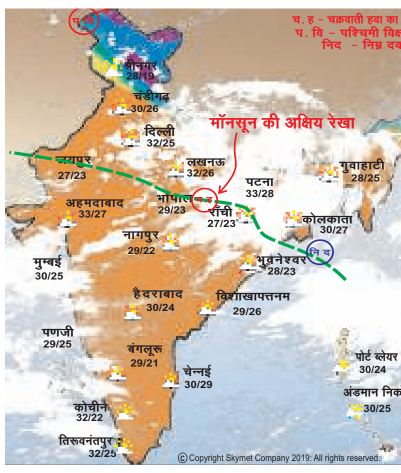

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर में मौसम गर्म रहेगा। हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के अनेक भागों में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होगी। इन राज्यों में घने बादल छाये रहेंगे।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/25/आंबा	अहमदाबाद	33/26/आंबा
कोलकाता	32/27/आंबा	बड़ौदा	30/25/व
चेन्नई	37/26/आंबा	नागपुर	30/23/आंबा
हैदराबाद	32/24/व	इन्दौर	28/24/व
बंगलूरू	29/21/व	राँची	31/25/व
त्रिवेन्द्रम	33/26/आंबा	पटना	35/28/व
गुवाहाटी	29/23/व	जमशेदपुर	33/27/व
गंगटोक	15/10/आंबा	पुणे	23/22/व

देश के प्रसिद्ध अर्ध सैनिक बल सीआरपीएफ की स्थापना हुई

1939 में आज ही क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस के नाम से अंग्रेजों ने इस सुरक्षा बल की स्थापना की। आजादी के बाद 28 दिसंबर, 1949 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया।

जेट इंजन से लैस हवाई जहाज ने पहली बार उड़ान भरी

1949 में आज ही जेट इंजन से लैस डी हैविलैंड डीएच 106 कॉमेट नामक हवाई जहाज ने ब्रिटेन से पहली बार उड़ान भरी थी। यह विमान जेट इंजन की वजह से 805 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता था।

स्वतंत्रता आंदोलन की महान क्रांतिकारी थीं कल्पना दत्त

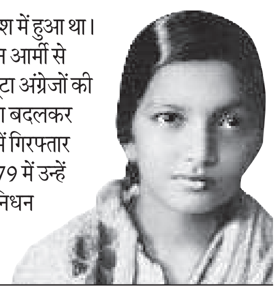

कल्पना दत्त का जन्म 1913 में आज ही बांग्लादेश में हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ीं। 1930 में इस दल ने चटगांव शस्त्रागार लूटा अंग्रेजों की नजर में आने पर पढ़ाई छोड़कर चटगांव आना पड़ा। वह वेश बदलकर क्रांतिकारियों को गोला-बारूद पहुंचाया करती थीं। 1933 में गिरफ्तार हो गईं। 1934 में आजीवन कारावास की सजा हो गई। 1979 में उन्हें वीर महिला की उपाधि दी गई। 8 फरवरी 1995 को उनका निधन हो गया। 2010 में आशुतोष गोवारिकर ने उनके जीवन पर आधारित फिल्म 'खेलें हम जी जान से' बनाई थी।

इधर-उधर की

करोड़ों की मालकिन है छह साल की बच्ची

सियोल, एजेंसी : आपने सुना होगा कि पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मगर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में छह साल की बोरम ने इस कथन को झूठा साबित कर दिया। यूट्यूब ने उन्हें इतना मालामाल कर दिया कि उन्होंने 55 करोड़ रुपये (80 लाख डॉलर) कीमत की पांच मंजिला इमारत खरीद डाली है। बोरम के यूट्यूब में तीन करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब में उनके दो बड़े ही लोकप्रिय चैनल हैं। एक में वह खिलौनों की समीक्षा करती हैं और दूसरा वीडियो ब्लॉग है। दोनों के कुल मिलाकर 3.12 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। उनका सबसे लोकप्रिय वीडियो 37.6 करोड़ बार देखा गया। इस वीडियो में वह प्लास्टिक के खिलौने की रसोई का उपयोग करके नूडल्स बनाती हैं। फोर्ब्स के मुताबिक रेयान यूट्यूब के जरिए कमाई करने के मामले में सबसे आगे हैं। रेयान ने साल 2018 में यूट्यूब के जरिए 2.2 करोड़ डॉलर की कमाई की थी।

एरीज ने खोजे चमक बदलने वाले 28 तारे

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▸ रंग लाई भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत, 57 हजार प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं तारे

▸ अंतरिक्ष के गर्भ में छिपे तारों के रहस्यों से अब उठेगा पर्दा

सौर मंडल में चांद और मंगल तो हमारी पहुंच में हैं ही, साथ ही सुदूर अंतरिक्ष के गर्भ में समाए तारे भी अब हमारी नजरों से ओझल नहीं रह गए हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के वैज्ञानिकों ने दूर अंतरिक्ष में चमक बदलने वाले 28 तारों की पहचान कर उन्हें खोज निकाला है। तीन साल पहले एरीज द्वारा देवस्थल (नैनीताल) में स्थापित 3.6 मीटर व्यास की ऑप्टिकल दूरबीन के जरिये यह संभव हो पाया है।

एरीज की वैज्ञानिक डॉ. स्नेह लता ने बताया कि ब्रह्मांड में फैले अरबों-खरबों तारों का अपना अलग संसार है, जिनके अनेक आकार-प्रकार हैं। इनकी थाह पाना आसान नहीं है। इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक निरंतर इनकी खोजबीन में लगे रहते हैं। एरीज में 3.6 मीटर की दूरबीन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से दूर के तारों को देख उनकी पहचान कर पाना संभव हो पाया है। जिसके परिणाम स्वरूप 57 हजार प्रकाश वर्ष दूर ग्लोब्यूलर कलस्टर का अध्ययन किया। दूरबीन में लगे सीसीडी (चार्जड कप्लड डिवाइस) इमेजर से इस कलस्टर के चित्र लिए गए हैं, जिनके गहन अध्ययन के बाद पता चला कि इस कलस्टर में 28 तारे मौजूद हैं। अपनी चमक बदलते रहना इन तारों का स्वाभाव है, जिसके कारण वैज्ञानिकों का इनके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। एनजीसी (न्यू गैलेटिक कैटालॉग) 4147 नामक इस कलस्टर में पहली बार इन तारों की पहचान की गई है। जिस कारण यह खोज महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इस सफलता में एरीज के दो दर्जन वैज्ञानिक व इंजीनियरों का अहम सहयोग रहा है। लिहाजा इसका श्रेय एरीज को जाता है।

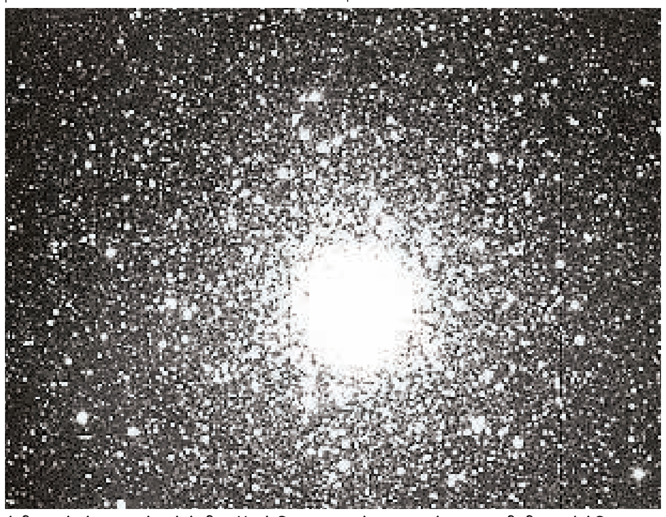

नैनीताल के देवस्थल में लगे टेलीस्कॉप से लिया गया ग्लोब्यूलर कलस्टर एनजीसी (न्यू गैलेटिक कैटालाग)-4147 का चित्र। साभार : एरीज

नए रहस्यों से पर्दा उठाएगी टेलीस्कोप : आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के निदेशक डॉ. वहाबउद्दीन ने कहा कि पहले शोध के लिए हमारे वैज्ञानिकों को दूसरे देशों की शरण लेनी पड़ती थी। मगर अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि अपने ही देश में खोज के नए आयाम पैदा कर सकते हैं। 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन से हम अपनी आकाशगंगा से परे दूसरी आकाशगंगाओं में झांक कर वहां के नक्षत्रों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। हाल ही में ग्लोब्यूलर कलस्टर एनजीसी (न्यू गैलेटिक कैटालॉग) 4147 में वैरिएबल स्टार्स की खोज इसका ताजा परिणाम है। इस दूरबीन से अभी तक आए परिणाम उत्साहजनक हैं। एशिया की सबसे बड़ी यह दूरबीन अंतरिक्ष विज्ञान व सुविधाओं के क्षेत्र में देश की बड़ी उपलब्धि है।

फिल्म रिव्यू

★★★

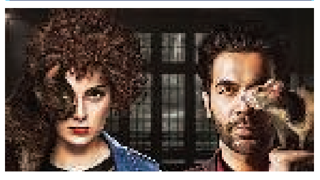

जज करना मुश्किल नहीं

जजमेंटल है क्या

निर्देशक : प्रकाश कोवलामुदी
मुख्य कलाकार : कंगना रनोट, राजकुमार राव, अमायरा दस्तूर, हुसैन दलाल
अवधि : दो घंटे 1 मिनट

फिल्म की कहानी मानसिक बीमारी एक्यूट साइकोसिस से पीड़ित बॉबी (कंगना रनोट) की है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की सोच यथार्थ से हट जाती है। किसी के आसपास न होने पर भी उसे आवाजें सुनाई देती हैं या फिर कुछ दिखाई देने की स्थिति में उसके महसूस होने की भ्रांति होती है। इस बीमारी में व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। बचपन में बॉबी के माता-पिता की आपस में झगड़ते हुए छत से गिरकर मौत हो जाती है। कहानी बीस साल आगे बढ़ती है। बॉबी को अखबारों की कटिंग से चिड़िया आदि बनाने का शौक है। यह कटिंग क्राइम खबरों की होती है। बॉबी डबिंग आर्टिस्ट है। उसे अपनी डब फिल्मों के पोस्टर का फोटोशॉप करके अपनी तस्वीर लगाने का भी शौक है। डबिंग करते हुए किरदारों में रच-बच जाती है। उसकी सोशल लाइफ वरुण (हुसैन दलाल) के इर्दगिर्द है। उसकी जिंदगी में मोड़ तब आता है, जब केशव (राजकुमार राव) और रीमा (अमायरा दस्तूर) बतौर किरायेदार उसके घर में रहने आते हैं। एक हादसे में रीमा की मौत हो जाती है। बॉबी केशव पर आरोप लगाती है। बॉबी की सभी पर शक करने की प्रवृत्ति और वास्तविकताओं के बीच अंतर करने में असमर्थता भ्रम की स्थिति पैदा करती है। केशव पर लगाए उसके आरोप सही हैं या कोरी कल्पना, इसी सवाल के ताने-बाने में गढ़ी गई है 'जजमेंटल है क्या' की कहानी।

शुरुआत में बॉबी के किरदार को स्थापित करने में लेखक-निर्देशक ने काफी समय लिया है। सबसे अविश्वसनीय बॉबी का हत्या के तारों को जोड़ने के लिए गूगल पर सर्च करना रहा। फिल्म में विक्षिप्त दिमाग में कई आवाजें व सुनाई देने और आसपास चेहरों को दिखाने के उपक्रम में कुछ नयापन नहीं है। 'मनमर्जियां', 'केदारनाथ' की कहानी लिख चुकीं कनिका ढिल्लन मर्डर मिस्ट्री को रोमांचक बनाने की बजाय बॉबी की मानसिक स्थिति में उलझकर रह गई हैं। 'साइज जीरो' जैसी दक्षिण की फिल्म का निर्देशन कर चुके प्रकाश कोवलामुदी ने साहसिक प्रयोग किया, लेकिन उसे सही दिशा नहीं दे पाए। मगर हां, फिल्म में रामायण का संदर्भ देते हुए लक्ष्मण रेखा, सीता हरण और अग्नि परीक्षा का हवाला देते हुए स्त्रियों की दशा बताने का प्रयास रोचक है। फिल्म के आर्ट डायरेक्शन की तारीफ करनी होगी। सेट रंगबिरंगा, मनमोहक और खूबसूरत है।

बॉबी की मनोदशा और व्यथा को कंगना रनोट ने बखूबी जीवंत किया है। वह कहीं भी लाउड नहीं होती हैं। राजकुमार राव के किरदार को समुचित तरीके से गढ़ा नहीं गया है। वरुण के किरदार में हुसैन दलाल अपनी पंचिंग लाइन और अदाकारी से दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहते हैं। अमायरा दस्तूर, अमृता पुरी के हिस्से में कुछ खास करने के लिए नहीं आया है।

-स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

शोध अनुसंधान

मोटापे का खतरा बढ़ा सकता है फोन का ज्यादा इस्तेमाल

यदि आप रोजाना पांच घंटे या इससे ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक शोध का दावा है कि ज्यादातर समय फोन पर व्यस्त रहने वाले छात्रों की जीवनशैली में कई बदलाव आ जाते हैं। इसके चलते उनमें मोटापे और आगे चलकर हृदय रोग का खतरा हो सकता है। कोलंबिया स्थित सिमोन बोलीवर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता मिराी मंटीला मोरन ने कहा, 'स्मार्टफोन का इस्तेमाल कई काम के लिए किया जा सकता है और इसे हर वक्त अपने साथ रखना भी आसान है। लेकिन लोगों को इन खूबियों के प्रति आकर्षित होने की जगह यह समझना चाहिए की यह हमारे स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर रहा है।' इस शोध के लिए 19 से 20 साल के 1060 छात्रों को चुना गया था। अध्ययन के अनुसार, पांच घंटे फोन इस्तेमाल करने वाले 43 फीसद छात्र मोटापे के खतरे का सामना कर रहे थे। (आइएएनएस)

चिकनगुनिया पर असरकारक है नया टूल

डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस के संक्रमण के कारण हर साल हजारों लोग जान गंवा देते हैं। वैज्ञानिकों ने इन वायरस का संक्रमण फैलाने वाले मादा एडीज एजिप्टी मच्छर को नियंत्रित करने का तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने एक ऐसा टूल बनाया है जो अंडे देने के लिए जगह तलाश रही मादा मच्छर को अपना निशाना बनाएगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऑटोसाइडल ग्रेविड ओवीट्रैप टूल (एजीओ) की मदद से चिकनगुनिया को हराया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस रसायन मुक्त टूल से चिकनगुनिया के संक्रमण से सुरक्षा मिलेगी। प्यूर्टोरिको में इस टूल का परीक्षण किया गया था, जो सफल रहा। अध्ययन के लिए 639 घरों को चुना गया था जिसमें 290 घरों में एजीओ ट्रैप उपलब्ध कराए गए। फिर, जिन घरों में एजीओ ट्रैप दिए गए थे उनमें से 175 व्यक्तियों और अन्य घरों के 152 लोगों के रक्त के नमूने की जांच की गई। एजीओ ट्रैप वाले घर के केवल उन 10 फीसद लोगों में ही चिकनगुनिया के लक्षण मिले जो ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। (आइएएनएस)

चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान-2

करीब आती मंजिल ▸ गुरुवार की रात उपग्रह को पृथ्वी की अगली कक्षा में प्रवेश कराया गया

29 जुलाई को तीसरी बार चंद्रयान-2 की कक्षा को बदला जाएगा

बेंगलुरु, प्रेट्र : चंद्रयान-2 उपग्रह गुरुवार की रात सफलतापूर्वक चंद्रमा की तरफ और एक कदम बढ़ गया। अंतरिक्षयान पर लगे प्रणोदन प्रणाली के जरिए गुरुवार-शुक्रवार की रात एक बजकर आठ मिनट पर दूसरी बार उपग्रह की कक्षा को बदलते हुए उसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की अगली कक्षा में प्रवेश कराया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि कक्षा बदलने की यह प्रक्रिया लगभग 15 मिनट तक चली।

इसरो के मुताबिक अंतरिक्षयान के सभी पैरामीटर सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रयान-2 अब पृथ्वी की कक्षा में 251 गुणा 54,823 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस कक्षा में उपग्रह 29 जुलाई तक परिक्रमा करेगा। 29 जुलाई को ही दिन में ढाई से साढ़े तीन बजे के बीच चंद्रयान-2 की कक्षा को तीसरी बार बदला जाएगा और उसे प्रणोदन प्रणाली से पृथ्वी की अगली कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा।

22 जुलाई को प्रक्षेपण के करीब 16 मिनट 23 सेकंड बाद चंद्रयान-2 पृथ्वी की कक्षा में 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीएसएलवी-मैक 3 रॉकेट से अलग हो गया था और चक्कर लगा रहा था। बुधवार 24 जुलाई को पहली बार उपग्रह को पृथ्वी की अगली कक्षा में भेजा गया था। शुक्रवार को दूसरी बार उसके कक्षा में बदलाव किया गया। छह अगस्त तक अभी और दो बार चंद्रयान-2 की कक्षा (ऑर्बिट) को बदला जाएगा।

चंद्रयान-2 पृथ्वी की कक्षा से 14 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा की तरफ रवाना होगा। 20 अगस्त को उपग्रह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। उसके बाद 31 अगस्त तक वह चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। एक सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ जाएगा। सात सितंबर को विक्रम लैंडर दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। विक्रम लैंडर के उतरने के कुछ घंटे बाद रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और चांद की सतह पर तमाम खोज कार्य शुरू करेगा। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। अभी तक चंद्रमा के इस क्षेत्र में कोई देश नहीं पहुंच पाया है।

चंद्रयान-2 पर दुनिया भर की नजर : चांद पर अभी तक तीन देशों रूस, अमेरिका और चीन के मिशन ही उतर पाए हैं। चांद पर अपना मिशन लैंड कराने वाला भारत चौथा देश होगा। इसलिए नासा समेत दुनिया भर की नजर चंद्रयान-2 की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग पर लगी है। चंद्रयान-2 से मिलने वाली जानकारियां अहम हैं। अमेरिका 2024 तक दक्षिण ध्रुव पर अपना मानव मिशन भेजने वाला है, इसलिए उसे चंद्रयान-2 से मिलने वाली जानकारियों का बेसब्री से इंतजार है, ताकि उसके हिसाब से वो अपने मिशन में बदलाव कर सके।

क्या-क्या पता लगाएगा : भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान-1 से चांद पर पानी होने का पता चला था। अब चंद्रयान-2 यह पता लगाएगा कि कहां-कहां और किस रूप में पानी है। माना जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी मौजूद है। इसके अलावा वहां के मौसम और रेडिएशन का पता लगाने के साथ ही चंद्रयान-2 यह भी पता लगाएगा कि वहां किस हिस्से में और कब-कब रोशनी होती है और कब-कब अंधेरा छाया रहता है।

20वीं सदी में तेजी से गर्म हो रही है पृथ्वी

जेनेवा, प्रेट्र : बीते दो हजार वर्षों के मुकाबले 20वीं सदी में वैश्विक तापमान में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका असर दुनियाभर में देखा जा सकता है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि गर्मी बढ़ने के कारण 1300 से 1850 ईसवी के दौरान जलवायु संबंधी कई अभूतपूर्व और अप्रत्याशित घटनाएं हुई थीं। लेकिन स्विटजरलैंड की बेरन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने वैश्विक जलवायु-परिवर्तन की एक अलग तस्वीर पेश की है। नेचर एंड नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुए अध्ययन से से पता चलता है कि पिछले 2,000 वर्षों में दुनिया भर में एक जैसी सर्दी और गर्मी की अवधि का कोई प्रमाण नहीं है। बेरन यूनिवर्सिटी के राफेल न्यूकोम ने कहा कि यह सच है कि लिटिल आइस एज के दौरान पूरी दुनिया में ठंड थी, लेकिन हर जगह मौसम एक जैसा नहीं था। वैज्ञानिक के अनुसार, ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण अब विश्व की जलवायु भी बदल-सी गई है। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो कहीं बहुत ज्यादा सर्दी लोगों के लिए समस्या बन रही है।

बर्थडे का सेलीब्रेशन

चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगडू में स्थित नेशनल नेचुरल रिजर्व में पांडा के 16 शिशुओं के पहले जन्मदिन को समारोहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर एक साथ बर्थडे पार्टी दी गई। इन सभी का जन्म पिछले साल हुआ था। इस नेशनल रिजर्व में पांडा के संरक्षण का बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य किया जा रहा है। रायटर

10 लाख लेगो की मदद से बनाई कार

करीब दस लाख लेगो पीस की मदद से विशेषज्ञों की एक टीम ने यह फुल साइज बुगाती चिरॉन कार बनाई है। कार को रूस की राजधानी मॉस्को के गोर्की पार्क में प्रदर्शित किया गया है। इस कार का वजन करीब 1500 किलो है और यह 20 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल सकती है। इस अद्भुत कार को तैयार करने में 13,438 घंटे लगे। खास बात यह है कि लेगो को आपस में चिपकाने के लिए किसी भी किस्म के गोंद का इस्तेमाल नहीं हुआ। एजेंसी

स्क्रीन शॉट

खेल-खेल में सीखें बच्चे : सनी लियोनी

अभिनेत्री सनी लियोनी ने वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के लातूर जिले से निशा नामक बच्ची को गोद लिया था। पिछले साल वह सेरोगेसी के जरिये जुड़वा बच्चों की मां बनीं। फिलहाल, तीन बच्चों के मातृत्व के सुख ले रहीं सनी बच्चों के विकास को लेकर कहती हैं, 'मां बनने के बाद मेरी जीवनशैली में सुखद बदलाव आए हैं। मैं मानती हूं कि अगर बच्चों को उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो वे जल्द सीख सकेंगे। उचित संसाधनों के अभाव में बच्चे बाहर खेलने तो जाते हैं, पर उससे कुछ सीख नहीं पाते। मैं चाहती हूं कि कुछ ऐसी संस्थाओं का विकास हो, जहां बच्चे खेल-खेल में कुछ सीख भी सकें।'

नीना गुप्ता ने ताजा कीं पुरानी यादें

कुछ सितारे अपने बच्चों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। कुछ सितारों के बच्चों की फोटो तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे फैन पेज की भरमार है, जो स्टार्स के बच्चों को लेकर बनाए गए हैं। नीना गुप्ता की जिंदगी में सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल रहा है। उन्होंने अपने पास काम न होने की बात सोशल मीडिया पर ही साझा की थी, जिसके बाद उन्हें काफी काम मिलने लगा है। 'बधाई हो' फिल्म से उन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की। इस बार नीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी तस्वीर साझा की है, जिसमें वह अपनी बेटी मसाबा के साथ नजर आ रही हैं। बेबी मसाबा अपनी मम्मी नीना के बालों में लगे फूलों के गजरे से खेल रही हैं। इस फोटो के साथ नीना ने लिखा है, 'तब न तो इंस्टाग्राम होता था, न ट्विटर तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने बच्चे के साथ फोटो डाल दूं, क्योंकि भावनाएं तो एक ही हैं, तब की और अब की।'

मिलिए बच्चन पांडे से!

यह अक्षय कुमार की आगामी फिल्म का नाम है। 'हाउसफुल', 'हे बेबी' जैसी फिल्में साथ कर चुके साजिद नाडियाडवाला और अक्षय कुमार फिर साथ आए हैं। पोस्टर में अक्षय का दक्षिण भारतीय राउडी लुक आकर्षक है। वह गले में चार सोने की मोटी चेन, हाथ में कराटे की बेल्ट लिए लुंगी पहने खड़े हैं। फिल्म अगले वर्ष क्रिसमस पर रिलीज होगी।

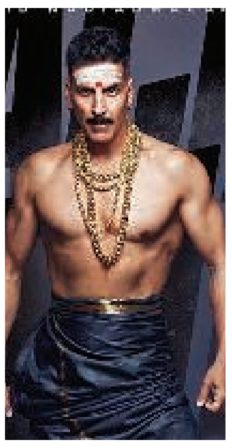

अभय देओल ने खुद उड़ाया अपना मजाक

बेहतरीन अभिनेता अभय देओल बड़े पर्दे पर कम ही फिल्में करते हैं, जिसको लेकर कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। पर, अब तो अभय देओल ने खुद ही अपना मजाक बनाकर हैरान कर दिया है। दरअसल, अभय ने इंस्टाग्राम पर एक मीम शेयर किया है। इसे पहले किसी और ने शेयर किया था। इस मीम में अभय के फिल्मों से गायब हो जाने की बात को क्रिएटिव तरीके से कहा गया है। अभय ने कैप्शन में जवाब भी दिया है कि वह कितने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। इस मीम में एक तरफ अभय की तस्वीर है, जिस पर उनका नाम लिखा है। दूसरे सेक्शन में कोई तस्वीर नहीं है और उस पर लिखा है, अब गायब है। अभय ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'यह मुझे ऑनलाइन मिला। यह एक बड़ा सवाल है, जिसका शॉर्ट में जवाब नहीं दिया जा सकता। शायद एक दिन मैं इस बारे में किताब लिखूं।'

वाणी कपूर ने किरदार के लिए की खूब मेहनत

अभिनेत्री वाणी कपूर काफी समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। पिछले दिनों ही खबर आई कि वाणी रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर' में बतौर मुख्य अभिनेत्री नजर आएंगी। ऐसे में फिल्म में अपने किरदार के साथ न्याय करने के लिए वाणी ने खुद पर खूब मेहनत की है। इस बारे में वह बताती हैं, 'दर्शकों से हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना रोमांचक अनुभव रहा है और ऐसी प्रतिक्रियाएं देखकर मैं वाकई काफी खुश हूं। मैंने इस फिल्म में फिटनेस के लिहाज से खुद पर काफी अधिक मेहनत की है।' 30 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि इस फिल्म में अपने किरदार के लिए मैंने योग के नियमित सत्र में हिस्सा लिया तथा जिम में वेट ट्रेनिंग ली। वाणी ने बताया, 'मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आरंभ से ही उत्साहित थी और मुझे फिल्म में कैसा दिखना है, इसे लेकर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद पहले से ही तैयारी कर चुके थे। हालांकि मेरे लिए डाइटिंग करना और फैटी व्यंजनों का सेवन बंद करना सबसे कठिन रहा।' निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने वाणी के चयन पर कहा, 'हम फिल्म में ऐसी अभिनेत्री को लेना चाहते थे, जो सुपर फिट हो, क्योंकि उसे देश के सबसे स्मार्ट दिखने वाले अभिनेता रितिक रोशन के अपोजिट काम करना था। ऐसे में वाणी हमें सबसे अधिक फिट लगीं।' वह बेहतरीन अभिनेत्री हैं और अपने किरदार के लिए उन्होंने खूब मेहनत की है। बता दें कि यशराज फिल्म्स की इस फिल्म में एक्शन दृश्य काफी अधिक होंगे। फिल्म तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।

खुलेंगे राज

अमेरिका और ताइवान के साथ मिलकर शोध कर रहे बीएचयू के वैज्ञानिक, संचार क्षेत्र में आएगी क्रांति, नाभिकीय ऊर्जा का पता लगाना होगा आसान...

सूरज के रहस्य पर 'न्यूट्रिनो' डालेगा प्रकाश

मुहम्मद रईस, वाराणसी

चंद्रयान-2 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक सूर्य मिशन (आदित्य एल-वन) में जुट गए हैं। बीएचयू के वैज्ञानिक भी एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में हैं। न्यूट्रिनो (घोस्ट पार्टिकल) के जरिए सूर्य की संरचना व उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि न्यूट्रिनो के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। इसकी विशेषताओं पर भी शोध चल रहे हैं। इस मिशन में साथ दे रहे हैं अमेरिका व ताइवान के वैज्ञानिक। न्यूट्रिनो का पता लगाने में प्रयुक्त रेजिस्टिव प्लेट चैंबर (आरपीसी) डिटेक्टर में प्रयोग होने वाले चार्ज पिकअप पैनल के स्वरूप में बीएचयू के वैज्ञानिकों ने कई बदलाव किया है। यह शोध यूरोप के जर्नल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन (जेआइएनएसटी) में 2017 में प्रकाशित हुआ।

तमिलनाडु में प्रयोगशाला प्रस्तावित : न्यूट्रिनो के माध्यम से सूर्य की जानकारी जुटाने का विचार वैज्ञानिकों ने 2000 में सरकार के सामने रखा था। सरकार ने तमिलनाडु के थेनी जिले में प्रस्तावित प्रयोगशाला के लिए छह वर्ष पहले करीब 1500 करोड़ रुपये स्वीकृत भी किए।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भौतिक विज्ञान विभाग के लैब में न्यूट्रिनो का विश्लेषण करते शोध छात्र। जागरण

न्यूट्रिनो पहचान बदलने वाला अतिसूक्ष्म कण है। यह लगभग प्रकाश की गति के बराबर गतिमान रहता है। डीएनए की तर्ज पर इससे उत्पत्ति स्थल की पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। - प्रो. व्यंकटेश सिंह, भौतिकी विज्ञान विभाग-बीएचयू

सीधी रेखा में चलता है यह कण

- सूर्य की ऊर्जा का 90 फीसद न्यूट्रिनो है
- सूर्य के कोर (केंद्र) से सतह तक आने में फोटान (प्रकाश ऊर्जा) को करीब एक लाख वर्ष का समय लगता है
- न्यूट्रिनो यह दूरी मात्र 2.3 सेकंड में तय कर लेता है
- यह रास्ते में पड़ने वाले धातुओं के भीतर से बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधा गुजरता है
- इस पर आधारित तकनीक से टेलीफोन से कई गुना ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है